Rural World

AN IDEA FOR A PROSPEROUS RURAL INDIA

Quarterly / ₹100
November 2023-January 2024

AGENDA FOR RURAL INDIA | ग्रामीण भारत का एजेंडा

रूरल वर्ल्ड

समृद्ध ग्रामीण भारत की सोच

ruralworld.co.in
www.ruralvoice.in
eng.ruralvoice.in

@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein

125 Years of Bayer in India

Health for All
Hunger for None

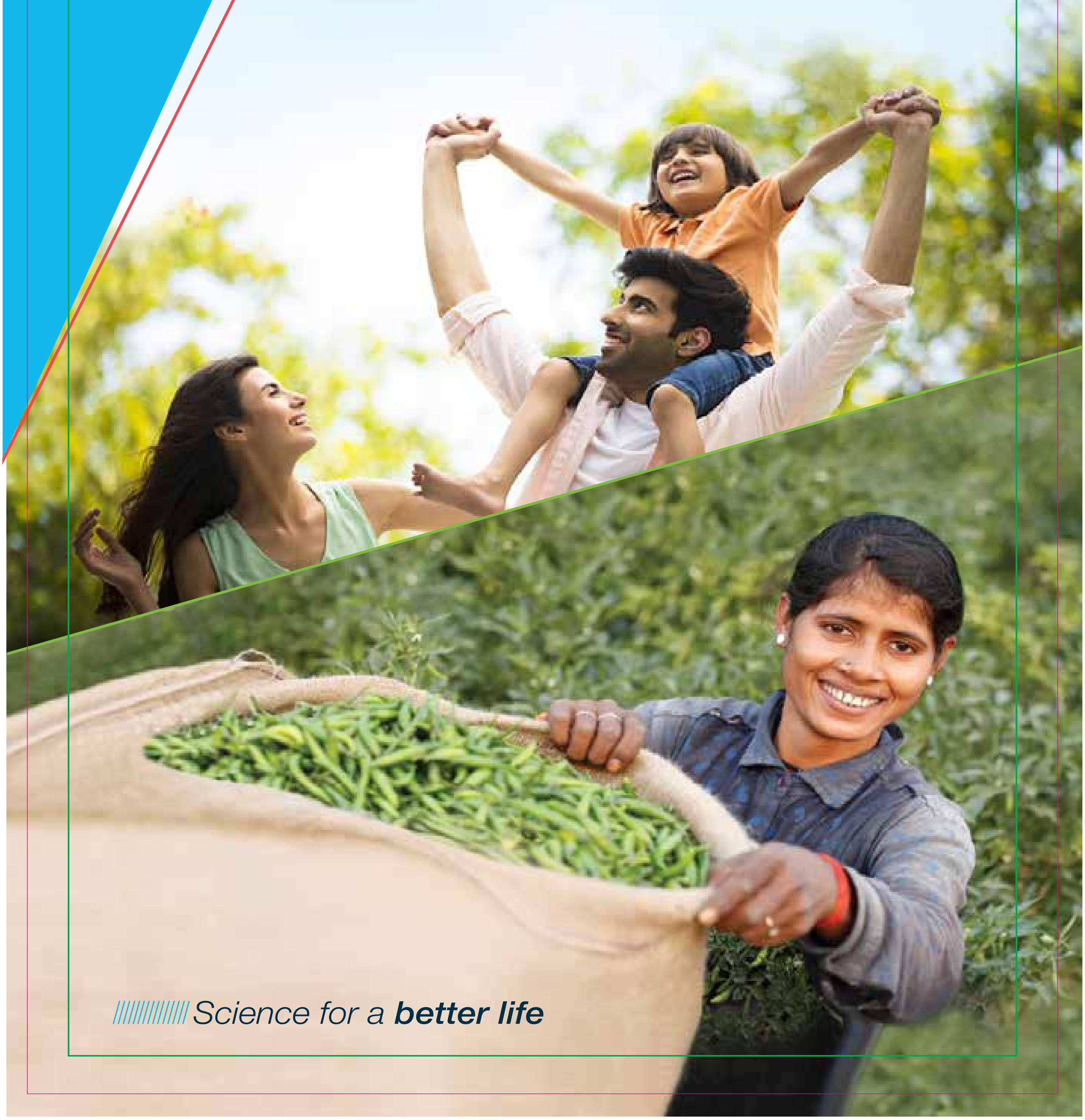

Science for a **better life**

Harvir Singh
Editor-in-Chief

Rural World: An Idea For The Prosperity Of Rural India

Three years ago, we started Rural Voice as a new vision for agriculture and rural India. Mahatma Gandhi had said that India resides in villages, and the former Prime Minister Chaudhary Charan Singh went a step ahead by noting that the path to the country's prosperity passes through its villages. Riding on the wave of economic liberalization, India is moving towards becoming a five trillion-dollar economy, but in the ups and downs of this wave of economic progress, the villages and rural population are being left behind. Various statistics and surveys confirm that rural India, more so agriculture, has lagged far behind urban India and other sectors of the economy. This gap is increasing in every aspect of life. The launch of 'Rural World' is a continuation of the mission on how to reduce this gap. Rural World is a new addition to the journey of media venture Rural Voice Media Pvt. Ltd. The experienced team of Rural Voice includes experts in agriculture and rural economy, science and technology, policymaking, agri-business and trade. Through Rural Voice, we have been seeking to bring rural India and agriculture closer to other sectors through the power of news, information and information system to improve the economic and social life of villages and farmers.

In this inaugural issue of Rural World, Professor Ramesh Chand, a member of NITI Aayog and a renowned agricultural economist and policy expert, has argued that in developed nations, there is a need to reduce the burden on agriculture by taking people dependent on it into manufacturing and service sectors. The formula has been successful. But now this formula is failing because even the double-digit growth rate of those sectors has failed to generate better employment opportunities. As far as India is concerned, the latest periodic labour force survey data for 2022-23 shows that 45.8 percent of the country' working people are still engaged in agriculture and allied sectors. In such a situation, a new formula will have to be found for India. The path to India becoming a developed nation will have be through the policy of agriculture-centric economy, but this path is not easy. It requires a new policy imagination.

Rural Voice, together with Socratus, conducted a six-month long field investigation to understand the problems and issues of rural India through the eyes of its citizens. What, in their view, are the options for a better life and livelihood? There could not have been a better subject for the cover story of the inaugural issue of Rural World. Through our field visits over six months, we sought to delve deep into the life and aspirations of rural residents in 60 districts of five states with different economic-social and agro-climatic conditions. For us, Rural World is not just a new media product; it is an idea of a prosperous rural India. An idea of how agriculture can be a lead sector and growth driver of the economy that would help bridge the gap between Bharat and India. Rural World aims to enrich its readers with information, news and analysis. Rural World will also work as a bridge between technology and its adoption on the ground market and agriculture and rural India. As purveyors of information, our work will complement the efforts of government agriculture departments, agri-entrepreneurs, corporates and cooperatives. The support and goodwill that Rural Voice received in the last three years has given us the courage for embarking on this new venture. The journey of Rural World is starting with the positive thought that agriculture and rural India will be equal partners in achieving the goal of a developed and new India.

Finally, I would like to say something on the selection of the language for Rural World. We have decided to publish Rural World as a bilingual magazine both in Hindi and English. The reason for this is to make this magazine accessible to readers in all parts of the country. At the same time, due to the way the entire world has become connected like a link due to globalization and digitalization, it is necessary for the rural world to reach out at the global level. I hope that this effort of ours will be successful in making its place among the readers and all the stakeholders.

@harvirpanwar

CONTENTS

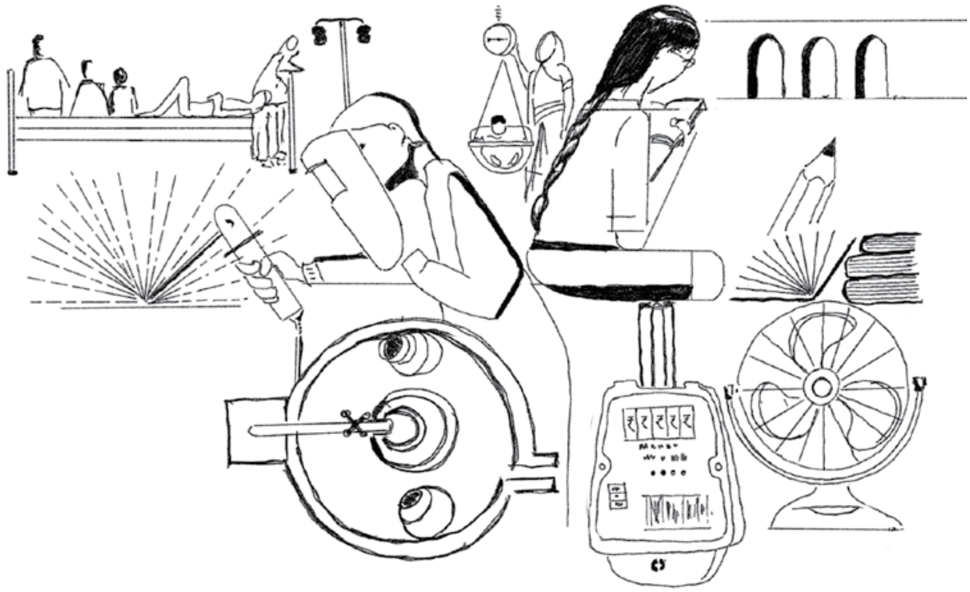

Cover Story

06 Agenda For Rural India
An initiative by Rural Voice & Socratus: The growing difference between Rural & Urban and aspirations of farmers & rural people

20 T Nandakumar
Ways to fulfil the aspirations of Rural India

22 Interview
Prof. Ramesh Chand, Member, NITI Aayog

28 Opinion: RS Paroda
On bringing back youth to agriculture

32 Opinion: Dr. Biswajit Dhar
The structural constraints of Indian agricultural

कवर स्टोरी

42 ग्रामीण भारत का एजेंडा
रूरल वॉयस और सॉक्रेटस की पहल: गांव और शहर का बढ़ता अंतर तथा किसानों और ग्राम वासियों की आकांक्षाएं

54 टी. नंदकुमार
ग्रामीण भारत की आकांक्षाएं पूरी करने के रास्ते

56 इंटरव्यू: प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग
कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने को राज्य आगे आएं

62 आर.एस. परोदा
युवाओं को कृषि की ओर दोबारा कैसे लाएं

Volume.-I Number-1
Quarterly (1 November 2023 -31 January 2024)

Editor
Harvir Singh

Printed and Published by Harvir Singh on behalf of Rural Voice Media Pvt. Ltd. Editor: Harvir Singh, Printed at Multicolour Services Shed No. 92, DSIDC, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi 110020 and Published from 11-A, Skylark Apartment, DDA SFS Flats, Site-2, Ghazipur, Delhi-110096
Website: ruralworld.co.in
Email: contact@ruralvoice.in

Published for the Quarter; 01 November, 2023 - 31 January, 2024, Released on 01 November, 2023, Total Number of pages 68 including covers

COVER DESIGN
Alok Shrivastava, Socratus

GRAPHICS
Nithin Vemula, Socratus

DISCLAIMER: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmited in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

हरवीर सिंह
एडिटर-इन-चीफ

ग्रामीण भारत की समृद्धि का विचार है रूरल वर्ल्ड

तीन साल पहले कृषि और ग्रामीण भारत के लिए नई सोच के रूप में हमने रूरल वॉयस की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। आर्थिक उदारीकरण की लहर पर सवार भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आर्थिक तरक्की की इस लहर के उतार-चढ़ाव में गांव और ग्रामीण आबादी कहीं पीछे छूटती जा रही है। तमाम आंकड़े और सर्वेक्षण इस बात की तस्दीक करते हैं कि ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र शहरी भारत और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों से कहीं पीछे छूट गया है। यह अंतर जीवन के हर पहलू में बढ़ रहा है। यह अंतर कैसे कम हो, इसी विचार को आगे बढ़ाने का क्रम है 'रूरल वर्ल्ड' का आरंभ। रूरल वर्ल्ड, मीडिया वेंचर रूरल वॉयस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की यात्रा में एक नई कड़ी है। रूरल वॉयस की अनुभवी टीम में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, नीतिगत मामलों के एक्सपर्ट, छोटे गांव और कस्बों की मंडियों से लेकर ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ तीन साल से जुड़े हुए हैं। रूरल वॉयस के माध्यम से ये गांव और किसान के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए खबरों, सूचनाओं और सूचना तंत्र की ताकत के जरिये ग्रामीण भारत और कृषि को दूसरे क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं।

रूरल वर्ल्ड के प्रवेशांक में नीति आयोग के सदस्य और देश-दुनिया के प्रतिष्ठित कृषि अर्थविद व नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चंद ने स्वयं तर्क दिया है कि विकसित राष्ट्रों में कृषि पर निर्भर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में ले जाकर इस पर बोझ कम करने का फॉर्मूला कामयाब रहा है। लेकिन अब यह फॉर्मूला नाकाम है क्योंकि उन क्षेत्रों की दो अंकों की वृद्धि दर भी रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने में नाकाम है। ताजा आंकड़े कहते हैं कि भारत में कामकाजी लोगों का 45.8 फीसदी अब भी कृषि और सहयोगी क्षेत्र में काम करता है। ऐसे में भारत के लिए नया फॉर्मूला तलाशना होगा। भारत के विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था की नीति ही होगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है।

रूरल वॉयस और साक्रेटस ने छह माह की जमीनी पड़ताल में यह जानने की कोशिश की, कि ग्रामीण नागरिकों की नजर में ग्रामीण भारत की समस्याएं और मुद्दे क्या हैं। उनके नजरिये में बेहतर जीवन और जीवन यापन के क्या विकल्प हैं और ग्रामीण भारत की आकांक्षाएं क्या हैं। रूरल वर्ल्ड के प्रवेशांक की कवर स्टोरी के लिए इससे सटीक विषय नहीं हो सकता था। दोनों संस्थानों की टीम ने छह माह की इस प्रक्रिया के जरिये देश के पांच अलग-अलग राज्यों, जिनकी आर्थिक-सामाजिक और एग्रो क्लाइमेटिक परिस्थिति अलग है, के 60 जिलों के ग्रामीण नागरिकों के माध्यम से ग्रामीण भारत का एजेंडा और आकांक्षाएं जानने की कोशिश की और उसे हम अपने इस प्रवेशांक के माध्यम से अपने पाठकों और देश के सामने रख रहे हैं। रूरल वर्ल्ड केवल एक नया मीडिया प्रॉडक्ट नहीं है, यह एक विचार है समृद्ध ग्रामीण भारत का, कृषि और किसान की आर्थिक तरक्की का वाहक बनने का, भारत और इंडिया के बीच के अंतर को पाटने का। अभी तक जो बेहतर हासिल हुआ उसको साथ लेकर मजबूत भविष्य के नये भारत की राह को सुगम बनाने का विचार है रूरल वर्ल्ड। इसके जरिये पाठकों को सूचनाओं, खबरों और विश्लेषण के जरिये समृद्ध करना मूल मंत्र है। टेक्नोलॉजी और बाजार तथा कृषि व ग्रामीण भारत के बीच एक पुल के रूप में भी रूरल वर्ल्ड काम करेगा, जिसमें सरकार, कॉरपोरेट, सहकारिता और उद्यमिता के तमाम विकल्प एक साथ चलेंगे। यही भविष्य भी है। पिछले तीन साल में रूरल वॉयस को सभी वर्गों से जो सहयोग और समर्थन मिला है, उसी ने हमें इस नये वेंचर के लिए साहस दिया। इस सकारात्मक सोच के साथ रूरल वर्ल्ड की यात्रा शुरू हो रही है कि कृषि और ग्रामीण भारत एक विकसित और नये भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बराबर का भागीदार होगा।

यहां एक बात रूरल वर्ल्ड की भाषा के चयन को लेकर भी मैं कहना चाहूंगा। हमने रूरल वर्ल्ड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिपोर्ट एवं आलेख प्रकाशित करने का फैसला लिया है। इसकी वजह जहां देश के सभी हिस्सों के पाठकों के बीच इस पत्रिका की पहुंच बनाना है, वहीं जिस तरह से ग्लोबलाजेशन और डिजिटाइजेशन के चलते पूरा विश्व एक कड़ी की तरह जुड़ गया है उसके चलते रूरल वर्ल्ड की पहुंच भी वैश्विक स्तर पर होनी जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास पाठकों और सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा।

@harvirpanwar

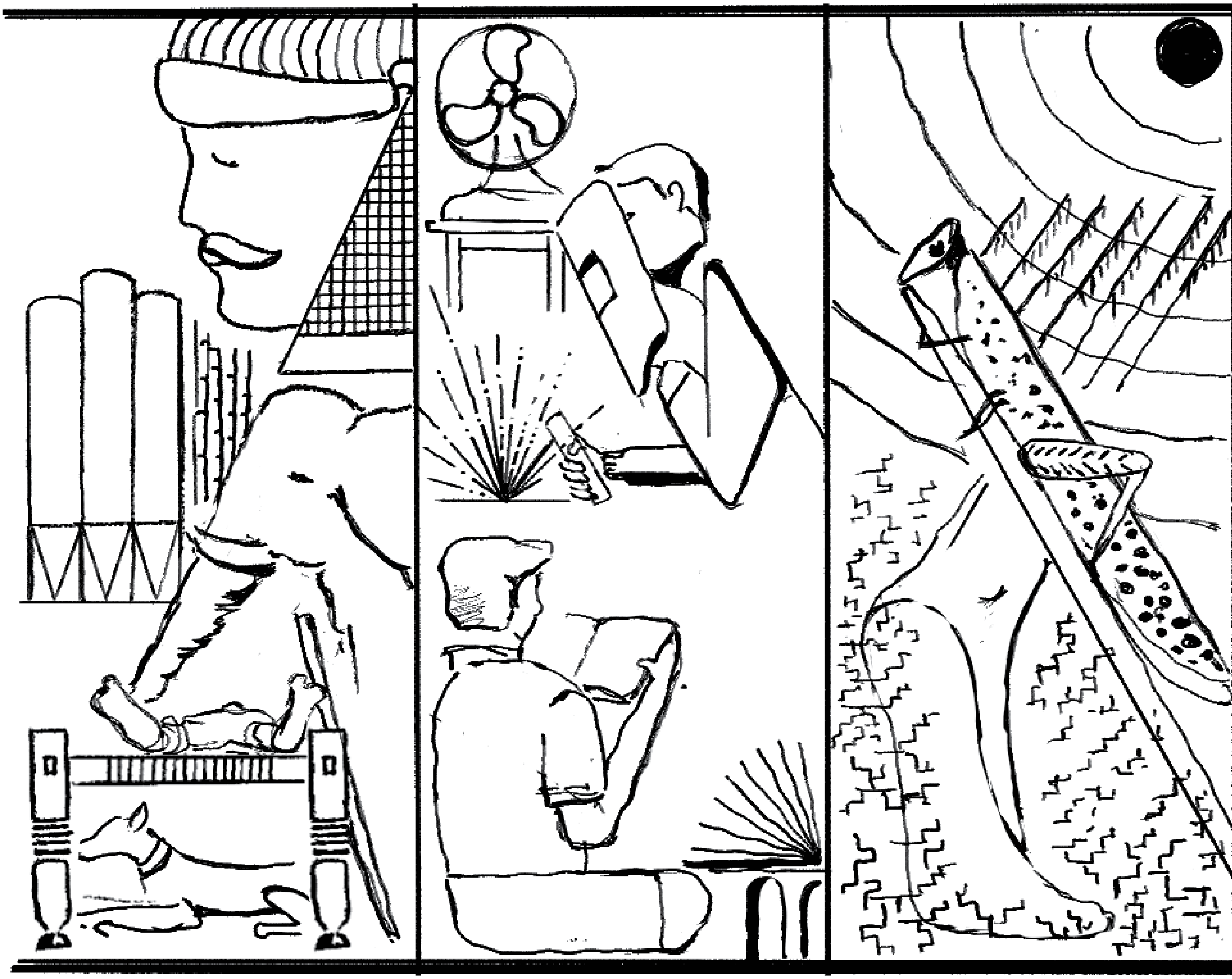

AGRICULTURE NEEDS HAND HOLDING

Existential Crisis For Rural India

All Illustrations: Alok Shrivastava, Socratus

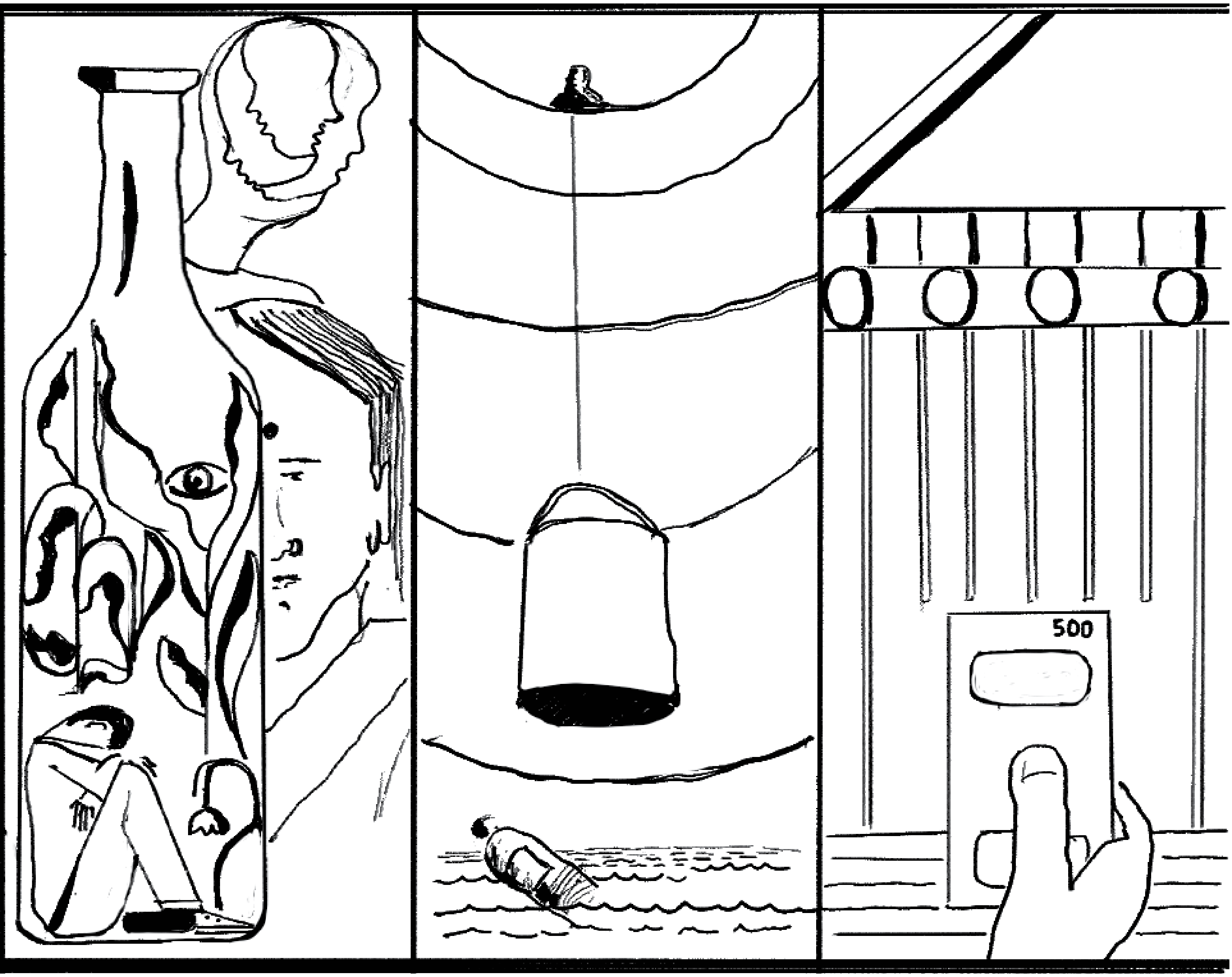

Harvir Singh | Prachur Goel

Indian agriculture faces an existential crisis with the entire rural landscape in the grip of societal and environmental challenges despite, a visible improvement in infrastructure like roads, sanitation and mobile phones. You might ask: Is it a paradox of sorts then ? The answer is 'Yes' and based on a six-month-long direct interaction with the critical stakeholders like farmers' organisations, civil society, policy makers and market intermediaries not in New Delhi or metropolitan cities but in the states bottom up to smaller towns in five states with a wide diversity in agri-climate, economic strength, and crop patterns.

Our findings after this comprehensive interaction, converted into measurable data , would give you an impression about the state of agriculture which may not be in conflict with an assessment of a bureaucrat in New Delhi or a state capital but is a holistic view of the rural landscape that needs effective policy intervention and political support right now than later.

If you talk to senior government officials in New Delhi, they would tell you there has been a significant progress in terms of new roads built, electricity connections or the houses and toilets constructed. They might highlight how mobile phones have become common in rural areas and how there is a growing market

Participants of Agenda for Rural India convening in Muzaffarnagar.

for all sorts of products and services.

Indeed, rural India has seen many changes. Things like infrastructure (roads, electricity connection) and access to various services have definitely gotten better thanks to different schemes of the Centre and the state governments. But these visible physical infrastructure facilities lead to rising aspirations of those living in villages and small towns to be at par with those in cities even as the pureplay agriculture, the core, is at risk of being left on its own. By the way, the aspirations of rural India are quite reasonable and doable, provided there is a political will and the menace of corruption is dealt with effectively.

Risks to the core of rural India, that is agriculture, as highlighted in our cross-country interaction include high level of debts, unabated rise in input costs including increasing labour wage , indiscriminate sale of spurious pesticides , perilous risks of climate change and wild gyrations in prices of the harvest, coupled with a political apathy.

"Plastic mukt, paryavaran yukt, nasha mukt, wifi yukt. Parivahan suvidha sahit, pradushan rahit, 24 ghante bijlee aur ek stadium ho jismein ladke, ladkiyan, mahilayen roz daude. Adhunik shiksha aur swasthya ho aur krishi sambadhi jaankari vigyaan ke aadhar par mile."

"Humare gaon hare bhare ho, jalstrot pariyapt ho aur shudh ho. Saaf suthre gaon ho, plastic mukt ho. Vidyalayon mein ladke, ladkiyon ki sankhya khub badi ho, khaas kar sarkari sansthaon mein."

This is what we heard when we asked people from Balotra, Barmer, Jaisalmer, Sikar, Nagaur and other districts of Rajasthan, who were gathered in Jodhpur, "2030 me aapka gaon ka sapna kya hai?".

People in rural India have a dream – they want their villages to have the same facilities as cities. They hope for better education, healthcare, roads, electricity, and other things that make life comfortable and convenient, just like what people in cities have, at least some of them. If they have all these things, they believe they could live much better lives.

The rural idyll of a peaceful, pollution-free village where everyone had work to do is far from reality. Rural life has changed, and it's not what it used to be. Many rural areas still lack basic facilities like reliable electricity, good roads, clean water, quality education, and healthcare. People are struggling, and farming is no longer a viable occupation for many – neither in terms of income nor social status. Moreover, rural inhabitants are facing new problems like climate change, pollution, lifestyle diseases, unemployment, and drug issues. These are problems that used to be thought of as city problems, not rural ones.

When **Rural Voice**, a sister publication of **Rural World** and **Socratus,** a non-profit organization, decided to embark on a first-of-its-kind pan-India convening series with citizens from rural India in order to hear their challenges and aspirations, it was driven by two main motivations. One, rural areas are often marginalized in mainstream discourse. In the news, rural areas are hardly present in the

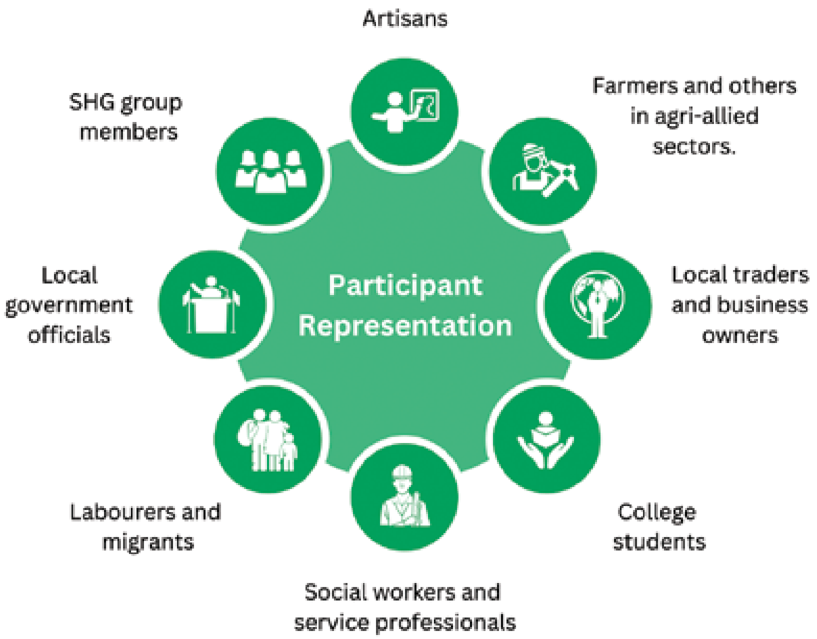

graphics: Nithin Vemula, Socratus

No More Blue Skies: Rural India's Pollution & Climate Battle

Adrija Chaudhuri, Socratus

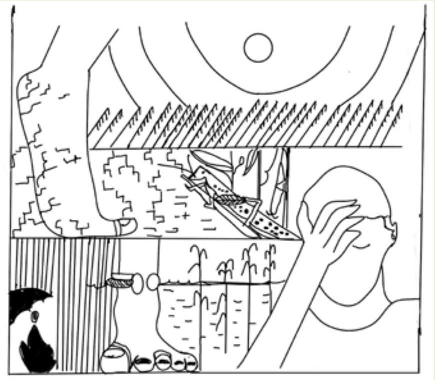

Our conversations with rural citizens from different ecological regions of the country confirmed our worst fear: that climate change is already here and rural communities are at the frontiers of it. As most of our participants were involved in agriculture and allied sectors, they spoke extensively of the damage caused to crops by climate change. In UP, farmers told us how unusually high summer temperatures had affected the mango and sugarcane crops. Unseasonal rainfall in March had also flattened much of the ripening wheat crop. In Rajasthan, where crops were dependent on rainfall in many regions, farmers could not effectively plan their crops due to the increasingly irregular rains. In Odisha, participants watched with dismay as unusually heavy rainfall lashed their crops and washed away the topsoil, causing soil erosion. The lack of timely rains was also an issue. As a tenant farmer and labour migrant from Balangir district told us: *"Jehetu sei borsho barsa helani, tarporo jeto dhano thila shobu noshto hoye gela [It was my bad luck that that very year (where he leased land for farming) it did not rain and my rice crop got destroyed]."* Coastal communities in Odisha were also affected by the rise in sea levels caused by global warming. Farmers in Meghalaya were also affected by heavy rainfall causing soil erosion, despite their best efforts to practice terrace farming, bunding and planting border crops. They believed human actions such as limestone quarrying and deforestation had worsened this problem.

And then there were the pests. The irregular rains and erratic weather were causing pest infestations at unpredictable times. In UP and Rajasthan, crops like mango, wheat moong and sugarcane were being affected by pests at odd times of the year. In Meghalaya particularly, women farmers were aggrieved by the wide variety of pests that were affecting their maize, vegetable and fruit crops.

Many participants saw natural farming as a solution to this crisis, and hoped that the government would take a more proactive role in promoting sustainable agriculture. They also felt effective crop insurance would help reduce the risk that they bore in the era of climate change.

Interacting with our participants also disproved the common misconception that environmental pollution was primarily an urban problem. In Muzaffarnagar, rural citizens complained of industrial pollution of water bodies, from the sugar mills nearby. This along with chemical residues on food was believed to be causing increased incidence of cancer and heart attacks in rural areas. There was a general perception that the overall quality of life in rural areas had declined due to pollution of air, water and land. As a resident of Muzaffarnagar put it: "People's lives are valuable, even if we get good yields and good prices for our crops, will we end up dying after eating them?" This was echoed in Jodhpur, where our participants linked the rising cases of cancer in rural areas to the overuse of chemicals in agriculture. Rural citizens in Tamil Nadu told us how industries were dumping waste in water bodies and groundwater was being contaminated through leaching, leading to more diseases in rural areas.

Our participants were not just aware of environmental issues, they also knew exactly what they wanted to hear from electoral candidates in terms of action to be taken. In Coimbatore, they called for a more effective pollution control board, rainwater harvesting and water conservation plants, and the creation of 'food forests' in every village. In Bhubaneswar, they felt raising awareness, reducing plastic waste and promoting solar energy were most important. In Muzaffarnagar, they proposed planting trees on panchayat land and conserving village lakes, forests and commons. Rural citizens everywhere were as aware and well-informed as their urban counterparts. As their everyday lives were far more dependent on the environment, they felt the impacts of environmental pollution and climate change more keenly. With minimal support, they were willing to implement measures to protect and conserve their surroundings.

national imagination apart from stories surrounding farmer suicides, adulterated alcohol or debates on the mid-day meal scheme. In a country where more than half of its population is rooted in rural areas, this is an incredible mismatch in representation. The second reason pertains to the dramatic changes that have happened in the last 15 years across the rural landscape with the penetration of the internet and better infrastructure. Through these convenings, **Socratus** and **Rural Voice** aimed to capture the current state of mind of rural India as well as generate a conversation around the issues raised. This article aims to honestly reflect the views and feelings of the people we talked to about their lives, problems, hopes, and dreams for a brighter future.

Our work covers people from 5 states of India, in an attempt to represent the diversity in the 5 regions: the north, south, east, west and north-east. We bring particular attention to our work in the north-east. Given its sparse population, distinct cultural diversity and

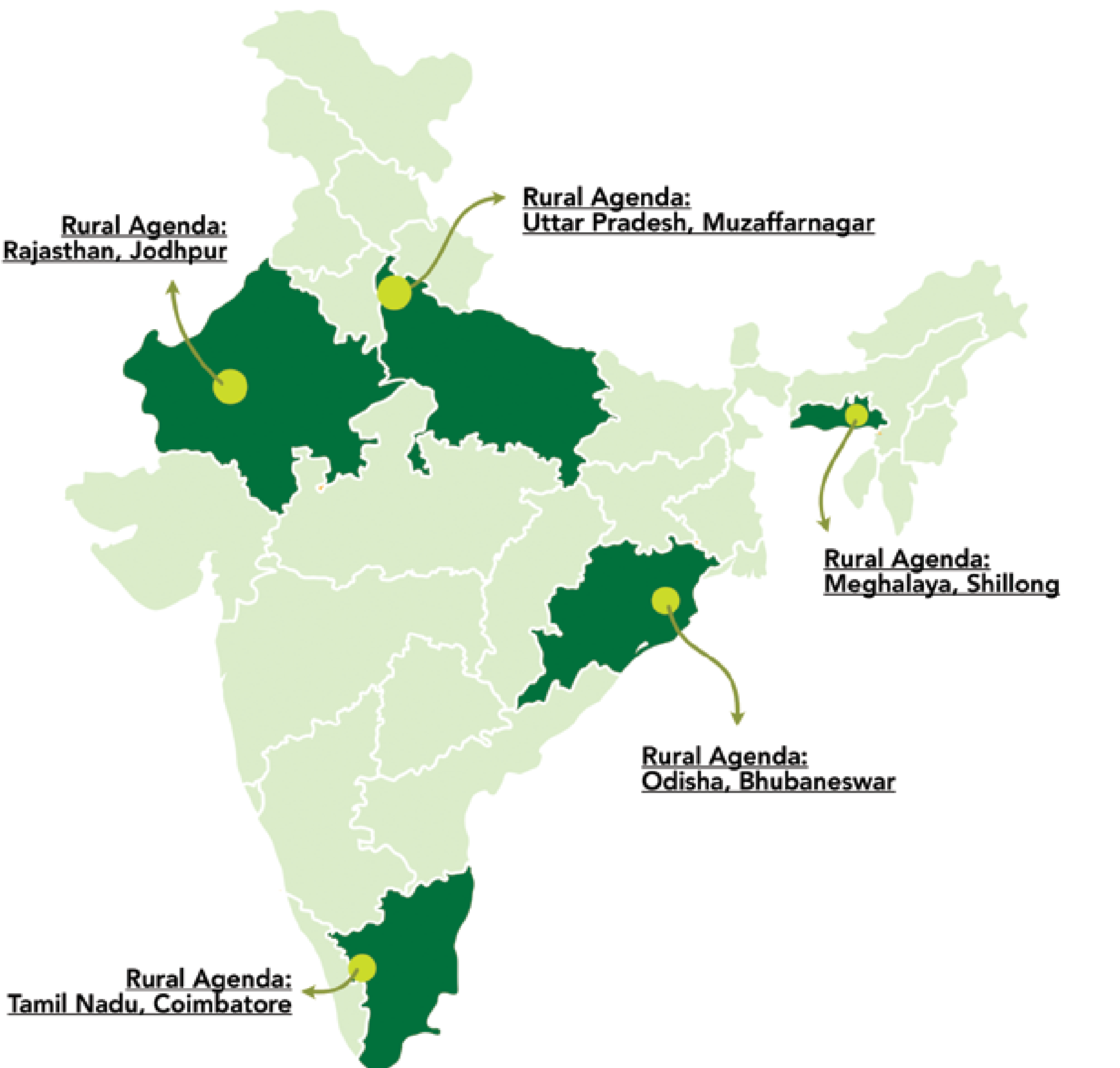

graphics: Nithin Vemula, Socratus

remoteness, it is often excluded in national dialogues. However, keep in mind that India is vast and diverse, so we couldn't include every region or person's perspective. We picked five states from each region of India, and in each state we partnered with a local organization that helped us bring the diverse rural citizens together to ensure a wide representation of the local population. We tried to recreate the same setting in all five states while being sensitive to the needs of the participants in each location.

We had our convenings in 5 locations.

graphics: Nithin Vemula, Socratus

At each location, we had a convening with people from 10–11 nearby districts. These locations were Bhubaneswar (Odisha), Coimbatore (Tamil Nadu), Jodhpur (Rajasthan), Muzaffarnagar (Uttar Pradesh) and Shillong (Meghalaya). These states are culturally, economically, agro-climatically, and politically different.

Our local partners were Livelihood Alternatives in Odisha; TNFPA (Tamil Nadu Farmers Protection Association) and FMIF (Farmers Merchants Industrialists Federation) in Tamil Nadu; South Asia Biotechnology Centre in Rajasthan; farmer leaders Umesh Panwar, Narendra Pal Verma and Dharmendra Malik in Uttar Pradesh; and NESFAS (North East Society For Agroecology Support) in Meghalaya. With their help, we were able to bring together more than 300 participants from 60 districts.

graphics: Nithin Vemula, Socratus

Uttar Pradesh

Highlights

- Stray Cattle
- Overuse of fertilisers
- Effect of climate change on crops

Participant Representation

Baghpat, Bijnor, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli

Rajasthan

Highlights

- Overuse of fertilisers and pesticides,
- Lack of water facilities for drinking and irrigation,
- High unemployment

Participant Representation

Balotra, Barmer, Falodi, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Nagaur, Newra, Pali, Sanchore, Sikar, Udaipur

Odisha

Highlights

- Farmer-animal conflict,
- lack of water facilities for drinking and irrigation,
- Lack of good crop prices

Participant Representation

Angul, Balangir, Baleswar, Bhubaneswar, Cuttack, Deograh, Dhenkanal, Gajapati, Ganjan, Jagatsinghpur, Jaipur, Kandhamal,

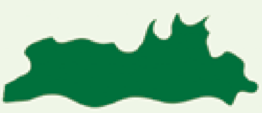

Meghalaya

Highlights

- Lack of good road connectivity,
- Effect of climate change on crops,
- Poor Healthcare,
- Poor Infrastructure

Participant Representation

East Garo Hills, East Jaintia Hills, East Khasi Hills, Eastern west Khasi Hills, Ri Bhoi, West Garo Hills, West Jaintia Hills, South Khasi

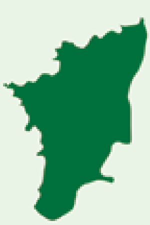

Tamil Nadu

Highlights

- Farmer-animal conflict,
- corruption,
- Lack of crop insurance for farmers,
- Degradation of water resources (lakes, rivers, dams)

Participant Representation

Coimbatore, Dharmapuri Dindigul, Erode, Namakkal, Nilgiris, Salem, Thirunelveli, Tiruppur

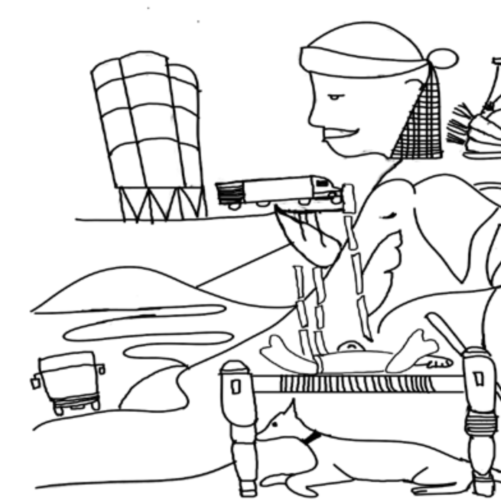

Agriculture: Difficult Harvests

Adrija Chaudhuri, Socratus

No discussion on rural India would be complete without a conversation on agriculture. In our convenings with rural citizens across the country, around 60% of our participants were farmers, by which we mean they were involved in agricultural activities for their livelihood. The reality of the agrarian crisis plaguing rural communities for the past two decades was painfully evident in the worries, hopes and dreams of our participants. While most of the issues they raised were not new, it was illuminating to understand the perceptions and priorities of the farmers themselves.

Everywhere we went, farmers told us that it was becoming almost impossible to sustain themselves through agriculture alone. Crop prices were simply unable to keep up with the costs of farm inputs. As a young farmer from Western UP told us: "Aur sab itni costly hote ja rahi hai bohot zyada.....har tarah se pressurise kar diya hai" [Everything is becoming so costly, including fertilizers and pesticides, that we are being pressured from all sides] In Muzaffarnagar, part of the "sugarcane belt" of North India, the stagnation of the SAP (State Advised Price) and delay in payments from the sugar mills were common problems. Farmers here also complained of the rising cost of basic necessities and farm inputs, including pesticides, fertilizers, seeds and labour. Even in this relatively prosperous agrarian belt, farmers were being forced to take loans to continue farming. It was telling that no farmer wanted their children to become farmers and there were hardly any takers from the younger generation as well.

In Odisha, farmers felt that crop prices were hardly remunerative and that the root causes of poor price realization were the difficulties in accessing markets and the lack of market infrastructure. As a farmer from Kendrapara district said: "The main reason for the poor price received by farmers was the lack of storage facilities like warehouses and cold storages." Most farmers were forced to sell their produce directly at the farm gate to local traders and middlemen. This happened due to poor transportation facilities and the lack of warehouses and cold storages in which to store their produce. In the very different arid agroecological zone of Rajasthan, farmers raised similar issues of the lack of storage facilities and marketing opportunities. They told us how crop prices were unable to keep up with the rising costs of farm inputs such as seeds, fertilizers and pesticides, which ended up squeezing their profits. In Shillong too, we heard the same story: poor price realization due to inferior road connectivity, lack of storage facilities and delayed payments. In Coimbatore, farmers felt that the MSP (Minimum Support Price) was too low and that it should be decided by the farmers themselves. They suggested that MSP should be extended to crops commonly grown in Tamil Nadu, such as tea, coffee, vegetables, millets and spices.

In many of our events, there was also a perception that the MSP and good prices alone could not address the issue of decreasing viability of agriculture. Farmers everywhere voiced their

People from different occupations participated in the convening. There were artisans, local traders and business owners, SHG group members, local elected officials, local government officials, labourers and migrants, college students, social workers, and service professionals. Care was also taken to ensure that people across gender and social groups were in attendance.

Design of the convenings

Group deliberation and negotiation

The format of the convenings was similar in all the regions. It included both group discussions and individual voting. To start, we had everyone introduce themselves to make everyone more comfortable. Then, we divided the participants into different groups with a mix of people. Each group talked among themselves and picked out the five biggest problems in their community. Afterward, each group shared these issues with everyone in the room.

The idea behind this approach was to encourage the participants to express their thoughts and feelings. We wanted to create a space where people could have discussions and come to an agreement on the most important ideas. Following this, the groups discussed hopes they had for their villages. Groups also figured out the top five things they wanted their candidates to promise in an election.

The important process here was that participants discussed their problems with others and then decided together which issues were most crucial. This way, they had to talk and negotiate with people who had different perspectives, and they worked together to find common ground. Our role as facilitators was to help this process happen without trying to influence what the participants

expectations that governments would secure their incomes under schemes such as PM-KISAN. They also suggested that value-added products and local industries in agriculture should be actively supported and encouraged by governments. Farmers felt the capacities of collective organizations such as FPOs and cooperatives should be enhanced to take on this responsibility. In all our convenings, we also heard that landowning farmers were unable to source labour for their fields, and that they were increasingly relying on migrant labour for cultivating their farms. They suggested that agricultural work should be provided under MGNREGA, and that the wages could be jointly paid by the farmers and the government, thereby also ensuring a higher wage rate.

This brings us to the matter of government schemes on agriculture. The lack of awareness about such schemes, due to which they were not reaching those who were in need, seemed to crop up in every location. This was felt strongly by our participants from Rajasthan, who suggested that information about government schemes should be displayed outside all government offices. In Meghalaya, farmers felt that they should have better information on and access to government schemes on agriculture. In Odisha, participants were dismayed at the delayed or lack of implementation of government schemes such as MGNREGA. Another issue that came up with striking regularity was the overuse of chemical fertilizers and pesticides. While this is a widely accepted problem amongst agricultural scientists and experts, it was interesting to note that the level of awareness among farmers regarding this issue was also quite high. In Odisha, farmers told us that these harmful chemicals were leaching into and polluting water sources as well, including groundwater. In Rajasthan, we heard the concern in their voices about how excessive chemical use was causing cancer and other diseases in rural areas. They felt trapped in systems that encouraged the overuse of chemicals. Farmers also prioritized a concern that does not figure prominently in the discourse on agriculture: human–animal conflict. In UP, farmers were afraid to even plant crops due to the stray cattle menace. In fact, it was the issue that resonated the most among our participants in Muzaffarnagar. Farmers suggested several solutions, ranging from using government funds to build cattle shelters in every village to a monthly payment for farmers to care for their old cattle, to legalizing the cattle trade. In Odisha, Tamil Nadu and Meghalaya, wild animals from the forested areas nearby often entered their fields, destroying crops and endangering the safety of the farmers themselves. As a farmer from Coimbatore district told us: "In the division along the western ghats, from Tenkasi to Satyamangalam forest division, millet crops can't be grown due to deer nuisance, pig nuisance and peacock nuisance". A farmer from the Nilgiris foothills even carried a photo album documenting the damage in his area. The farmers believed that ill-conceived government conservation schemes were to blame for this rise in human–animal conflict.

We cannot close this section without mentioning an issue that is vital to agriculture: water. Water for irrigation was a concern everywhere, but especially in Odisha and Rajasthan, two contrasting agroecological regions. In Rajasthan, the declining quality of groundwater due to overuse of chemicals made good irrigation facilities vital to the future of farming.

said in any way.

In a democracy, people turn their opinions into political choices by voting. In India, how someone votes is influenced by their own thoughts and also by the views of the community they belong to.

As a part of our last activity, we asked the participants to tell us about the most important issues that would affect their vote in both state and national elections. This was something they did on their own. In the past, we've noticed that Indian voters sometimes choose different parties between the state and national elections. We wanted to see if this pattern still held true.

Participants of Agenda for Rural India convening in Bhubaneswar.

Farming faces existential economic, social and environmental crisis

"Kisan to khush-haal hai hi nahin. Hundred percent kisan, karzdaar hua baitha."

Costs of living have gone up and in the absence of commensurate increase in income from agriculture, farmers end up accumulating substantial debt.

The costs of inputs have gone up – from seeds to labour, fuel to pesticides. All of them now need to be bought from

Rural India still awaits basic infrastructure and services

Jonathan Donald Syiemlieh,
Socratus

The extensive discussions and insights gleaned from the five regional convenings, which collectively laid the foundation for framing the Agenda for Rural India, have prominently stated the need for bolstering and enhancing rural infrastructure. This critical imperative extends to various sectors, including health and education, transportation and energy accessibility. The following are the findings related to challenges regarding lack of infrastructure in rural areas.

Rural Road Connectivity

More than one-fourth of the participants during the polling stressed the importance of improving road networks, footpaths, streetlights, and drainage systems throughout rural areas in Meghalaya. In both Meghalaya and Uttar Pradesh (UP), the consensus that emerged during the polling exercise highlighted a shared demand for the enhancement of high-quality road infrastructure, especially to connect farms and streamline transportation to and from agricultural markets (mandis).

Health Infrastructure

The state of healthcare in rural India has a direct impact on the lives and livelihoods of millions of rural residents. In both Uttar Pradesh and Meghalaya, participants voiced their concerns about the inadequacy of health infrastructure, including non-functional Primary Health Centers (PHCs) and Community Health Centers (CHCs).

A significant number of participants in Uttar Pradesh, Odisha, and Meghalaya expressed that they would choose their future leaders if the promises made regarding the fulfillment of well-equipped, affordable, and easily accessible healthcare facilities (including hospitals and PHCs) were upheld.

Education Infrastructure

The state of educational infrastructure in rural India directly influences access to quality education and, by extension, the socio-economic development of the country. Rural youth in Uttar Pradesh do not receive adequate skills and technical education as echoed by a social worker from Muzzafarnagar , and the quality of primary and higher education in rural regions of Odisha, Rajasthan, Meghalaya, and Uttar Pradesh is deteriorating.

A participant from East Khasi Hills, stated that 'there is a high dropout rate across primary to middle school' . Furthermore, there is insufficient

the market. In the case of fertilizers and pesticides, more is being applied every year. Farmers are unable to consistently fetch good and timely prices for their agricultural produce.

While costs have increased, the risks around farming have increased as well. Climate change is causing erratic weather including heat waves, rainfall, frost, pest attacks. Conversations around climate change have moved away from elite circles and are now a lived reality for everyone. It was discussed in great detail in every location. Human–animal conflict is increasingly manifesting itself and differently in different parts of the country. Stray cattle was the most critical issue in Uttar Pradesh, which has forced farmers to sleep in their fields. Animals are destroying crops in Odisha and in Rajasthan. Around Coimbatore, wild animal conflicts such as those with elephants are widespread and on the rise.

"Chemical ka atyadhik upyog sabse zyada barbaadi ka karan hai, gaon mein. Chemicals bahut zyada hai. Chahe woh zameen mein ho, janwaron mein ho, insaano mein ho. Har jagah chemical hi chemical hai."

Participants of Agenda for Rural India convening in Coimbatore.

We were in Muzaffarnagar, a city in western Uttar Pradesh (UP). Along with Punjab, this region is at the heart of the green revolution in India. However, in a place like Muzaffarngar, the fact that the farmers themselves are bringing up the issue of overuse indicates how unbalanced the use of fertilisers and pesticides has become.

"Nakli pesticide aa gayi hai – koi checking nahin hai."

"Dealer trade me lala log baithe hain jinko agriculture ka ABCD bhi nahin pata. Wo hume dawayian de rahen hain."

The critique of excessive chemical use was present everywhere we went. The narrative concerning natural ways of farming was surprisingly popular. Farmers are caught between the "natural" and "regular" farming narratives. Recurring and unexpected pest attacks need urgent attention for which solutions apart from using pesticides are not clear. The push for making farming sustainable and food healthy so that it works for both people and the planet is well and truly widespread, especially in Rajasthan and Odisha. In Muzaffarnagar and Coimbatore, farmers want to go

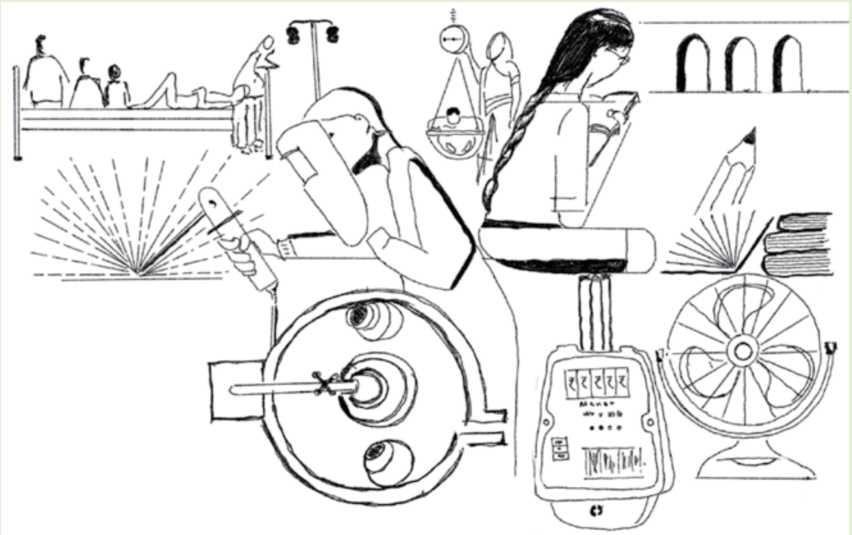

focus on imparting practical skills, such as those related to agriculture. The poll promises that garnered votes from attendees in Odisha primarily centered on promoting farmer's education through training programs. Alternatively, in Meghalaya, a substantial portion of participants expressed their preference for election promises related to education infrastructure and achieving uniformity in delivering high-quality education up to the collegiate level.

Energy Infrastructure

Residents of Meghalaya, Tamil Nadu and Odisha have conveyed that power cuts and load shedding have had adverse effects on their daily lives, emphasizing the necessity for the state government to implement measures to ensure uninterrupted 24-hour electricity supply. In Uttar Pradesh, increasing electricity tariffs was cited as a concern by a farmer from Baghpat district. The participants in Odisha had stated that they would vote for leaders who would help promote and turn to renewable energy sources, particularly solar power, to reduce their reliance on fossil fuels. The development of energy infrastructure in rural areas of India is a crucial step toward achieving balanced, inclusive, and sustainable growth.

Conclusion

The insights shared by local communities, farmers, teachers, artisans, and others have provided invaluable contributions in shaping a rural India infrastructure agenda. By channeling investments into essential areas such as healthcare, education, transportation, energy access, we not only address immediate needs but also set in motion a series of transformative changes that profoundly impact the welfare of rural communities.

more "natural" but are unsure whether it will work and the risk appears too big for many. Overall, suggested solutions ranged from banning spurious pesticides, regulating dealers, educating farmers about balanced use of artificial inputs to going completely organic or leaning towards natural soil supplements.

Difference in aspirations and reality fuels labour shortage, unemployment and drugs

"Agar Bihar ke mazdoor na aaye, to aap kheti nahin kar sakte. Humne khud karni chod di hai."

Be it Muzaffarnagar or Coimbatore, farmers everywhere complained that finding labour to work on the farms is a struggle. According to farmers, the wages for labour have become too high. And this is despite young people from the village not having any jobs. Young people would rather not do any work instead of labouring in the fields. As a result, land owners are dependent on migrant labour on many occasions.

"MGNREGA ko kheti mein jodkar nuyntam mazdoori sunischit ki jaye.

Jo sabse badi samasya hai humare rajnaitik tantra ki, woh hain 'freebies'."

The challenge of labour prompted a farmer from Baghpat to say that agricultural labour should be considered under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). As a result, the scheme would compensate for part of the labour cost. Another opinion among land-owning farmers across regions is that the so-called "freebies" must be stopped. It is making people dependent on "handouts" and affecting their intent and availability to work.

Kisan se aaj kal koi shaadi nahin karta. Bacche AC me baithna pasand karen.

The future of agriculture in India looks precarious not just because of the economic or environmental challenges mentioned, but because of a deep social challenge. Young people don't want to do farming. Farming is not aspirational anymore. Men who continue to farm are finding it difficult to find brides. Society sees it as a dead end – backbreaking, uncertain and unremunerative. The likelihood of being pushed into debt with a bad harvest are high.

As a result, young people, supported by their families, are completing higher levels of education. However, there are hardly any good jobs in villages except for the rare government ones. Non-farm employment opportunities such as manufacturing, services, or small-scale industries are scarce. The blame for this is attributed to many factors: limited quality education in rural areas, absence of vocational training and lack of credit and infrastructure to enable rural industries to grow. The end result: young men and women, full of ambition and

potential, are unemployed.

"Gaon nasha mukt hona chahiye, yeh sab ki prathmikta hai. Nasha nahi hona chahiye aur iske prati yuvaon mein jagrukta bahut zaroori hai."

In 2016, the Hindi movie Udta Punjab brought the drug epidemic in Punjab to popular imagination. In 2023, it appears that drug usage is now not just limited to urban elites and regions of Punjab. Be it in Bhubaneshwar or Jodhpur, we heard the same thing : a large number of youth are consuming drugs across all social groups. Alcohol has long been a major problem in rural areas. It continues to be as we heard in Meghalaya, Tamil Nadu and Odisha. However, widespread consumption of drugs across India seems to have escaped the notice of the mainstream media. In the absence of a deeper understanding, one can hypothesize about the various causes for this epidemic. Is it due to joblessness – dreams colliding with stark reality? Is it because of popular songs and media making it "cool" and acceptable? Or is it because drugs seem to be more easily available? Joblessness, lack of engaging social institutions, increased desirability and availability of drugs is now seem to be fueling a drugs epidemic across India.

Village infrastructure still unable to provide basic services

People are still waiting for good quality basic infrastructure. People from the Garo, Khasi and Jaintia tribes in Meghalaya still need good road connectivity to enable movement of goods and people. Road connectivity has improved but not enough. And if roads are there, public transport is unavailable. The same goes for electricity. Constant electricity supply throughout the day is still a dream for rural India. The need for constant connection to the internet is also a necessity now.

A farmer from Balotra (Rajasthan) is still in need of clean water for drinking, echoing the sentiments of people in the opposite corner of India, in Meghalaya, who also want tap connections. In Muzaffarnagar, farmers have water but are concerned about toxic chemicals and metals that have seeped into groundwater.

Participants of Agenda for Rural India convening in Jodhpur.

There is a deep sense of being left behind when it comes to education in villages. The growing gap between government and private schools is gnawing at people. People want excellent public education. Even if the schools are there, the number of teachers is not sufficient. The government schools are considered ill-equipped to provide "quality education" that can lead to good careers for young people.

The need for good health and healthcare is increasingly felt across locations. With increasing lifestyle diseases, people need better treatment. Multi-speciality hospitals are far away from villages. Local health infrastructure leaves a lot to be desired. PHCs and CHCs are not sufficient and are ill-equipped.

"Engal gramathil suttamana sutrupuruchural, podukalaivarigal, vilayattu maidanangal, tirumsaranda payarchivaguppu vayyangal vendum."

[In our village we want a clean environment, [...] places to rest, playgrounds, exercise facilities.]

The older generations in the villages are seeing society changing. They feel the communitarian feeling is slowly fading away. Younger generations are seen as being occupied with their phones and have become distant from their villages, and their families. With changing diets and lifestyle, obesity rates among young people are increasing.

With trees being cut down, because of often unplanned construction of roads and infrastructure, bringing with it an increase in vehicles and trash, traditional open spaces for public gatherings are not feasible options anymore. People don't gather under trees and discuss life and politics. There is a felt need for clean, public spaces for the community. Spaces where people can rest comfortably, gather, talk and where young people can play and exercise. A place to have fun in the presence of others. To revive the village, this may be the easiest and the most important space to create.

Corruption in electoral politics and administration

"Sabse pehla vaada yeh ho ki vaada karne wala vaada nahi nibhaaye toh woh ek kanoonan apraadh ho. Aur iske liye sazaa ka pravdhan ho kyunki woh vaada karte hain, aap vote dete hain, woh chale jaate hain, phir agle paanch saal baad aaye hi nahi, toh baat hi khatam ho gayi"

In Coimbatore, money and muscle in electoral politics emerged as a rallying point for rural citizens across various districts. One man at the convening in Coimbatore made the point that the legal apparatus is stacked against the agricultural farmer, and if an instance of corruption does come to light, the government officer must also bear their

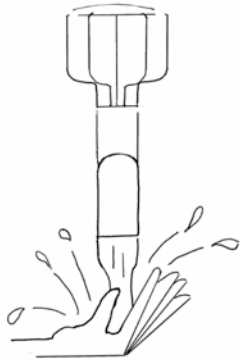

Clean Water: A Key Aspiration

Adrija Chaudhuri, Socratus

Water facilities play an important role in not just agriculture but human flourishing. And yet, rural areas continue to face difficulties in accessing water for drinking, domestic use and farming. It was sobering to see that a basic utility such as access to clean water was a key aspiration voiced by rural communities across the country. It was also one of the first challenges that came to their minds when prompted. At our Jodhpur convening, two women in purdah broke their reserved silence to tell us about the long distances (close to 10 km) they walked everyday to collect water. They had travelled from the semi-arid Nagaur district of Rajasthan and did not have access to tubewells or taps. The lack of water for drinking and irrigation was echoed by participants hailing from districts across Rajasthan, including Barmer, Balotra, Falodi, Sikar, Jodhpur, Pali and Udaipur. Farmers from these areas also lamented the decline in groundwater levels and its contamination.

The primacy of water issues in one of the most arid regions of the country was, although distressing, not surprising. However, problems with accessing water were prevalent even in states receiving high rainfall such as Odisha and Meghalaya. In Meghalaya, participants from the three main hill regions, Garo, Khasi and Jaintia, faced water shortages in the dry winter season. They did not have easy access to drinking water and even running water from taps. The lack of water for irrigation made them dependent on rainfall for agriculture. In Odisha, where we had participants from 21 districts out of 30, the lack of drinking water and irrigation facilities figured prominently, indicating the widespread nature of the issue.

Rural citizens also expressed concern for the degradation of their local water bodies. As mentioned earlier, in Muzaffarnagar, the pollution of groudwater was raised. In Tamil Nadu, especially, our participants were highly aware of water related issues regarding the pollution of rivers, lakes and streams of the Western Ghats. Groundwater was also being contaminated by industries. They recommended the revamping and conservation of water bodies and the diversion of water from rivers and dams into agricultural fields.

part of the blame.

There was also a strong sentiment in Rajasthan regarding corruption. Participants called for putting a stop to influencing votes by giving money and promising freebies. People wanted to bar corrupt politicians or those with criminal records from contesting elections. Citizens are tired of jumlas (false promises) and want their candidates to be held accountable to their campaign promises if they get elected.

It appears that "corruption mukt Bharat" is still a distant dream. Apart from the elections, corruption emerged as a big issue in governance as well. Most rural citizens felt that corruption in local governance was impeding the progress of their village. Corruption in panchayats and the cooperative sector was the topic of many a heated discussion in Muzaffarnagar and Jodhpur. Strengthening the Gram Sabhas was seen as a possible solution to encourage accountability at the local level. In Bhubaneswar, participants were weary of facing corruption in every sector, including in government schemes like NREGA, and dreamed of a corruption-free Odisha. In Shillong too, participants asked for a corruption-free government that would actually deliver on the promises made.

People vote after careful consideration

When people were asked to state the top issues that would determine their votes in the state and national elections, they gave it a lot of thought before individually writing it down. The analysis of people's opinions reveals some interesting observations.

People are politically aware. There is a distinct difference between issues prioritized for central government and those prioritized for state government. And the division is reasonably accurate in terms of their constitutional role. In Meghalaya, for instance, the most desirable ask from their Lok Sabha candidates was to represent the state and its indigenous culture at the national level, recognize the tribal languages in the Eighth Schedule, enable peace and help implement national schemes in the state. From their candidates in state elections, they wanted to hear about community development, water supply and employment. Similarly in Rajasthan, while the Vidhan Sabha candidates were to focus on jobs, law and order, education, and electricity, their national government representative's focus should be on interlinking rivers.

Water and corruption revealed themselves consistently in conversations around voting across the regions. The discourse on corruption seems to have reduced in recent years, yet the lived experience of people suggests that it is a widely occurring pertinent issue.

Rural India is asking for its rightful place

"Rajnaitik dal, grameen vikas ki yojnaon ke muddo ko apne goshna patr mein shaamil kar, goshna patr sammiti mein grameeno ka pratinidhitva sunischit karein."

The latent sentiment across more than 300 citizens from 60 districts was for a recognition of rural India's

Unemployed: Choice or Compulsion?

Ansila M. Thomas, Socratus

As we travelled through the expanse of the country, the conversation around unemployment seemed to be one unfortunate thread that remained common in all parts of the country. Across the five regions, we noticed that youth unemployment stood out as a particular point of contention. In some places it was underemployment for the educated, in other places it was a lack of diverse industry for people to be able to happily engage themselves in. In all cases, the bleakness of a lack of choice coloured the conversations surrounding livelihood.

While issues of livelihood and government policy were debated amongst the various groups, many, particularly those engaged in agriculture, did not want their children to follow their profession. In Muzaffarnagar, this led to many young people migrating to larger cities in search of better opportunities and lifestyles. Having watched their parents go into debt while farming and being discouraged to follow the profession, many young people do not want to continue looking after the fields with their parents.

A possible solution for how this migration away from the village could be stemmed is to equip the youth with a technical education for farming. But this is not happening. Educational curriculum remains largely alienated from agricultural needs and the general impression of the education received in these areas is that the quality is not top notch.

Many of these sentiments were echoed in the convenings in other parts of the country. In Jodhpur, Rajasthan, it was pointed out that unemployment was a major issue before the youth and that if electoral representatives prioritized policies supporting small businesses and manufacturing set ups that they would be more likely to vote for them. In Meghalaya the widespread unemployment was linked to the increase in drug and alcohol addiction among the youth.

In both the Odisha and Tamil Nadu convenings, political corruption was linked to unemployment in their regions. In Odisha, ineffective governance was a particular frustration that was often cited.

It is important to note that in all these cases, underemployment and the lack of choice when it came to employment were all identified as problems of equal importance as outright unemployment. In a departure from previous generations, employment is seen not just about making ends meet but about finding surplus income, purpose and recognition. Unfortunately, the work options in rural areas are not able to provide that to the youth today.

place in the national imagination. Our media, movies, aspirations and politics seem to have moved further and further away from the lived realities of 65% of Indians. It is a failure of governance and community action that these pressing concerns have not been resolved. Some concerns like roads and healthcare have been around for decades while others like climate change and drugs have emerged more recently.

"Har school mein ek khet hona chahiye ya rooftop farming honi chahiye aur aise paudhe lage hone chahiye jisse unko seekhne ko mile. Usee jo hain bacchon ko seekhne ko milega."

Agricultural activities need to be rejuvenated in the popular imagination. For the farmers, that is the most important challenge to address. If their children and the youth do not engage with agriculture, there is no future.

"Kya swabhimaan nahi hai humare andar..hum mehnat wale log hain, anan-daata keh laye jaate hai kisan.. khud nahi kamaa sakte kya?...aap hume vyavasthayein dijiye, saadhan dijiye, baaki ka hum kar lenge."

People still take pride in their villages and themselves. They want to flourish. They realize that migrating to cities doesn't assure them of a good life. They know many who end up staying in overcrowded slums, away from their communities, while working in the gig economy. They would rather build a better future for themselves in their villages, where they know people. The unsaid question is: instead of giving freebies, isn't it possible to invest and build local village entrepreneurs and businesses that can rejuvenate life in these areas? Can't agriculture be supported with good extension support and marketing? The aspirations of rural India are for a good life. Across India, they are similar and modest. They are ready to work to make this dream a reality. A farmers' collective in Coimbatore helps farmer families avail medical treatment with substantial discounts. Collectives have the power to do that. With the support of the right government action and markets, their aspirations can become reality. Rw

(**Prachur Goel** is *Director of Socratus.)*

Voices from Rural North-east India

Participants of Agenda for Rural India convening in Shillong.

Jonathan Donald Syiemlieh,
Socratus

Convening titled the 'Agenda for Rural India – Meghalaya,' successfully brought together voices from rural communities spanning across seven districts within the state. The diverse group of participants brought a wealth of experiences and perspectives to the discussions, enriching the discourse on rural development and sustainability.

Quote : 'I aspire for a smart clean and green villages in Meghalaya by 2030' - West Khasi Hills farmer

Despite its reputation as one of the wettest regions globally, Meghalaya grapples with water scarcity issues, particularly during the winter months. This scarcity adversely impacts the availability of clean drinking water and hinders agricultural irrigation activities.

Livelihoods: 'In Meghalaya, we're confronted with significant challenges in our livelihoods' remarked a participant from East Jaintia Hills. She shared insights about the extensive unemployment situation in the state, emphasizing the necessity for job opportunities and skill development programs to integrate the youth into the labor force. Other voices in the room from Ri Bhoi, Garo hills among other districts, highlighted the absence of rural food processing facilities which has hindered their ability to add value to agricultural products. Finding innovative ways to encourage entrepreneurship and rural enterprise could be pivotal in enhancing livelihood prospects for the people of Meghalaya as echoed by the participants.

Rural development: Participants brought to light the significant concern of road connectivity which hinders accessibility and limits opportunities for trade and transportation. The common voices across all the seven districts brought forward the insufficient health infrastructure coupled with the lack of consistent access to education facilities due to irregular teachers and high dropout rates. Additionally, a teacher from East Khasi Hills highlighted the scarcity of drinking water resources during the winter.

A large proportion of the participants stated that climate change induced pest infestations pose a significant threat to crop yields, exacerbating an already precarious situation for farmers. In this regard, farmers expressed their concerns on struggling to secure fair market prices for their produce and experiencing delays in receiving payments. One of the farmers from Eastern West Khasi hills stated that the unpredictable weather conditions and an increase in extreme events have severely impacted crop yields and the livelihoods of rural farmers.The participants from Meghalaya are calling for a regulatory role of the government in the agricultural market to protect the interests of farmers, promote fairness, and ensure that the agricultural sector remains stable and economically viable. Notably, a farmer from Ri Bhoi district highlighted the pressing need for cold storage facilities

Substance abuse: In Meghalaya, social issues concerning the younger generation are emerging as focal points of concern as stated by the participants. A village executive member expressed that the practice of early marriage among children raises questions about their overall well-being and access to education and opportunities. Artisans from Khasi Hills iterated about the increasing trend of youth succumbing to addiction to drugs and alcohol which poses potential long-term health and societal challenges.

Youth Interaction: We actively engaged with the youth of Meghalaya in Shillong to gain profound insights into their unique challenges and dreams. They voiced their concerns such as the inadequacy of attention directed towards vital rural infrastructure elements like roads, healthcare, and education. The youth vehemently stressed the need for government support to unlock the vast potential of rural areas, encompassing their abundant resources, the promotion of tourism, sporting opportunities, and the flourishing of the arts. Furthermore, the discussion delved into exploring pathways through which the youth could foster an entrepreneurial mindset and contribute to the growth and prosperity of their communities.

Aspirations Of New Rural India

T NANDAKUMAR

Former Secretary Food & Agriculture, GOI, Former Chairman NDDB

Rural Voice, a sister publication of Rural World and Socratus, an NGO, did the extraordinary: It went to rural areas and listened! It did a detailed exercise in mapping the aspirations of the people in five centres each representing a different geographical region of India. Presented in a nutshell, this represents a snapshot of the concerns, priorities and aspirations, of the majority of Indians and a vision for future. For the government and for policy makers, this presents a template for redesigning rural development and addressing the issues of an aspirational rural India.

While the issues have been outlined by the organisers under different heads of development, climate & environment and political economy, what stands out as common themes are the following: most rural areas want less use of fertilisers and pesticides, better markets and prices for their produce, a solution to the man-animal conflict, especially with reference to stray animals, much better focus on better education and health, and more effort in protecting the environment, particularly in terms of water and air. While these issues have been articulated time and again in different fora, it is probably the first time that they have been put together in a compact, actionable format. The common refrain from rural India seems to be the poll promises and their lack of implementation. It's no wonder then that rural India seems to be disappointed with politicians and their poll promises. They seem to realise that these are what they are: just promises. This perception needs to be changed if rural India is to become prosperous and healthy. Disappointment with the government could result in social unrest paving the way for extremism, detrimental to the overall progress of the nation.

Government has been aware of most of these problems that plague rural India. They made efforts to address these problems at various times have been through multiple schemes like MGNREGA, Swatch Bharat, Rural Drinking Water Mission (Jal Shakti) , Rural Electrification , PM Kisan, Aspirational District(now Block) Program, Mid-day Meals, Public Distribution System, ICDS etc. These did cover a lot of ground in terms of improving the incomes and lives of rural Indians. Most of these schemes have delivered positive results in terms of achieving the outcomes they set out to do. However, aspirational rural India expects more, and faster delivery of programs which visibly improve the lives of poor. From this perspective, a whole new approach of integrating some of the schemes and converging the interventions at the village and the block levels is required.

The ministry of rural development has been, ever since its creation, designing and implementing rural development and anti-poverty programs with substantially higher outlays. These include some of the flagship programs like IRDP and its later avatars, MGNREGA, PMGSY, etc. There are major programs which impact rural India designed and managed by other ministries like Health, Drinking Water and Sanitation, Agriculture, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Panchayati Raj, Water Resources etc. These programs are vertically driven by line ministries and implemented at the district and block levels. These are monitored centrally and at the state level by the respective agencies which implement these programs. However, the Ministry of Rural Development does not seem to have a comprehensive idea of all the rural development programs and their cumulative impact on the rural population. Measurement of outcomes and assessment of impacts remains a challenge from a larger development perspective. One of the things that Government needs to do is to give the rural development department, a much larger role in planning and monitoring of all rural programs, almost parallel to the role of Niti Aayog with a specific coordinating responsibility in terms of the programs being grounded at the block and district levels . This requires a planning and monitoring function embedded in the Rural Development Ministry. Given the hierarchical nature of governance at the Ministerial and Secretary levels in the central ministries, this needs a different design of a coordinating authority embedded in the rural development ministry. The time-tested

coordinating committee or an empowered group pf ministers is unlikely to produce results. While the line ministries should be free to design programs, as per national priorities, the convergence of these programs at the implementation level and the monitoring of outcomes should be entrusted to this new coordinating authority. A similar authority should also be found at the state level.

Effective implementation of most of the central programs depends on effective governance at the state and district level. The district has become the key administrative unit in implementation of most developmental programs. However, the institution of the District Collector still retains the structure and character of the old Revenue and Law and Order System. Experiments with the creation of a district development commissioner at the district level and a Zila Parishad (District Council) system has not had the desired impact. The state governments have been, by large, hesitant to delegate its role and functions to any district level organisation, be it, elected, or otherwise. Except one or two states, the district level Panchayati Raj (Zila Parishad) experiment have not had many successes to its credit. In modern times, given the technological prowess driving development, and given the importance of private sector participation, the model of governance at the district level needs a redesign in terms of its scope, power and responsibilities. While planning should remain the concern of elected representatives, implementation has to be the responsibility of the executive. The monitoring of development has to be done differently and scope for corrective action embedded in the schemes themselves. The office of the district collector with its current staffing norms will not be able to meet the challenges of an aspirational India. This office needs serious redesign and strengthening with a set of young tech savvy management professionals to support the district collector. The Collector should also be freed from many of the routine committees and meetings. Redesign of the role and functions of the district collector is urgently called for if meaningful rural development has to be achieved.

The block development office, which is the fulcrum of rural development, was originally conceived in the community development agenda of the erstwhile Planning Commission. This office is probably the most reviewed, supervised and monitored office in the entire administrative hierarchy. Skills and support systems remaining the same, the burden that this office is expected to carry is enormous. No wonder then, that achievement of targets, whichever way, becomes the priority. In the implementation hierarchy the block development officer is the most important in terms of functions and responsibilities, but probably the weakest in terms of skills and support systems.

States which have experimented with delegation of more functions and responsibilities to the Panchayats as envisaged in the Constitution (73^{rd} Amendment), have had better outcomes to report than those who were slow in empowering Panchayats. Many states did a pro forma delegation of powers to Panchayats without actually empowering them with any skill or financial powers. One of the most important steps that needs to be taken to achieve a faster rural development is to empower the panchayats to design, plan and implement locally appropriate schemes with the best technical support available. Inability of the state to allocate untied resources to panchayats, in spite of Finance Commission grants, and help them achieve better results, has remained the bane of effective rural development. A five-year investment program, involving skill development, technology, upgrades, management orientation, reporting and monitoring systems coupled with higher devolution of funds and continuing guidance for its utilisation is the first step to change the rural scenario in a shorter time.

There are, of course, issues of policy at the national level which needs to take care of the aspirations relating to policies around agriculture, livestock and fisheries, incentives for chemical fertilisers, promotion of natural & organic farming, linking rural markets to urban demand centres, investment in rural areas for processing agriculture produce, investment in rural infrastructure and policies relating to climate and environment. The new Multi-Dimensional Poverty Index captures most of these issues: what is required is a comprehensive action plan.

The most important part of any people friendly and people focused scheme is the ability of the government at various levels to listen carefully to what the people have to say. This effort by **Rural Voice** is a small but important step in understanding the problems and the aspirations of rural India. Government would be well advised to use such non-formal platforms to listen to multiple voices to understand the problems and aspirations to design people-friendly policies. Rw

While planning should remain the concern of elected representatives, implementation has to be the responsibility of the executive. The monitoring of development has to be done differently and scope for corrective action embedded in the schemes themselves.

States Have Bigger Role For Agri Reforms

According to NITI Aayog member ***Prof. Ramesh Chand,*** *states have greater responsibility towards the agricultural sector, they should make laws according to their circumstances.*

For the last 10 years, our growth in agricultural productivity has been higher than that of China and America, hence the yield gap has started reducing. NITI Aayog member Professor Ramesh Chand is a world-renowned agricultural economist. His imprint is always visible in the determination of agricultural policies of the country. Being an agricultural economist, he has written many papers and books. In a long interview with **Rural World** *Editor-in-Chief* ***Harvir Singh,*** *Prof. Chand has spoken about all major issues related to the agriculture sector in the country. Edited excerpts:*

Q Agricultural marketing is still a very complex issue. This leads to huge fluctuations in crop prices which are harmful for both farmers and consumers. What should be the roadmap for agricultural reforms? Farmers are demanding guarantee of MSP, but you consider Bhavantar – price/cost difference as an effective policy step for farmers. What is your opinion on this and how should it be done?

The nature of agricultural production is such that it depends heavily on weather and climate. For this reason there is instability and ups and downs in them, which is natural. We cannot stop it, but the fluctuations that occur due to the nature of production and which

impact farmers and consumers, we can and should reduce them with the right market policies. There are two sides to the price farmers get for their produce. Firstly, Minimum Support Price (MSP) is received from the government and secondly, the price is received from the market. These two are not competitors of each other, but complement each other. If the market is competitive, farmers will get a fair price, but if production is high, the price falls despite competition. Therefore, there is a need for government intervention regarding prices in the market also. We should take care of two-three things. Firstly, we should not increase the MSP so much that if the farmers can get better prices in the market, then the MSP should not harm them. Secondly, what is the means of giving MSP? In our country it is mostly given through government procurement. Government procurement of grains is also necessary because we need grains for the Public Distribution System (PDS).

If we need food grains other than PDS, then we need to adopt other means, like Bhavantar Bhugtan Yojana, the idea of which I had given many years ago. Little implementation has been done in Madhya Pradesh and Haryana. Therefore, other such means should also be used which can control the negative impact of MSP.

Q ***Agriculture subsidy has been a big issue for policy makers and economists. It is not only complex but also politically sensitive. According to you, should the policy of giving subsidy continue or an incentive based economic policy should be adopted? Some states have adopted the policy of direct cash transfer to farmers. The Central Government has also been giving Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi to the farmers in the form of direct benefit transfer for the last five years. Can it replace subsidies in future?***

Both have their own advantages and disadvantages. First let me explain in detail what should be considered in this and what situation we are moving towards. The biggest advantage of subsidy is that it encourages production and brings growth, because most of the subsidies are on inputs. Only the farmer who uses the input will get subsidy. One side of this is that if a farmer does not use the inputs in his land, then there is no justification for him getting subsidy. The second is to give cash, which the farmer can use in any form, whether it is fertilizer input or any other input or anything else. This will be available to everyone, regardless of whether they use input or not. But subsidies do not have as much positive impact on production as cash transfers do. The one who uses more fertilizer has more production. It brings a balance to the system. There are many types of subsidies. Just as you give subsidy on seeds, then it is a good thing to give subsidy on technology which is a career. Subsidy is good for agricultural conservation. If you give subsidy for farm mechanization, which enables the farmer to manage the stubble instead of burning it, then it is very good. What is important is how the subsidy is given and on what basis. More than the subsidy itself, its negative effects arise from the way the subsidy is delivered. We provide free electricity to farmers for irrigation, this will lead to more water usage and ground water level will go down. Thus both have negative and positive aspects. We should take a balanced approach keeping all the aspects in mind.

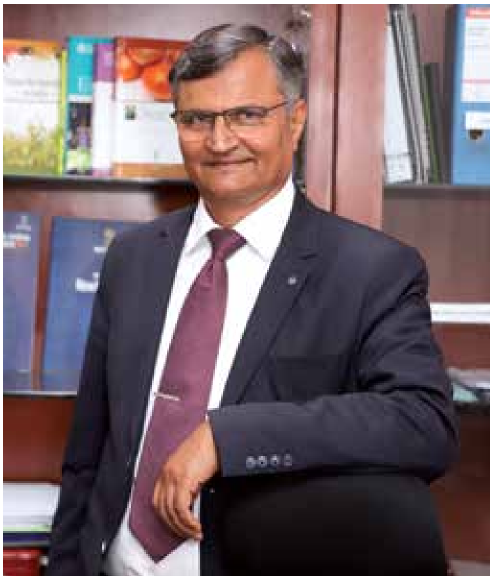

If we need food grains other than PDS, then we need to adopt other means, like Bhavantar Bhugtan Yojana, the idea of which I had given many years ago.

We are moving towards direct benefit transfer and income support and also giving subsidies, but no government has rationalized it and this should not happen. It is argued that direct benefit transfer or income support is being given to farmers to reduce subsidies, but in reality we are not reducing them. If all the positive and negative aspects are considered then the amount given as income support is better than subsidy.

Q ***India has achieved self-reliance in food security and the country has emerged as a major agricultural exporter. The level of agricultural exports has crossed 50 billion dollars. But why has there been a situation of ban or strictness on the export of wheat, rice and sugar for the last two years, while the government has made claims of record production? Why is there no stability in policies regarding export of agricultural products? How do you view decisions taken suddenly?***

If there is no stability in your situation then you cannot keep the policy permanent. Policies are made keeping in mind the circumstances. If such a situation arises that international prices fluctuate more than the normal fluctuation of 10-15 per cent, then this

> **Farmers and traders should keep this in their mind that if the prices remain within the prescribed limit, the government will not interfere.**

intervention becomes necessary. If there is a sudden flood or any natural disaster somewhere in the country, or production gets affected due to some circumstances, then in that situation you have to choose whether you give priority to own country or to the foreign country. Is your own consumer or foreign consumer the priority? That's why I said that the situation is not permanent, especially in the case of agriculture. Therefore, we cannot keep the policies permanent.

Many decisions appear to have been taken suddenly, but you will see that there must have been some reason or the other. As you saw in the case of onion recently. Such a situation had suddenly arisen in onion. Had there been no intervention, the prices of onion would have gone up to Rs 100, as was the case earlier. Food management and controlling food prices becomes important for both consumers and farmers. I definitely agree with you that this intervention should happen only when the price goes above or below a certain limit.

Farmers and traders should keep this in their mind that if the prices remain within the prescribed limit, the government will not interfere. If it goes above or below that, the government will definitely intervene. Most governments in foreign countries also do this. This has been happening with us since the beginning. It is not that trade has been left free. We have always followed the policy of strategic liberalisation. Our aim has been that we will allow our prices to go up and down according to international trade, but if the fluctuations are high, we will protect them, sometimes in the interest of the consumer, and sometimes in the interest of the farmers.

Q ***Were the three repealed agricultural laws need of the hour, should work still be done on agricultural reforms? The government has been continuously using the Essential Commodities Act for two years which is not in line with the liberal agricultural market spirit of the three farm laws. These two subjects are contradictory to each other, so how much reforms are needed in the agriculture sector?***

When the three agricultural laws were withdrawn, the Prime Minister said that perhaps we had failed to explain the benefits of these laws to the farmers. There may be shortcomings in the policies. When farmers were protesting, I had issued a paper from NITI Aayog. Those who are interested in this should see the paper to know with which thinking the thinkers of the government started the process of bringing new laws. I believe that there are many important reasons for progress in any economy. For example, technology is a factor in increasing production, secondly, our policies and institutions are its factors. If we do not improve policies and institutions according to the situation, then only incremental change will come, not transformational change. It is very important to bring improvement.

We all know that some aspects of the agriculture sector are at the central level and some at the state level. The responsibility of the states is equally big, or rather their responsibility towards the agricultural sector is bigger. They should extensively discuss its positive and negative aspects, and take whatever comes out of it and move towards reforms.

Secondly, your question is that on one hand the Central Government had brought reforms in the Essential Commodities Act, and on the other hand it is itself using it more. The

basis for bringing changes in the Essential Commodities Act was that if competition in the market increases, private investment in the market will increase. If there is ever a need for availability of anything, the buffer stock not only of the government but also of the private sector will play an important role. Because there are only two ways in which prices can remain stable, either you trade or keep it in stock. In most countries there is no government stock, there fluctuations are controlled only through private stock. If the law related to the market had been implemented, you would have seen how much private investment would have increased and how many storage houses would have been built. Instead of all the goods coming into the market at once, they would come out gradually according to the price. The Essential Commodities Act and the laws regarding the market were complementary to each other. If there is Essential Commodities Act then private investment will not come, and if private investment does not come then you will need Essential Commodities Act. This is one reason why the government is now doing the opposite of what it wanted to do earlier.

Q ***You recently released the paper 'Green Revolution to Amrit Kaal: Lessons and Way Forward for Indian Agriculture', in which you have put forward steps for the future strategy of agriculture by taking lessons from the Green Revolution. How will these be implemented?***

We have had many achievements in the last 75 years and we have a historic record in the last 10 years. The growth of agriculture sector has been 4-5 percent. There are many such achievements. Many challenges have also arisen with him. Climate change has emerged as a big challenge for the agricultural sector, excessive use of chemicals has affected people's health. Keeping all these things in mind, if we do not make a scientific road map then there will be a possibility of wandering here and there. Most of the evidence is that excluding agro-chemical based farming, productivity in traditional farming, in which agro-chemicals were not used and indigenous seeds were used, would be affected by 30 to 35 percent. I look at the lack of productivity in traditional farming in a different way. 100 years of science has played a role in the modern farming that started due to the Green Revolution. Maize hybrids were introduced only in 1920. Then chemicals came, different types of seeds came, and many other things came. On one hand there is 100 years of science and on the other hand there is traditional farming in which we have not included science at all.

Keeping all this in view, I have put together a road map that we can bear a part of the production that is expected to be affected because now we are surplus in food grains. We can take this chance and move towards that direction slowly but very carefully. Let us take stock after ten years that during this time we have been successful in increasing the productivity by including science in it so that there is no negative impact on our food security.

We have had many achievements in the last 75 years and we have a historic record in the last 10 years. The growth of agriculture sector has been 4-5 percent.

The model adopted by those countries which turned from developing to developed, today's industry has closed that option for us. The biggest challenge for us is that if we are moving forward with the goal of a developed India, in which the income of every person will increase from 2100 dollars to 11-12 thousand dollars, then where will people get employment, where will people's income come from? In the government's goal of inclusive growth, we not only have to increase the income of the country, but also increase the income of all the people, and income increases through employment. In that road map, I have also tried to highlight that we now have to think about agriculture-centric development, because our employment is still agriculture-centric. Recently, PLFS survey of 2022-23 came, it also says that 45.8 percent of the workforce is in the agriculture sector. It is decreasing very slowly. Looking at sustainability, employment, climate change and maintaining the pace of growth, I have taken a position that agriculture will play a central role in creating a developed India.

Q ***There is emphasis on new technology in agriculture but public investment in agricultural research and infrastructural facilities is not increasing, the need of which has been continuously expressed by agricultural scientists. The government's policy regarding GM technology is also not very clear. Is GM technology useful for India and should we take an aggressive approach in adopting research and technology and increasing investment?***

Technologies in agriculture sector are coming from many fields. Earlier we were completely dependent on the public sector. Now you must be seeing that agri-startups are also coming, there is also private sector. But the fragmentation we did in agriculture – Agriculture University, Veterinary University, Horticulture University, Fisheries University – increased the fixed costs so much that the money which should have gone into research started going into salaries. We could have used it efficiently. Many governments also say that if all the money is spent on subsidies then how will it be given for research. We should take this seriously. Only public sector research strengthens the country. I would also say that the farmers should promote the technology available for their benefit, the states should also try for this and this is very important.

Nowadays technology is also becoming expensive. We have to compete with the world.

You asked the question of GM technology, it is a sensitive issue but I will not hesitate to answer it because it is a matter of the future of the country and the farmers. First of all, I believe that where you get success through traditional technology, we should not go into GM at all, like in wheat and rice, if we are getting success then there is no need to go into it. But even after putting in all efforts, if we do not get anything from traditional technology, then we are forced to turn to GM technology. Secondly, what is being said is that the private sector makes the technology very expensive through seeds, so where the development of GM is done by public sector institutions, like they developed brinjal, mustard, we should do the same. Third, there is no objective assessment of GM technology in our country. Even in GEAC there was no agricultural scientist. It is important to keep agricultural scientists in policy making. We want to reduce the use of chemicals, GM technology is a substitute for many types of chemicals in which you get freedom from chemicals, so we should look at all these things. And fourth, we are not ignoring technology too much. On one hand we are ignoring technology and on the other hand we have to spend billions of dollars on importing edible oils. Considering all these things, the country should not reject it completely. If we do not get success anywhere else then we should definitely give it a chance in edible oil.

Q The increasing incidents of environmental change are having a major impact on agriculture. Farmers have also started understanding the harm of climate change. A recent report by the Agriculture and Food Organization of the United Nations (FAO) states that in the last three decades, agricultural and allied sector production has suffered a loss of $ 3.8 trillion due to climate change, natural disasters and adverse weather. How will we be able to deal with this? How will we be able to protect agricultural production and farmers' income from this, how will we be able to maintain balance with this?

This is an issue of survival of the planet and people, not an issue of farmers' income. There is a National Action Plan on Environment which has different missions. There is also a Water Mission which is linked to agriculture. Agriculture is a sector which is affected by climate change and also affects the climate. If the temperature increases by one degree, it does not affect the production of cars or refrigerators, but agricultural production is affected. The most negative impact of climate change is going to be on the agri food sector.

There is another issue which has been completely ignored. I had also called important people from 14 countries of the world through FAO to discuss the same thing. I also asked the FAO to bring forward this issue that farmers are now understanding the impact of climate change on agriculture, but are not aware that agriculture also has an impact on climate change. We cannot leave it to the industry and transport sector alone to reduce their emissions. The role of agriculture in climate change in India is 17 percent. Agriculture is the biggest stakeholder in this. Green house gases are released from agriculture. Just as we are talking about electrical vehicles, green economy and green hydrogen, similarly we will have to talk about reducing emissions in agriculture. Now it has been decided that we have to stop the temperature rise of one and a half degree. Till now we have not felt its harm because science has succeeded in reducing the impact of climate change. But there is a limit to it and we are moving towards the upper limit. When we reach that limit then no science will be able to counter it. We have to save agriculture from climate change, and the contribution of agriculture in saving the environment also has to be reduced like other sectors.

"The role of agriculture in climate change in India is 17 percent. Agriculture is the biggest stakeholder in this. Green house gases are released from agriculture."

Q More production growth than crops is coming from dairy, fisheries and horticulture. In such a situation, do you think that farmers' income can be increased through agricultural diversification?

Certainly, if you look at the income, there is definitely risk in horticulture crops but the income is 4 to 5 times more than non-horticulture crops. Today, the highest productivity and highest growth is coming in those states which are moving towards diversification. Due to the Green Revolution, states like Haryana and Punjab, which used to be ahead in productivity, are no longer at the top. Andhra Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh are moving ahead. Where diversification has taken place or is taking place, there is rapid growth and higher productivity. We have to provide new avenues to the farmers dependent on MSP. In my paper which you mentioned, I have given a graph related to this. The segment of agriculture in which there is more government interference, whether through MSP or subsidy, has less growth. The reason for this is that diversification is dependent on demand and that which is dependent on demand has more power to pay the price. That is why you are seeing that the demand for vegetables, fruits, eggs, poultry, milk and fish is increasing as per demand. The demand for grains is increasing very slowly. Diversification is a major factor in growth and increasing the income of farmers.

Q Your assessment is that in the coming decades, India will have to find export markets for up to 25 percent of its additional production. Is any such strategy being worked on? How much scope is there for this in

> **The segment of agriculture in which there is more government interference, whether through MSP or subsidy, has less growth.**

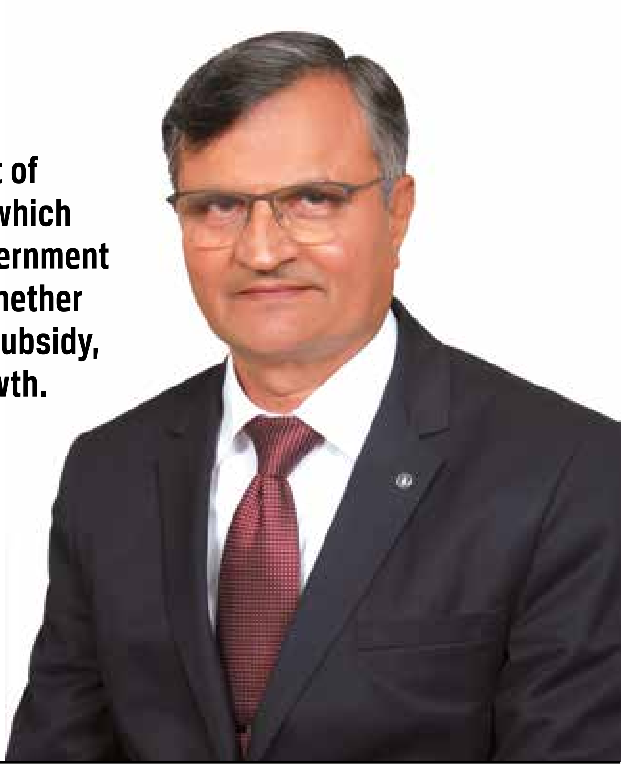

the trade agreements being made at the World Trade Organization and regional level?

The percentage of foreign market that we will have to look for in the next 10 years depends on the expectation that our agriculture sector will grow by 3 to 3.5 percent. If the industry demand is increasing by 2.25 per cent, then our surplus will increase. Today the situation is not normal, international prices are at a high level. Today anything of yours will be exported. But after two-three years the prices will come down because there is a cycle of prices. The price of wheat will come down. We have to prepare the agriculture sector to remain competitive in that situation. For that I have also suggested that there is competition in two ways. One is supply chain and the other is production. We have to carry them, otherwise there are chances of price crash. We have to bring efficiency in agriculture and make some parts export oriented. There are lots of options coming in it. You must have heard about ONDC platform i.e. Open Network and Digital Commerce. If we sell the produce through that then there is cost savings. The second way is through FPO which we are linking with ONDC. There are some such innovative ideas in marketing. We have to reduce costs not only in production but also in marketing. Along with production, we also have to bring efficiency in the supply chain. We have to move forward by making both transportation and marketing competitive. This is the future of our agriculture.

Q ***Even now 45.8 percent of India's working population is earning livelihood from agriculture and related sectors. The gap between their income and those in the non-agricultural sector is increasing. In such a situation, the gap between rural and urban India is increasing, how to reduce it?***

The size of our holdings is small. Small farmers are becoming more efficient than big farmers. It is said that small is beautiful, but here small is not strong. Alternative sources of income are necessary for them. There are part-time farmers whose more than half of their income comes from non-farm sources, such as odd jobs. There are many farmers who want to leave agriculture. There are also those who want to increase their holding by taking land on lease.

Q ***The government gives subsidy on loans for the agricultural sector, but in different states, sharecroppers who cultivate about 15 to 30 percent of the land do not get the benefit. Is the need of the hour now to implement the Model Land Leasing Act or other reforms?***

The situation is different in different areas of the country. If you look at eastern states like Bihar, Jharkhand, Assam, Odisha, institutional debt is still low there. We need to promote that. On the other hand, there are some states where more credit is being given. That loan is being spent here and there. We need a different policy there. As farmer leaders say, banks also have a role in giving mortgage to the farmers, they give them a lot of loans. This is changing. Farmer credit cards have been made, now even animal farmer cards are being made, farmer credit cards are also being made for fish farming. Farmers should also keep in mind that they should take such a loan which is easy to repay. Agriculture has become a mechanism for credit in many areas. At the end of the year you returned the money and took it back in exchange. I would say that the role of credit should be in bringing diversification in North-West India.

Long ago, NITI Aayog had given a land lease model which was adopted in a limited form by some states but we need it very much. Fallow land is increasing in the country. Farmers' sons are now coming into the non-agricultural sector. States must pay attention to implementing the Model Land Leasing Act. This will make a lot of difference.

Q ***How important is farmer loan waiver and is its purpose right or not?***

If a major natural disaster occurs, in that case I would say that it can be justified. If no major crisis of that kind arises, loan waiver would cause significant damage to the institutional credit delivery system. I think such things should be avoided under normal circumstances. Rw

Tailoring India's Agricultural Education for Youth

RS Paroda

Former Secretary, DARE & Director General,ICAR and Chairman, Trust for Advancement of Agricultural Sciences(TAAS), New Delhi

India with 1.41 billion people is the second most populous country in the world after China (1.452) and is projected to surpass China soon and reach an estimated figure of 1.668 billion by 2050, as per the 2022 edition of United Nations' World Population Prospects. Further, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India (GoI) in its recently released report on 'Youth in India 2022' has estimated that youth in the age group of 15-29 years comprised 27.2 per cent of the population in 2021, which is expected to decrease to 22.7 by 2036. Nonetheless, today India has the largest global youth population of 356 million between 10-24 years age group with greater proportion of nearly 200 million young people living in the rural areas. In addition, the overall rate of literacy among India's youth has increased, with approximately 90 per cent being able to read or write. Coupled with the prevalence of social media and internet penetration, the youth are largely digitally savvy population, accessing online resources that encourage learning and enhancing skills. Thus, the country has the advantage of a 'demographic dividend.' When this vast resource of young citizens enters the workforce, it could lead to greater economic growth resulting from a shift in a population's age structure, mainly when the working-age population is larger than the number of dependents. These young people are driving a culture of innovation, entrepreneurship and diversity and need to have greater inclusion in the agricultural sector, which contributes to nearly 20 per cent of the country's GDP.

The COVID-19 crisis has amply demonstrated that even under the most severe lockdown of economic activities, agriculture needs to continue producing without fail. Many countries have reported economic recession and efforts to revive their economies to overcome shocks due to the pandemic are underway. Education in general and agricultural education would be the most crucial for this process. It is only with high quality, inclusive and equitable training, countries will succeed in overcoming the pandemic setback, which has impacted millions of children, youth, and adults, especially in the lower income groups. In agrarian countries like India, agriculture is a central activity contributing significantly to the national GDP. In the years to come, the agriculture sector will take another qualitative leap, taking the benefits of digitalization and other technological advancements.

Why Youth are Reluctant to Join Agricultural Sector?

Over the years, the farming community has been affected adversely due to small land holdings, which comprise over 80 per cent of total farm households. Multiple risks associated with agriculture intensify the challenges owing to over-exploitation of natural resources linked with rapidly increasing globalization, soaring fuel and food prices, volatile markets and growing climatic volatility. It is estimated that only around five per cent of youth is currently involved in agriculture. This is because they do not find agriculture a creative, profitable and/or a respectable profession. Youth is a great resource, to be used for agricultural development and hence the challenges to retain youth in agriculture (Box 1) are to be effectively addressed. A major dilemma in the developing world is the poor social image of agriculture due to which, rural youth are moving towards the urban sector, looking for alternative and better opportunities. It is evident through successful business models of leading public and private sector organizations, as well as multinational companies (e.g., IT sector), that

youth are more innovative and productive as well as receptive to new technologies. On the contrary, in the agriculture sector, there is a wide gap between energy (youth) and experience (older people), which is a cause of backward nature of farming and slow adoption of innovations and new technologies. Due to poor technology dissemination, science is delinked with the society, which makes farming non-remunerative as well as non-resilient. Unless the intellectually satisfying technologies are in place, the youth is not likely to get attracted towards agriculture.

In fact, rural youth (both men and women) need vocational trainings in the potential areas like information communication technology (ICT), high-value agriculture, processing, value-addition, packaging, supply-chain management, storage, etc. This will empower them with knowledge and skills in priority areas like specialty agriculture, high-tech horticulture, protected cultivation, IPM/biocontrol, dairying, fisheries, bee keeping, community nursery, seed production, linking farmers with markets, etc. Well trained and competent youth will certainly embrace agriculture with high degree of confidence. Thus, under the above scenario, agriculture is not seen to be a remunerative and respectable profession, particularly by youth, and is not considered a sustainable pathway to meet food, nutrition, and livelihood security. It is well understood that youth (both men and women) of today have a different mind-set and outlook and like to pursue intellectually satisfying, commercially viable and socially empowering activities.

Unfortunately, in developing countries like India, there exists an 'aspiration-attainment gap'. Hence, their aspirations must be addressed on priority. Therefore, youth must be motivated through advances in innovation, capacity development, partnership and a participatory approach, through enhanced skills and a positive attitude towards their role in the overall agricultural and rural development of the country. It would require a paradigm shift in the mindset, from traditional agriculture as the means of livelihood to a business-oriented, specialized agriculture involving skilled youth in rural areas. The current agricultural occupation scenario has to be made attractive and remunerative through scaling new innovations and entrepreneurships. Quality/skilled youth can only be attracted and retained in farming if it is associated with improved rural infrastructure and better educational and related facilities. The comprehensive strategies for plausible transformation in future would demand more rewarding jobs in all agro-based and agro-related activities with equal opportunities and facilities in rural and urban areas, better options for public–private sector investments in agriculture and rural-sector infrastructure, and promotion of small agri-firms and producer companies to promote agri-food and value-chain systems. To empower rural youth, including women, here is an urgent need to also transform the extension system into an innovation extension platform that delivers technology-orientated knowledge, inputs, and value-added services. The extension approach would have to focus on farming communities rather than an individual farm household approach, as had been the case in the past. All these are critical for future growth and development of any nation and would, therefore, need an enabling environment through policy and institutional support by all concerned.

Challenges In Retaining Youth In Agriculture

- Insufficient access to knowledge, information, and education
- Limited access to land
- Inadequate access to financial services
- Lack of formal and informal on-the-job training
- Limited access to markets
- Limited involvement in decision-making and policy dialogues

BOX - 1

Major Concerns of Agricultural Education in India

The National Agricultural Research and Education and Extension System (NAREES) of India is one of the largest agricultural education systems with 4 Deemed-to-be-Universities, 3 Central Agricultural Universities, 3 Central Universities, 63 State Agricultural Universities (SAUs), 93 ICAR Institutions and 731 Krishi Vigyan Kendras (KVKs) under the aegis of Indian Council of Agricultural Research (ICAR). Over

Rural youth (both men and women) need vocational trainings in the potential areas like information communication technology (ICT), high-value agriculture, processing, value-addition, packaging, supply-chain management, storage, etc.

Major Concerns of Agricultural Education (AE) in India

- AE admission in undergraduate courses is not the first priority of most students, as compared to engineering, medicine, law, accountancy, etc.
- AE has very low gross enrolment ratio (GER); out of the total eligible population in the country GER for AE is only 0.03% whereas for higher education it is 26%.
- AE is a state subject, which has caused variations in terms of funding, faculty recruitment and salary, infrastructure, and faculty/student developments programs. The coordination between Centre and States is also insufficient.
- Inadequate investment and declining financial resources in agricultural universities/colleges
- Student retention in agriculture is low (only 30% graduates continue in the same sector)
- Opening of new institutions without matching resources and norms, especially by private sector which are giving degree in agriculture, some of which are lacking quality control and charge very high tuition fees and other dues
- Disconnect among agricultural education, employment and industries' requirements
- Lack of adequate skill, entrepreneurship, and experiential learning; overall poor employability of agricultural graduates
- Inadequate academic rigour and contextualization of emerging challenges and

opportunities

- Erosion of basic sciences from agricultural courses
- Widening disconnect between education, research and extension resulting in knowledge deficit
- Poor system of evaluation, monitoring, impact assessment, accountability, and incentive systems
- Limited digitalization; and inefficient governance.

BOX - 2

Keeping in view the changes in aspirations and lifestyle, there is a need to bring about changes in the agri-education ecosystem, to motivate and attract youth to agriculture and allied fields.

the years, it has contributed significantly both for research and technological outputs around agriculture. Besides the concerns in agricultural education shown in Box 2, two other systemic weaknesses in the current system are: (i) the curricula are not integrally linked to development programs, and (ii) there is a disconnect between agri-graduates and farming community, with the former not providing the required services and not integrally linked to development programs, and (ii) there is a disconnect between agri-graduates and farming community, with the former not providing the required services to the later. Also, over the years, knowledge creation has invariably taken a back seat due to over-emphasis on technology transfer and 'location-specific regional research' by SAUs. Further, the students tend to aspire executive positions from the beginning of their career, creating a deficit for the skilled operations at the lower levels of farm sector.

Transforming Agri-Education System

Keeping in view the changes in aspirations and lifestyle, there is a need to bring about changes in the agri-education ecosystem. Youth can be retained in agriculture only when required knowledge and education, technical skills, sustained encouragement and enabling policy environments are provided. In addition, the required policies, incentives, and rewards need to be put in place to attract young talents to undertake innovative farming that is not only profitable and sustainable but also respectable. This will inspire as well as attract the youth to adopt agriculture as a profession for their happy living. Such an approach should be a strategic priority at the local, state and country level to ensure youth-led inclusive growth in agriculture. Thus, the new strategy should be to reorient present-day agriculture from crop based to farming system based with emphasis on 'plough-to-plate' approach, which is more relevant, efficient, demand-driven, productive, competitive, and profitable. It must also ensure food, nutrition and environmental security for all.

The ICAR, in collaboration with all relevant stakeholders in the recent past, has undertaken some important reforms in AE in India. Quality assurance in higher agricultural education has been introduced through accreditation system, framing of minimum standards for higher education, academic regulations, personnel policies, review of course curricula and delivery systems, support for creating/strengthening infrastructure and facilities, improvement of faculty competence and admission of students through All India Examination.

Notwithstanding the initiatives Vis-a-vis ICAR's Fifth Deans' Committee Report, there is still good scope for further improvement in the AE ecosystem for motivating and attracting youth (MAYA) in agriculture through greater attention on technical and policy aspects as follows:

Technical Aspects

- As articulated in the NEP 2020, agricultural education must maintain such standards to ensure that agricultural graduates from India are professionally well equipped to handle national as well as international challenges.
- The NAREES should assess the manpower needs of the fast transforming, knowledge-intensive agriculture to make necessary adjustments in curricula and skill development, emphasizing on experiential learning and exposure to national and international issues.
- More technological interventions are likely in the disciplines of ICT, digitalization, biotechnology, nanotechnology, agro-processing, precision agriculture and systems simulation, hence the associated manpower demand and shift in the pedagogy be accordingly included.
- Pluralistic approach and public-private partnership focusing on business/ marketing/income orientation are needed for making the local extension sensitive to the challenges at micro level, strengthening the feedback mechanism and setting the right priorities.
- Promoting entrepreneurship and agri-startups, encouraging market-led extension strategies and intensive use of electronic media should be duly covered in the educational programs.

Policy Aspects

- The Ministry may consider setting-up an 'Agricultural Education Council of India (AECI)' as a regulatory authority which should work on similar lines as that of the Veterinary Council of India (VCI).
- Since higher education is on the concurrent list, agricultural education must be brought into the concurrent list in order to bring uniformity in proposed reforms.
- World class institutes should be set- up along the lines of IITs and IIMs with needed autonomy for decision making.
- The focus should be shifted to instil employable skills in agriculture graduates; invest on non-formal education and vocational training in agricultural technologies
- Educational reforms must now embrace non-formal degree programs around diploma and certificate courses to impart skill oriented vocational training programs for empowering youth to be 'job creator' rather than 'job seeker'.

Conclusion

Agricultural education sector, as in other subjects, requires a trained human capital with youth who (i) possess social consciousness and are connected and committed to rural communities; (ii) have strong entrepreneurial skills and spirit, and are capable of initiating new job opportunities; (ii) are guided by positive values and high ethical standards; (iv) are committed to a new vision towards sustainable agricultural production, (v) have a solid grounding in the scientific and technical principles that underlie the practical experience so critical for building confidence; (vi) undertake generalist preparation that will enable them to develop holistic solutions to the problems that they will encounter in their careers (vii) are innovators with the confidence to be creative and address real problems (viii) possess strong leadership, interpersonal and team building skills and demonstrate strong communication skills, including effective use of international business languages and information technology, (ix) have 'business skills' to generate employment and wealth and able to work particularly with rural communities.

This needs a paradigm shift in our approach and policy focused on youth to transform them from 'job seekers to job creators'. Capacity development of youth through informal and vocational training and creating awareness of new opportunities in agriculture, including secondary and specialty agriculture, would attract youth in agriculture, help bridge the gap between rural and urban and boost rural economy for contributing towards faster national economic growth.

Finally, motivating youth through enabling environment, institutional support and required hand holding will not only attract youth to agriculture but would ensure accelerated growth of agriculture sector to contribute at least one trillion out of targeted five trillion economy envisioned by our Prime Minister. Rw

The Ministry may consider setting-up an 'Agricultural Education Council of India (AECI)' as a regulatory authority which should work on similar lines as that of the Veterinary Council of India (VCI).

Opinion

Indian Agriculture Needs A Holistic Policy Framework

Dr Biswajit Dhar

Professor, Jawaharlal Nehru University (Retd) & Distinguished Professor Council for Social Development

For any observer of India's economic progress, it should be obvious that India's agricultural sector is steeped in crisis for the past several decades. In 1950-51, agriculture's share in the country's GDP (including livestock) was 45%; the share of the workforce directly dependent on the sector was close to 70%. Seven decades later, agriculture's share in GDP is just around 15%, but more than 42% of the country's workforce depends on this sector. Unless this fundamental imbalance is resolved, agriculture will continue to be the Achilles' heel of India's economic transformation story, which it has been for a long time now. It will, therefore, be impossible for India to catapult itself out of the ranks of lower-middle income countries it has been caught in for nearly a decade-and-a-half.

Logically speaking, the income-employment imbalance in agriculture can be addressed through a sustained rise in agricultural incomes and/or reduction in the share of the workforce in agriculture. The National Democratic Alliance (NDA) government had focused on the former since 2016, setting the target of doubling farmers' incomes by 2022. However, in the period since, no definitive policy initiatives were taken for realising this objective until the farm laws were introduced as ordinances in May 2020 and were enacted as laws by the Parliament, in record time. The three laws (henceforth farm legislations) are Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, and the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. These farm bills sought to deregulate the agricultural markets for entry of big business by removing restrictions on trading, movement, and storage of agricultural products and by promoting contract farming. The narrative in support of the farm legislations spoke of another objective, namely, making India an agricultural export hub. This objective marks a fundamental shift in the policy orientation of the sector, as the primary driver for agriculture has always been the realisation of domestic food security and supporting rural livelihood.

Agriculture in India: Weighed down by structural constraints

One of the dismal realities of the agricultural sector in post-Independent India has been that it never experienced a high-growth phase unlike the non-agricultural economy. The highest decadal growth (compound annual growth rate or CAGR) for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agricultural growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased between from the 1980s to the 2000s, before declining in the previous decade. This shows clearly that farming did not benefit from the process of economic reforms in the country.

The slowdown in agricultural growth between the 1950s and the 1970s, coincided with a sharp rise in population growth. The decadal growth in population was 13.3% in 1951, but in the following two decades, it rose to 21.6% and 24.8%. The intersection of these two factors created significant levels of food insecurity, which manifested in growing import dependence on food grains. The phenomenon was also referred to as ship-to-mouth existence, describing the eagerness with which the country's citizens waited for the PL 480 shipments from the United States to land at India's ports, for this alone could have helped limit starvation. It was this crisis which led to the central government launching of the Green Revolution in the late-1960s.

The gains from the Green Revolution were realised in the entire country only in the 1980s when agriculture overcame its low growth syndrome; registering the highest decadal

growth of 3.5 % (the 2000s witnessed a similar level of growth). However, as shown in Chart 1, the gains through higher growth stagnated quickly. This trend in production has a direct bearing on stability of farm incomes.

Indian agriculture was able to escape the throes of crisis in the mid-1960s through the technological interventions made through the introduction of the Green Revolution. The benefits of new technology in terms of higher output growth could not be reaped until the 1980s, and also that this growth could not be sustained in the following decades. This was largely because the spread of the green revolution technology was tardy and, therefore, did not extend the benefits, as described below.

One of the major factors was inadequate sources of irrigation more than five decades after the Green Revolution technology was introduced. In 2019-20, 53% of the gross cropped area under principal crops was irrigated, increasing only by 6% in nearly a decade. The above-mentioned numbers are somewhat deceptive since there is considerable variation among States in the availability of irrigation facilities; some of the major States like Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka were below the national average as regards coverage of irrigated area under principal crops during 2019-20. Of the 36 States and Union Territories for which data were available, in 25 States, coverage of irrigated area under principal crops was lower than the national average.

Over the decades, agriculture has been receiving progressively smaller shares in the country's capital formation. In the 1950s, agriculture's share was nearly a quarter of the country's overall investment; four decades later, the share had halved. Only after five more years, agriculture's share had halved yet again. It was less than 6% in 2018-19, latest period for which data is available.

It narrates a story about the neglect of agriculture since the 1980s, the period in which successive governments have taken far reaching measures to introduce economic reforms. Clearly, none of the governments were inclined to initiate measures that could contribute to the improvement in productivity of the sector supporting the largest share of the country's workforce. To be sure, one could argue that the decline in agriculture's share in overall investment is a reflection of its declining share in the economy itself. The simple ratio of agriculture's share in investment and its share in GDP, shows that there has

Agricultural Growth Never Took-off in India

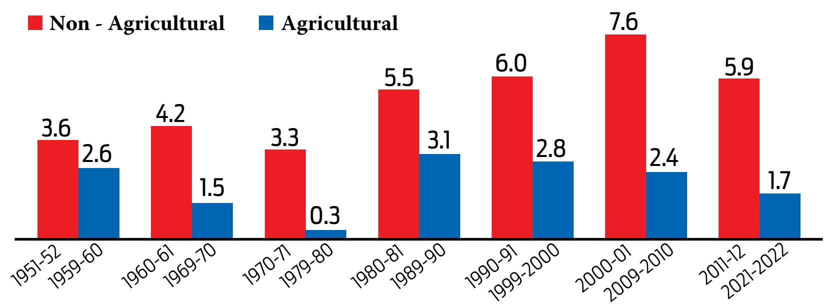

Note: 2010-11 to 2018-19 calculations are for GVA numbers from 2011-12 series, rest are GDP numbers from the 2004-05 series. Agriculture includes agriculture for 2004-05 series and crops and livestock for 2011-12 series. All figures in constant prices

Source: National Accounts Statistics

been a disproportionate fall in agricultural investment in the country since the 1980s. While this ratio has always been less than one, which implies that agriculture is an investment-deficient sector, it has fallen further since the 1980s.

If inadequate investment, including in critical infrastructure, was adversely impacting agricultural productivity, the farming community faced yet another serious obstacle in that the market was not providing them the desired level of incentives. This can be gauged from the behaviour of barter terms of trade between agriculture and non-agricultural sectors. Agriculture has faced adverse terms of trade during the decade of the 1980s and again for most years since the mid-2000s. In the 1990s, when the terms of trade had turned in its favour there was an upward trend only in the first half of the decade, following which a declining trend had set in.

One could argue that unlike in the non-farm economy, there is a limit to agricultural growth in any economy. Once all the land has been brought under cultivation and is being cultivated with the maximum possible intensity and the best possible technology, production cannot increase anymore. The evidence at hand suggests that India is still far from hitting this frontier. This is best seen from the fact that although India is among the top producers of all major food crops, it is considerably behind the countries having the highest levels of yields. The tables, providing details for wheat and rice, India's major food crops, show that not only have India's yields in wheat and rice been considerably lower than those of the countries on top of the yield charts in recent years, but these have

This can be gauged from the behaviour of barter terms of trade between agriculture and non-agri sectors. Agriculture has faced adverse terms of trade during the decade of the 1980s and again for most years since the mid-2000s.

Agriculture's problem of under-investment in India

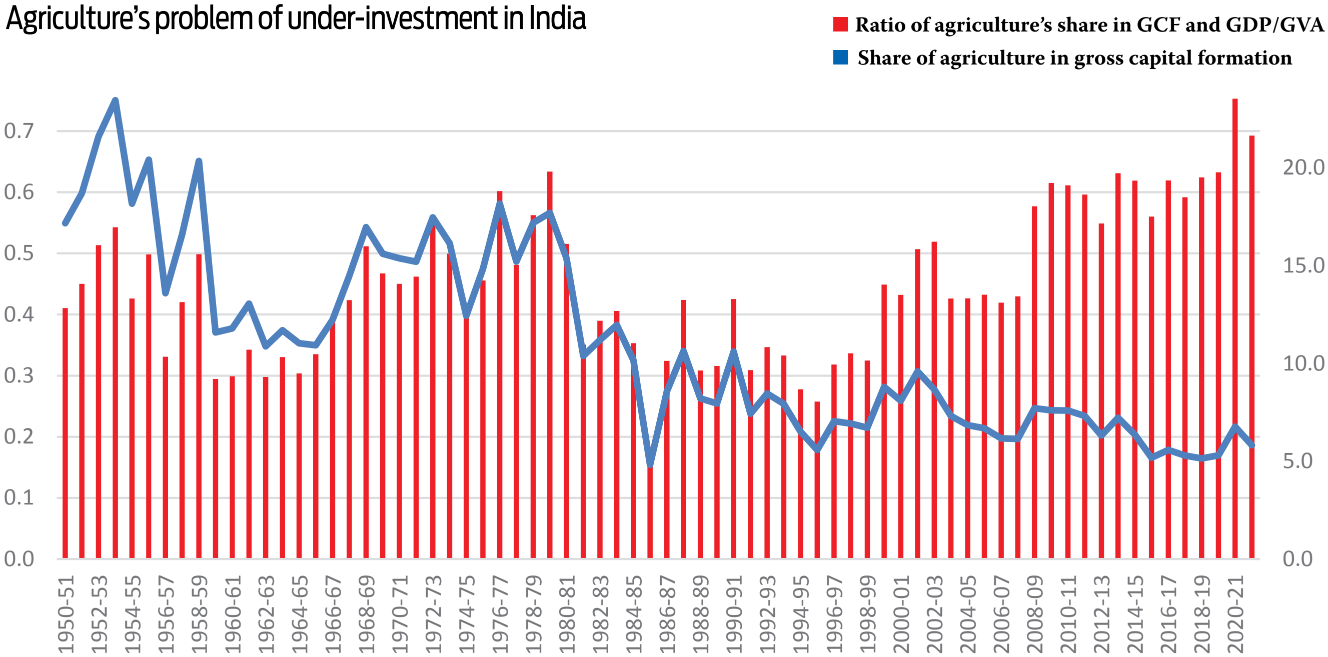

For 2004-05 series agriculture GDP and capital formation share for agriculture has been taken. For 2011-12 series Gross Value Added and gross capital formation have been taken

Source: National Accounts Statistics

also been growing relatively slowly. Thus, India's wheat yield in 2021 was more than three times lower than that of the country showing the highest yield, and in rice, the gap was slightly lower.

An otherwise disappointing headline numbers on productivity of food crops in India appear quite different when analysed regionally. A comparison of state-wise food grains yield brings this out clearly. Yields in Punjab and Haryana have, historically, been significantly higher than the all-India average. In the 2021-22 latest period for which data are available, food grain yields in Punjab and Haryana were 4.2 tonnes/hectare and 3.9 tonnes/hectare as compared to just 2.4 tonnes/hectare at the all-India level. A further concern is that the two best performing states in terms of yields have been witnessing downward trends since the later half of the previous decade.

It is pertinent to note here that all but 10 states in the country recorded food grain yields that are more than the national average. In 2021-22, these states accounted for nearly 56.5% of the production of food grains and less than 44% of the area under production.

All but 10 states in the country recorded food grain yields that are more than the national average. In 2021-22, these states accounted for nearly 56.5% of the production of food grains and less than 44% of the area under production.

Need for a Policy Reset in Agriculture

The most enduring set of policies that the government has adopted for the development of the agricultural sector since the mid-1960s have been an extensive subsidies regime. This followed the adoption of the "Green Revolution" strategy, which emphasized the necessity of providing the farmers with a "complete "package of practices" for increasing yields, including "credit, modern inputs and price incentives" in the form of assurance of MSP by the government for the major crops. At the same time, India maintained high levels of import tariffs, which it did to protect small farmers from import threats as well as to support its fragile balance of payments. However, the sector supporting the largest share of the workforce remained starved of investments.

With unabated increase in farm subsidies, two questions have repeatedly been asked. The first is the ability of the increasingly fragile government finances to support them. The second, and a more vexed set of questions have been asked in the World Trade Organisation. The subsidies disciplines introduced by the Agreement on Agriculture (AoA) stipulate that input subsidies, MSP, and a component of the expenditure incurred for operating the public distribution system (PDS) taken together, cannot exceed 10%

Wheat Yields: Top 10 countries and India

(tonnes/hectare)

Countries	2010	2015	2020	2021
Ireland	8.60	10.67	7.77	10.08
New Zealand	8.12	8.67	9.93	9.71
Netherlands	8.91	9.13	8.56	8.02
United Kingdom	7.67	8.98	6.96	7.81
Belgium	8.83	10.02	8.95	7.79
Denmark	6.63	7.95	8.10	7.53
Germany	7.21	8.09	7.82	7.30
France	7.04	7.80	6.68	6.93
Zambia	6.31	6.88	7.37	6.79
Saudi Arabia	6.15	6.14	6.38	6.70
India	2.84	2.75	3.44	3.47

Source: FAOSTAT

Rice Yields: Top 10 countries and India

(tonnes/hectare)

Rank in 2022	Countries	2010	2015	2020	2021
1	Egypt	9.4	9.4	9.6	10.2
2	Uruguay	7.1	8.7	8.6	9.4
3	Australia	10.4	9.9	10.0	9.4
4	USA	7.5	8.4	8.5	8.6
5	Peru	7.3	7.9	8.2	8.3
6	Türkiye	8.7	7.9	7.8	7.7
7	Japan	6.5	6.9	7.2	7.5
8	Spain	7.6	7.8	7.2	7.3
9	Kenya	4.2	4.0	6.4	7.3
10	Argentina	5.8	6.7	6.6	7.3
48	India	3.4	3.6	4.1	4.2

Source: FAOSTAT

of India's value of agricultural production. Besides, subsidies granted to individual crops also cannot exceed 10% of their value of production.

Several WTO members, including the United States, Canada, Australia, and the European Union, have argued that India has been violating its subsidy commitments in respect of several crops. In a significant submission to the Committee on Agriculture in 2018, the United States had claimed that the MSP that India provides to rice was consistently above 70% of its value of production since 2010-11 and that for wheat, this figure was above 60% during the same period.

A second challenge facing India's subsidies' regime has emerged from the suggestions made to the government to amend the country's subsidies regime. The most significant of these came from the "High Level Committee on Reorienting the Role and Restructuring of FCI". The Committee had recommended in its report in 2015 that India should provide direct income transfers to farmers, on which the AoA does not impose any spending limits by the government. It may be mentioned that direct income transfers have at least two implementation problems. First, three types of cultivators are engaged in agriculture, namely, owner cultivators, tenants/sharecroppers, and landless labour, and therefore payment of subsidies can be a vexed issue. Secondly, given the large number of holdings (over 146 million in 2015-16), implementation of direct income transfer could be a strain on the administration.

The above discussion makes it clear that agricultural policy in India needs a serious re-think. There is an urgent need to engage with the farming communities for adopting a comprehensive set of policies, which include setting up of farmer-friendly institutions in order to improve the economic viability of the sector. This can happen only if there is a mindset change in the government, above all, the willingness to develop agriculture as a national priority. The government needs to recognise that most farmers do not regard agriculture as a viable occupation, a situation that can only be altered through enhanced investments in physical infrastructure and creating institutions that respond to the needs of the low income and resource poor farmers. If, according to the government's own assessment 99.43% of farm holdings are held by this group of farmers, the crisis faced by Indian agriculture is truly monumental. Rw

There is an urgent need to engage with the farming communities for adopting a comprehensive set of policies, which include setting up of farmer-friendly institutions in order to improve the economic viability of the sector.

फोटो फीचर / ग्रामीण भारत का एजेंडा

रूरल वॉयस और सॉक्रेटस ने देश के पांच राज्यों में छह माह के दौरान पांच सम्मेलन आयोजित किए। इनमें 60 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये सम्मेलन भुवनेश्वर (ओडिशा), कोयंबटूर (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) और शिलांग (मेघालय) में हुए। ये राज्य सांस्कृतिक, आर्थिक, कृषि-जलवायु और राजनीतिक रूप से भिन्न हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण भारत की वर्तमान मनःस्थिति को समझना और साथ ही वहां के मुद्दों पर चर्चा शुरू करना था। इन चर्चाओं में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं, आशाओं और उज्जवल भविष्य के सपनों के बारे में बात की।

1

2

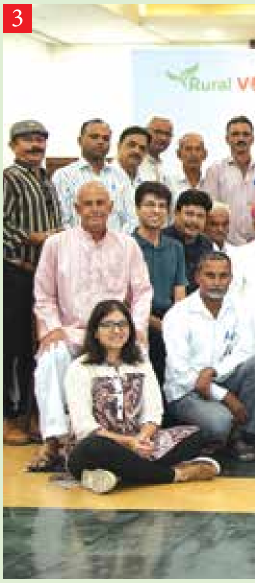

3

4

5

फोटो परिचय

1. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एजेंडा फॉर रूरल इंडिया में शामिल प्रतिभागी।

2. ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एजेंडा फॉर रूरल इंडिया में शामिल प्रतिभागी।

3. राजस्थान के जोधपुर में आयोजित एजेंडा फॉर रूरल इंडिया में शामिल प्रतिभागी।

4. तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित एजेंडा फॉर रूरल इंडिया में शामिल प्रतिभागी।

5. मेघालय के शिलांग में आयोजित एजेंडा फॉर रूरल इंडिया में शामिल प्रतिभागी।

फोटो फीचर
रुरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2022

1

2

3

6

7

4

5

8

9

1. रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवॉर्ड्स 2022 कार्यक्रम की दीप प्रज्जवलन के साथ शुरुआत करते अतिथिगण।

2. कॉन्क्लेव में रूरल वॉयस के चुनिंदा लेखों के संकलन को रिलीज करते हुए (बाएं से) अमूल के तत्कालीन एमडी आर.एस. सोढ़ी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.एन. ठाकुर, इंडियन पोटाश लिमिटेड के एमडी डॉ. पी.एस. गहलोत, भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़, कृभको चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह, रूरल वॉयस के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डीजी संदीप कुमार नायक, आईईजी में प्रो. सी.एस.सी. शेखर और पूर्व कृषि सचिव प्रो. सिराज हुसैन।

3. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान (बाएं से दूसरे), इफको के एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी और नेकॉफ के चेयरमैन राम इकबाल सिंह।

4. कॉन्क्लेव में शामिल प्रतिभागी और अतिथिगण।

5. कॉन्क्लेव के एक पैनल में चर्चा करते पैनलिस्ट

6-9. रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवॉर्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेता।

फोटो परिचय

1-3. कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के बजट पर आयोजित बजट चर्चा 2023-24 कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

4. प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का अवलोकन करते राज्यसभा के पूर्व सदस्य और जदयू नेता के सी त्यागी।

5. पैनल चर्चा में शामिल (बांए से दांए) सॉक्रेटस के डायरेक्टर प्रचुर गोयल, हरवीर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद के.सी. त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली और बीआरएस के लोकसभा सांसद नम्मा नागेश्वर राव।

फोटो फीचर / कृषि में डिजिटलाइजेशन पर किसान संगठनों के साथ वर्कशॉप

फोटो परिचय

रूरल वॉयस, भारत कृषक समाज, आईटी फॉर चेंज, अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), किसान स्वराज ने संयुक्त रूप से कृषि के डिजिटलीकरण के मुद्दे पर 21-22 नवंबर, 2022 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया। इस वर्कशाप में देश के सभी प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। यहां पर इस वर्कशाप के विभिन्न सत्र कैमरे की नजर से।

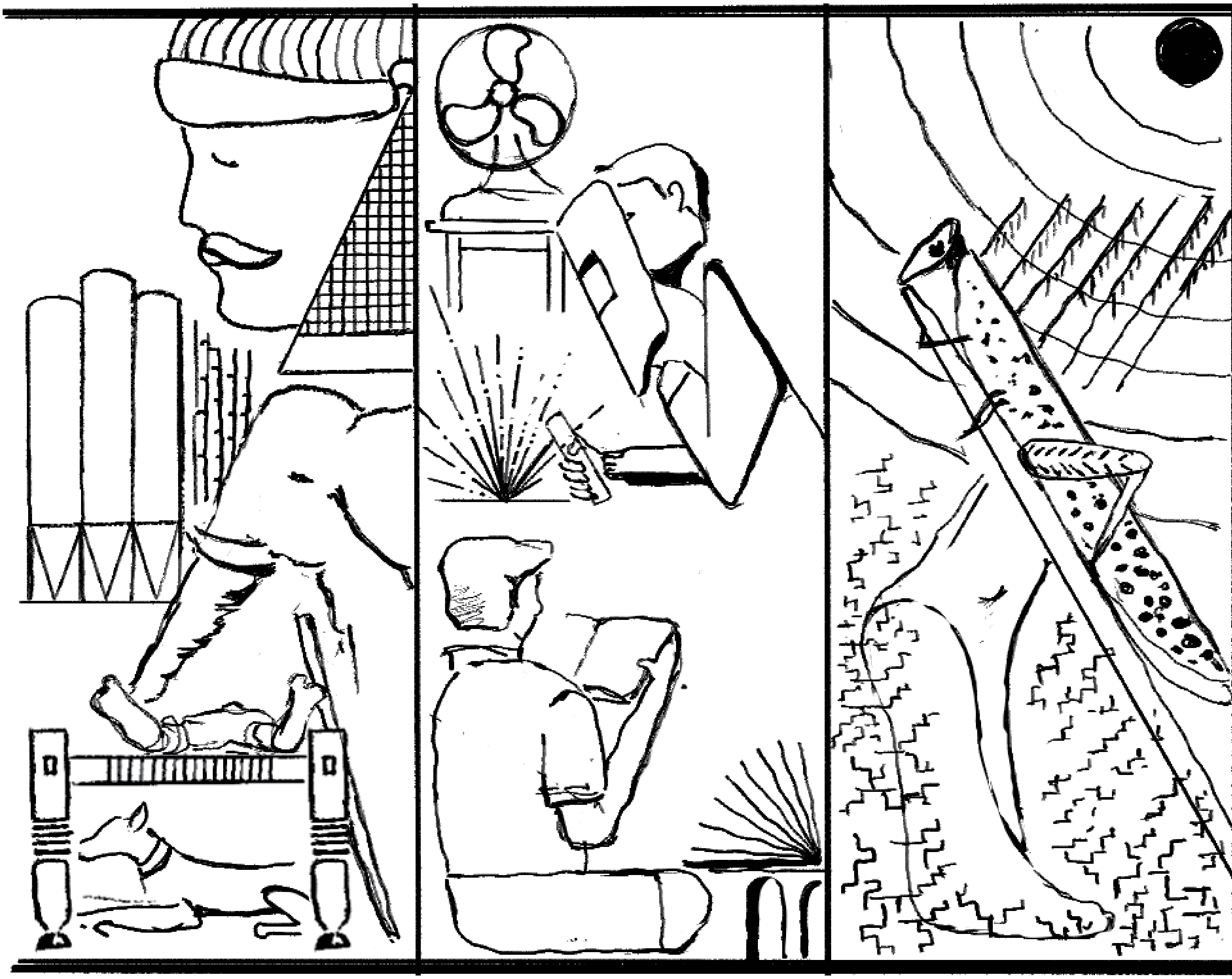

कृषि का हाथ थामने की दरकार

ग्रामीण भारत के लिए अस्तित्व का संकट

सभी इलस्ट्रेशन: आलोक श्रीवास्तव, सॉफ्टेस

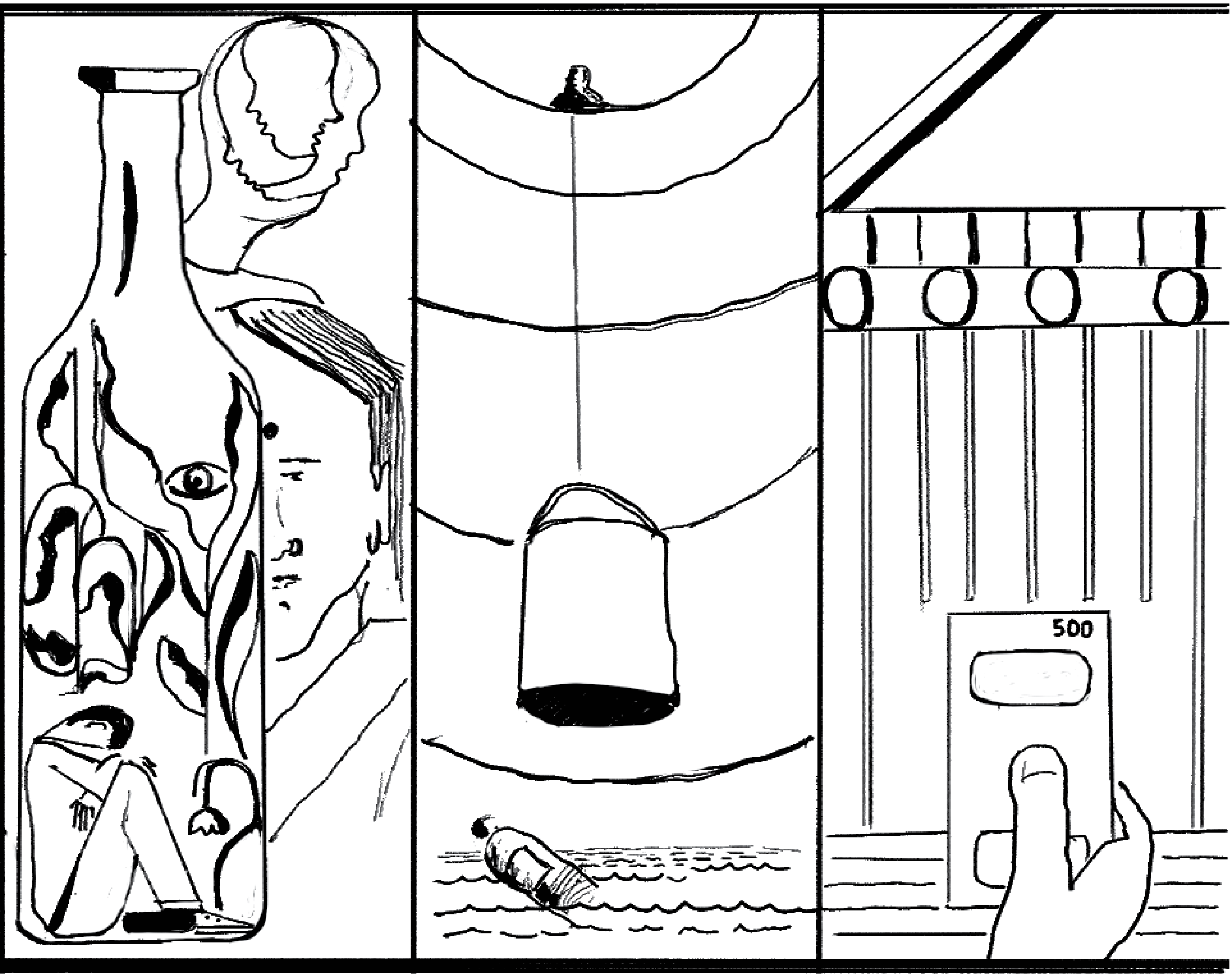

हरवीर सिंह | प्रचुर गोयल

भारतीय कृषि अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और पर्यावरण की चुनौतियों से घिरा है। हालांकि सड़क और स्वच्छता जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल फोन के क्षेत्र में स्पष्ट सुधार भी हुए हैं। आप पूछ सकते हैं, तो क्या यह विरोधाभास है? जवाब है, 'हां'। इस जवाब का आधार है किसान संगठनों, सिविल सोसायटी, नीति निर्माताओं और मार्केट इंटरमीडियरी जैसे स्टेकहोल्डर के साथ छह महीने तक हुई चर्चा। यह चर्चा नई दिल्ली या अन्य महानगरों में नहीं, बल्कि विविध कृषि-जलवायु, आर्थिक शक्ति और फसल पैटर्न वाले पांच राज्यों के छोटे शहरों में हुई। हमारे निष्कर्ष आपको कृषि की हकीकत से अवगत कराएंगे। यह नई दिल्ली अथवा किसी प्रदेश की राजधानी में बैठे ब्यूरोक्रेट के आकलन के विपरीत हो सकता है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विचार को प्रदर्शित करता है, जिसे एक प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप और राजनीतिक मदद की दरकार है।

अगर आप नई दिल्ली में किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से बात कीजिए तो वे आपको बताएंगे कि नई सड़कों के निर्माण, बिजली कनेक्शन, घर और टॉयलेट बनाने जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फोन अब आम हो गए हैं तथा वहां हर तरह के सामान और सेवाओं का बाजार बढ़ रहा है।

वास्तव में ग्रामीण भारत ने अनेक बदलाव देखे हैं। सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विभिन्न सेवाओं तक पहुंच

मुजफ्फरनगर में आयोजित ग्रामीण भारत का एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

निश्चित रूप से बेहतर हुई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं गांव और छोटे शहरों में रहने वालों की बढ़ती आकांक्षाओं की ओर भी इशारा करती हैं। उनकी आकांक्षाएं शहर वासियों के समान हैं, भले ही ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र 'कृषि' के सामने अपने हाल पर छोड़ दिए जाने का जोखिम है। हालांकि ग्रामीण भारत की आकांक्षाएं सही और अमल में लाने योग्य हैं। बशर्ते इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तथा भ्रष्टाचार की समस्या के साथ प्रभावी तरीके से निपटा जाए।

देशभर में हमारी चर्चा में कृषि क्षेत्र के लिए जो जोखिम उभर कर सामने आए, उनमें कर्ज का बढ़ता स्तर, श्रमिकों की मजदूरी समेत बढ़ती इनपुट लागत, नकली कीटनाशकों की बेरोकटोक बिक्री, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, उपज की उचित कीमत न मिलना और राजनीतिक उदासीनता शामिल हैं।

राजस्थान के जोधपुर में बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर तथा अन्य जिलों से आए लोगों से जब हमने सवाल किया कि "2030 में आपका गांव का सपना क्या है," तो उनका जवाब था, "प्लास्टिक मुक्त, पर्यावरण युक्त, नशा मुक्त, वाई-फाई युक्त। परिवहन सुविधा सहित, प्रदूषण रहित, 24 घंटे बिजली और एक स्टेडियम हो जिसमें लड़के, लड़कियां, महिलाएं रोज दौड़ें। आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हों और कृषि संबंधी जानकारी विज्ञान के आधार पर मिले।"

एक अन्य प्रतिभागी ने कहा, *"हमारे गांव हरे-भरे हों, जल स्रोत पर्याप्त और शुद्ध हो। साफ-सुथरे गांव हों, प्लास्टिक मुक्त हो, विद्यालयों में लड़के-लड़कियों की संख्या खूब बड़ी हो, खास कर सरकारी संस्थानों में।"*

गांवों में रहने वालों का एक सपना है। वे अपने गांव में शहरों के समान सुविधाएं चाहते हैं। वे भी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि की उम्मीद रखते हैं जिनसे जीवन आसान हो। लेकिन शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त ऐसा गांव जहां सबके पास काम हो, हकीकत से काफी दूर है। ग्राम्य जीवन काफी बदल गया है। अनेक ग्रामीण क्षेत्र अब भी निरंतर बिजली, अच्छी सड़कें, साफ पानी, क्वालिटी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं से महरूम हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं तथा अधिकतर के लिए खेती मुनाफे का काम नहीं रह गया है। ना आमदनी के लिहाज से, ना सामाजिक स्टेटस के लिहाज से। यही नहीं, ग्राम वासी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जीवन शैली से पनपने वाली बीमारियों, बेरोजगारी, ड्रग्स जैसी नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक समय यह समस्याएं शहरों की हुआ करती थीं, गांवों की नहीं।

मीडिया संस्थान रूरल वॉयस, जो रूरल वर्ल्ड का साझा पब्लिकेशन भी है, और गैर-लाभकारी संस्था सॉक्रेटस ने ग्रामीण भारत के नागरिकों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को सुनने-समझने के लिए उनके साथ अपनी तरह की पहली अखिल भारतीय सम्मेलन श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों को अक्सर मुख्यधारा के विमर्श में हाशिए पर रखा जाता है। खबरों में किसान आत्महत्या, मिलावटी शराब या मध्याह्न भोजन योजना पर बहस को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र की बातों को शायद ही जगह मिलती है। ऐसे देश में जहां आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी है, यह बेमेल बड़ा अविश्वसनीय लगता है। दूसरा कारण इंटरनेट और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ ग्रामीण परिदृश्य में पिछले 15 वर्षों में हुए बड़े बदलावों से संबंधित है।

इन सम्मेलनों के माध्यम से, सॉक्रेटस और रूरल वॉयस का उद्देश्य ग्रामीण भारत की वर्तमान मनःस्थिति को समझना और वहां उठाए

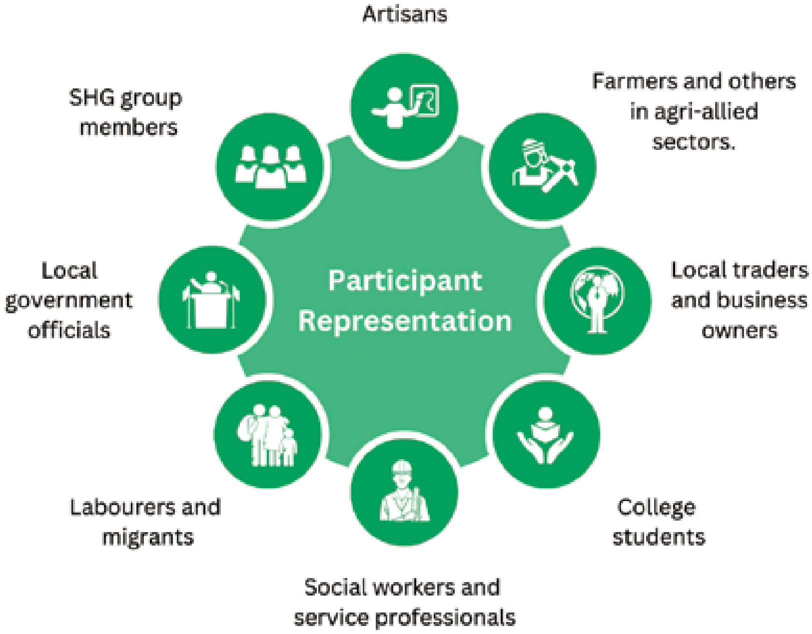

ग्राफिक्स: नितिन वेमुला, सॉक्रेटस

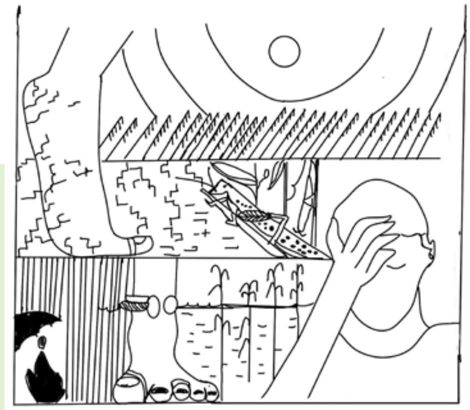

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट

अद्रिजा चौधुरी, सॉक्रेटस

"आजकल हम दिन में चार अलग मौसम का अनुभव करते हैं। मौसम में इस बदलाव ने फसल चक्र और उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है"- पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय का एक किसान।

देश के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ हमारी बातचीत ने हमारे सबसे भयावह डर की पुष्टि की कि जलवायु परिवर्तन का असर वहां दिखने लगा है। अधिकांश प्रतिभागी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने जलवायु परिवर्तन से फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बात की। उत्तर प्रदेश के किसानों ने बताया कि कैसे असामान्य रूप से ज्यादा तापमान ने गेहूं, आम और गन्ने की फसल को प्रभावित किया है। मार्च में बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की पकी हुई फसल भी बर्बाद हो गई। राजस्थान में अनियमित बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ। ओडिशा के प्रतिभागियों के मुताबिक, असामान्य रूप से भारी वर्षा ने उनकी फसलों को नष्ट कर दिया और मिट्टी की उपजाऊ सतह का क्षरण हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से ओडिशा के तटीय इलाके के लोग प्रभावित हुए। मेघालय में सीढ़ीदार खेतों, खेतों की मेड़बंदी और खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाने जैसे उपायों के बावजूद किसान भारी वर्षा के कारण मिट्टी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। चूना पत्थर खनन और वनों की कटाई जैसी गतिविधियों ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है।

अनियमित बारिश और असामान्य मौसम अप्रत्याशित समय पर कीटों के प्रकोप का कारण भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गेहूं, आम, मूंग और गन्ना जैसी फसलें साल के अलग-अलग समय में कीटों से प्रभावित रहीं। मेघालय में महिला किसान विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रकोप से फसलों के नुकसान से परेशान थीं जो उनकी मक्का, सब्जी और फलों को प्रभावित कर रहे हैं। जो फसलें पहले कीटों से अप्रभावित थीं, जैसे अदरक, केला और रागी, वे कटवर्म जैसे नए कीटों से प्रभावित हो रही थीं।

कई प्रतिभागियों ने प्राकृतिक खेती को इस संकट के समाधान के रूप में देखा और आशा जताई कि सरकार टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के हमलों के दौरान प्रभावी फसल बीमा जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रतिभागियों के साथ बातचीत में यह आम धारणा भी गलत साबित हो गई कि पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से एक शहरी समस्या है। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने आसपास की चीनी मिलों और दूसरे उद्योगों से नहरों और अन्य जल स्रोतों में प्रदूषण की शिकायत की। ऐसा माना जाता है कि भोजन पर रासायनिक अवशेषों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसकी गूंज जोधपुर में भी सुनाई दी। वहां प्रतिभागियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के बढ़ते मामलों को कृषि में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से जोड़ा। तमिलनाडु में ग्रामीणों ने बताया कि कैसे उद्योग जल स्रोतों में अपशिष्ट और सीवेज डंप कर रहे हैं और लीचिंग से भूजल दूषित हो रहा है।

हमारे प्रतिभागियों को न केवल पर्यावरणीय मुद्दों का पता था, वे यह भी जानते थे कि वे जनप्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं। कोयम्बटूर में प्रतिभागियों ने एक अधिक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संयंत्र और हर गांव में बेहतर खाद्य उत्पाद क्षेत्र बनाये जाने का आह्वान किया। भुवनेश्वर के प्रतिभागियों ने कहा कि जागरूकता बढ़ाना, प्लास्टिक कचरे को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हैं। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने पंचायत भूमि पर पेड़ लगाने और गांव के तालाबों, जंगलों के संरक्षण का प्रस्ताव रखा।

हर जगह के ग्रामीण शहरी लोगों की तरह ही जागरूक युक्त थे। उनका रोजमर्रा का जीवन पर्यावरण पर अधिक निर्भर है, इसलिए उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अधिक तीव्रता से महसूस किया।

गए मुद्दों पर चर्चा शुरू करना था। इस लेख का उद्देश्य उन लोगों के विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से प्रतिबिंबित करना है जिनसे हमने उनके जीवन, उनकी समस्याओं, आशाओं और उज्जवल भविष्य के सपनों के बारे में बात की।

हमारे इस कार्य में देश के 5 राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। यह 5 क्षेत्रों में विविधता को दिखाने का प्रयास है- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व। हमने उत्तर-पूर्व पर विशेष ध्यान दिया है। यहां की कम आबादी, विशिष्ट सांस्कृतिक विविधता और दूरी को देखते हुए, इसे अक्सर राष्ट्रीय संवाद से बाहर रखा जाता है। हालांकि, हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत विशाल और विविधतापूर्ण देश है। परंतु हम हर क्षेत्र या व्यक्ति के दृष्टिकोण को शामिल नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने भारत के हर क्षेत्र से पांच राज्यों को चुना। प्रत्येक राज्य में हमने एक स्थानीय संगठन के साथ साझेदारी की, जिसने वहां की आबादी का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में हमारी मदद की।

हमारे सम्मेलन पांच जगहों पर थे। प्रत्येक स्थान पर हमने आसपास के 10-12 जिलों के लोगों के साथ बैठक की। ये स्थान थे भुवनेश्वर (ओडिशा), कोयंबटूर (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) और शिलांग (मेघालय)। ये राज्य सांस्कृतिक, आर्थिक, कृषि-जलवायु और राजनीतिक रूप से भिन्न हैं।

हमारे स्थानीय साझेदार थे- ओडिशा में लाइवलीहुड ऑल्टरनेटिव्स इन ओडिशा, तमिलनाडु में टीएनएफपीए (तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन) और एफएमआईएफ (फार्मर्स मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स फेडरेशन), राजस्थान में साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, उत्तर प्रदेश में किसान प्रतिनिधि उमेश पंवार, नरेंद्र पाल वर्मा व धर्मेंद्र मलिक और मेघालय में नेसफास (नॉर्थ ईस्ट सोसायटी फॉर एग्रोइकोलॉजी सपोर्ट)। उनकी मदद से हम 60 जिलों से 300 से अधिक प्रतिभागियों को साथ लाने में सफल रहे।

सम्मेलन में विभिन्न पेशे के लोगों ने भाग लिया। उनमें किसान, स्थानीय व्यापारी और व्यवसायी, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य,

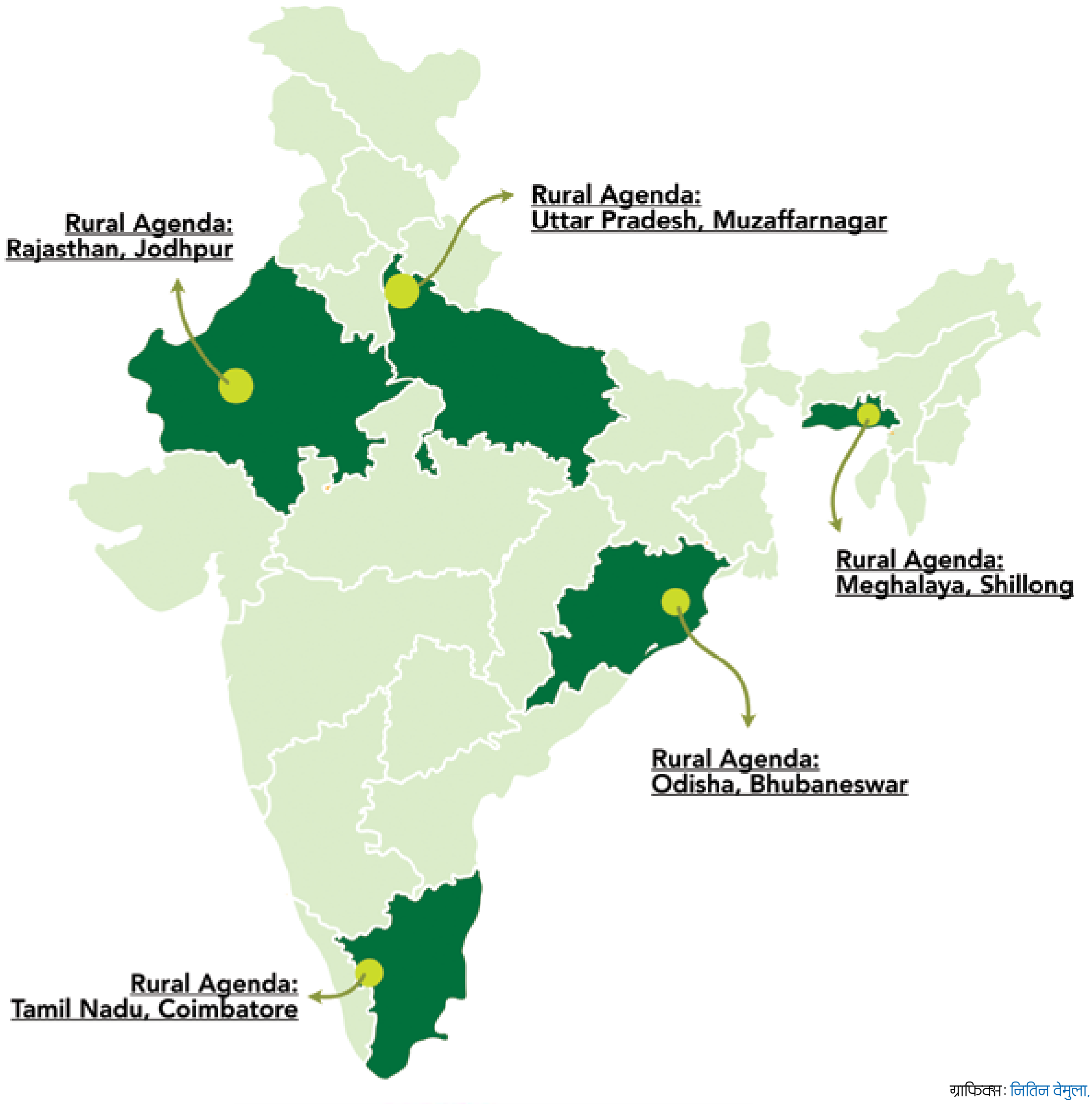

ग्राफिक्सः नितिन वेमुला, सॉक्रेटस

स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारी अधिकारी, मजदूर और प्रवासी, कॉलेज छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा क्षेत्र के पेशेवर शामिल थे। सम्मेलन में यह सुनिश्चित भी किया गया कि सभी लिंग और सामाजिक समूहों के लोग उपस्थित हों।

कृषि के सामने आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण संबंधी अस्तित्व का संकट

"किसान तो खुशहाल है ही नहीं, 100% किसान कर्जदार हुआ बैठा है।" - मुजफ्फरनगर का एक प्रतिभागी।

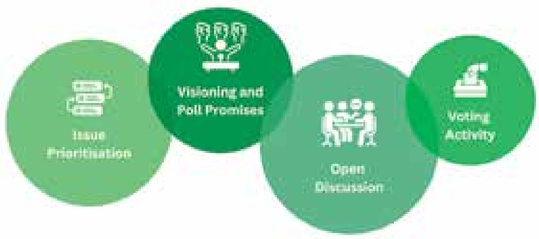

ग्राफिक्सः नितिन वेमुला, सॉक्रेटस

बीज से लेकर मजदूरी और ईंधन से लेकर कीटनाशक तक सभी इनपुट महंगे हो गए हैं। इन्हें बाजार से ही खरीदना पड़ता है। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग साल दर साल बढ़ रहा है। किसानों को उनकी उपज की सही और समय पर कीमत नहीं मिल रही है। शामली के गन्ना किसानों की शिकायत है कि वर्षों से उनका भुगतान लंबित है। ओडिशा के एक सब्जी किसान का कहना है कि दूर बाजार तक पहुंचने के लिए उसके पास परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। यही शिकायत मेघालय के किसानों की है। तमिलनाडु के किसानों ने सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की बात कही।

एक तरफ खेती की लागत बढ़ी है तो दूसरी तरफ इसमें जोखिम भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन से मौसम असमान हो गया है जिसकी वजह से हीट वेव, असमय बारिश और कीटों के हमले होते हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अब अभिजात वर्ग से निकलकर सबके बीच आ गई

ग्राफिक्स: नितिन वेमुला, सॉक्रेटस

Uttar Pradesh

Highlights

- Stray Cattle
- Overuse of fertilisers
- Effect of climate change on crops

Participant Representation

Baghpat, Bijnor, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli

Rajasthan

Highlights

- Overuse of fertilisers and pesticides,
- Lack of water facilities for drinking and irrigation,
- High unemployment

Participant Representation

Balotra, Barmer, Falodi, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Nagaur, Newra, Pali, Sanchore, Sikar, Udaipur

Odisha

Highlights

- Farmer-animal conflict,
- lack of water facilities for drinking and irrigation,
- Lack of good crop prices

Participant Representation

Angul, Balangir, Baleswar, Bhubaneswar, Cuttack, Deograh, Dhenkanal, Gajapati, Ganjan, Jagatsinghpur, Jaipur, Kandhamal,

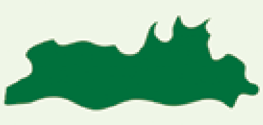

Meghalaya

Highlights

- Lack of good road connectivity,
- Effect of climate change on crops,
- Poor Healthcare,
- Poor Infrastructure

Participant Representation

East Garo Hills, East Jaintia Hills, East Khasi Hills, Eastern west Khasi Hills, Ri Bhoi, West Garo Hills, West Jaintia Hills, South Khasi

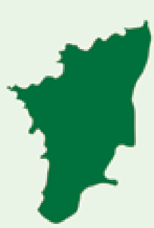

Tamil Nadu

Highlights

- Farmer-animal conflict,
- corruption,
- Lack of crop insurance for farmers,
- Degradation of water resources (lakes, rivers, dams)

Participant Representation

Coimbatore, Dharmapuri Dindigul, Erode, Namakkal, Nilgiris, Salem, Thirunelveli, Tiruppur

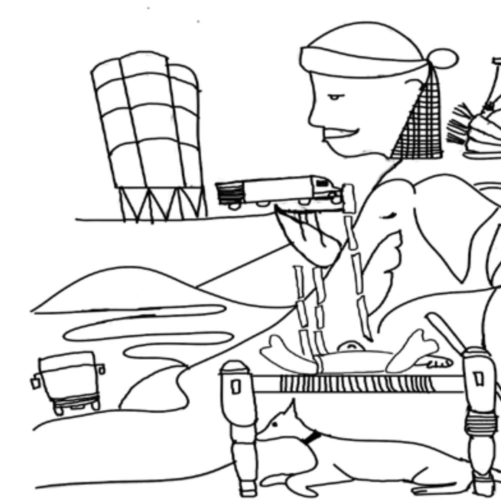

कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें

अद्रिजा चौधुरी, सॉक्रेटस

ग्रामीण भारत पर कोई भी चर्चा कृषि पर बातचीत के बिना पूरी नहीं हो सकती। देश भर में ग्रामीणों के साथ हमारी बैठकों में प्रतिभागियों में से लगभग 60 फीसदी किसान थे। पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों की चिंताओं, आशाओं और सपनों में स्पष्ट रूप से दिख रही थी। हालांकि, उनके द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे नए नहीं थे, फिर भी यह किसानों की धारणाओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए काफी हैं।

किसानों ने बताया कि केवल कृषि आय से गुजारा करना लगभग असंभव होता जा रहा है। फसलों की कीमतें लागत के अनुपात में कम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक युवा किसान ने हमें बताया, "उर्वरक और कीटनाशक सहित हर चीज महंगी होती जा रही है, हम हर तरफ से दबाव में हैं।" उत्तर भारत की "गन्ना बेल्ट" का हिस्सा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में प्रतिभागियों ने गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) न बढ़ने और चीनी मिलों से भुगतान में देरी को एक बड़ी समस्या के रूप में उठाया। यहां के किसानों ने कीटनाशकों, उर्वरकों, बीज और मजदूरी की लागत सहित कृषि इनपुट की बढ़ती लागत की भी शिकायत की। इस अपेक्षाकृत समृद्ध कृषि क्षेत्र में भी किसानों को खेती जारी रखने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ओडिशा के किसानों का मानना था कि फसल की कीमतें लाभकारी नहीं हैं। केंद्रपाड़ा जिले के एक किसान ने कहा, "किसानों को मिलने वाली कम कीमत का मुख्य कारण गोदामों और कोल्ड स्टोरेज जैसी भंडारण सुविधाओं की कमी है।" अधिकांश किसानों को अपनी उपज सीधे अपने खेतों-खलिहानों पर ही स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि कैसे फसल की कीमतें बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में वे असमर्थ हैं। शिलांग में भी हमने यही कहानी सुनी- खराब सड़क संपर्क, भंडारण सुविधाओं की कमी और देरी से भुगतान। कोयंबटूर के किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बहुत कम है और इसे किसानों को खुद तय करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि तमिलनाडु में आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों, जैसे चाय, कॉफी, सब्जियां और मसालों का भी एमएसपी तय किया जाना चाहिए।

हमारे कई सम्मेलनों में प्रतिभागियों की धारणा थी कि अकेले एमएसपी और अच्छी कीमतें कृषि की घटती व्यवहार्यता के मुद्दे का समाधान नहीं कर सकतीं। कई जगह किसानों ने कहा कि सरकारें पीएम-किसान जैसी योजनाओं के तहत सहायता बढ़ाकर उनकी आय सुरक्षित करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए कृषि में मूल्यवर्धित उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों ने महसूस किया कि इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सहकारी समितियों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए।

है। हर जगह इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। चाहे गेहूं या धान हो, आम या गन्ना हो या फिर टमाटर हो, हर फसल पर जलवायु परिवर्तन का असर है और लोग असहाय दिख रहे हैं। मानव और पशु का संघर्ष देश के अलग-अलग हिस्से में अलग रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर नजर आई जिनकी वजह से किसान खेतों में ही सोने के लिए मजबूर हैं। ओडिशा और राजस्थान में भी पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कोयंबटूर के आसपास हाथी जैसे जानवरों का अक्सर किसानों से सामना होता है।

एक प्रतिभागी के अनुसार, *"केमिकल का अत्यधिक प्रयोग गांव में सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण है। केमिकल बहुत ज्यादा है, चाहे वह जमीन में हो, जानवरों में हो, इंसानों में हो, हर जगह केमिकल ही केमिकल है।"*

हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में थे। पंजाब के साथ यह क्षेत्र भी भारत में हरित क्रांति के केंद्र में रहा है। लेकिन यहां भी किसान स्वयं उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल का मुद्दा सामने लेकर आए। इससे पता चलता है कि इनका प्रयोग कितना असंतुलित तरीके से हो रहा है। किसानों का कहना था-

"नकली पेस्टिसाइड आ गई है कोई चेकिंग नहीं है।"

"डीलर ट्रेड में लाला लोग बैठे हैं जिनको एग्रीकल्चर का एबीसीडी भी नहीं पता। वे हमें दवाइयां दे रहे हैं।"

अत्यधिक रसायनों के इस्तेमाल को लेकर आलोचना हर जगह दिखाई दी। आश्चर्यजनक रूप से प्राकृतिक खेती का नैरेटिव लोकप्रिय दिखा। लोगों का कहना था कि रसायनों से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता गिर गई है, फसलों में गंभीर बीमारियां लगने लगी हैं और खर्च भी बढ़ गया है। किसान प्राकृतिक और नियमित खेती के नैरेटिव में फस गए हैं। हर साल होने वाले और कई बार अप्रत्याशित रूप से कीटों के हमले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। खेती को सस्टेनेबल और खाद्य पदार्थों को सेहतमंद बनाने का विचार लगभग हर जगह दिखा, खासकर राजस्थान और ओडिशा में। मुजफ्फरनगर और कोयंबटूर में किसान ज्यादा प्राकृतिक की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन वे पसोपेश में हैं कि यह सफल होगा या नहीं। अनेक लोगों के लिए यह जोखिम बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर समाधान के लिए जो सुझाव आए उनमें नकली कीटनाशकों पर रोक, डीलरों का नियमन, किसानों को कृत्रिम इनपुट के संतुलित इस्तेमाल की जानकारी देना, ऑर्गेनिक खेती अपनाना और प्राकृतिक सॉयल सप्लीमेंट को अपनाना शामिल हैं। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स के एक किसान का कहना था कि किसान होने के नाते उन्हें प्रकृति का ध्यान रखने की जरूरत है, और बदले में प्रकृति उनका ख्याल रखेगी।

आकांक्षाओं और वास्तविकता में अंतर से मजदूरों

यह बात हर जगह सामने आई कि कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी जरूरतमंदों तक इनकी पहुंच में बाधक है। राजस्थान के प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि सरकारी योजनाओं के बारे में सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए। मेघालय के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। ओडिशा के प्रतिभागी मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी या कमी से निराश थे। उनका मानना था कि सरकारी नीतियों के बारे में सही जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रत्येक गांव में जागरूकता समूह बनाए जाने चाहिए। तमिलनाडु में प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विधायकों, नीति निर्माताओं और किसान संघों की मासिक बैठक होनी चाहिए।

एक और मुद्दा लगातार सामने आया वह था रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल। इस बारे में किसानों के बीच जागरूकता का स्तर भी काफी अधिक था। राजस्थान के एक किसान ने बताया, "केमिकल का अत्यधिक इस्तेमाल गांव की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है।" यूपी के किसानों ने बताया कि कैसे केमिकल के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और लोगों की सेहत प्रभावित हुई है। ओडिशा के किसानों ने कहा कि हानिकारक रसायन सभी जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। राजस्थान में यह चिंता जताई गई कि कैसे केमिकल के ज्यादा उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर और अन्य बीमारियां हो रही हैं। इस अहसास से किसानों में प्राकृतिक खेती और टिकाऊ कृषि के महत्व की समझ पैदा हुई है। अधिकांश किसानों का मानना था कि यह आगे बढ़ने का सही रास्ता। किसानों ने सरकारों से अपने गांवों में मासिक जागरूकता बैठकें आयोजित करने, प्रमाणन योजनाओं को सरल बनाने और रियायती कीमतों पर जैविक इनपुट की आपूर्ति करने का आह्वान किया।

किसानों ने मानव-पशु संघर्ष की चिंता को भी प्राथमिकता दी। यूपी में आवारा पशुओं के आतंक के कारण किसान कई तरह की फसल बोने से भी डरते हैं। यह मुद्दा मुजफ्फरनगर में हमारे प्रतिभागियों के बीच सबसे अधिक गूंजा। किसानों ने इसके लिए कई समाधान सुझाए। इनमें हर गांव में पशु आश्रय स्थल बनाने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने से लेकर किसानों को बूढ़े मवेशियों की देखभाल के लिए मासिक भुगतान, पशु व्यापार को वैध बनाना शामिल हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और मेघालय में आसपास के जंगलों से जंगली जानवर खेतों में घुस जाते हैं। तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले के एक किसान ने बताया, "पश्चिमी घाट से सटे इलाके में तेनकासी से सत्यमंगलम वन प्रभाग तक हिरणों, सूअरों और मोरों के उपद्रव के कारण बाजरा की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं।" नीलगिरि के एक किसान अपने क्षेत्र में हुए नुकसान का एक फोटो एलबम भी लेकर आए थे। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला- बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को मवेशी और पशु संरक्षण पर सरकारी नीतियों के साथ-साथ शहरीकरण के कारण वन क्षेत्रों के विस्तार पर दबाव से जोड़ा जा सकता है।

सिंचाई के लिए पानी हर जगह चिंता का एक विषय था, विशेष रूप से ओडिशा और राजस्थान में जो विपरीत कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ओडिशा में बढ़ती अनियमित वर्षा का प्रभाव खराब सिंचाई सुविधाओं के कारण अधिक महसूस किया गया। राजस्थान में भूजल के घटते स्तर ने खेती के लिए अच्छी सिंचाई सुविधाओं को जरूरी बना दिया है। मेघालय में किसानों को सर्दियों के मौसम में पानी की कमी झेलनी पड़ती है।

की कमी, बेरोजगारी और ड्रग्स की समस्या

जैसा एक प्रतिभागी का कहना था, *"अगर बिहार के मजदूर न आएं तो आप खेती नहीं कर सकते। हमने खुद खेती करनी छोड़ दी है।"* चाहे मुजफ्फरनगर हो या कोयंबटूर हर जगह किसानों की शिकायत है कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर तलाशना बड़ा संघर्ष हो गया है। मजदूरी काफी बढ़ गई है। गांव के युवा भले ही खाली बैठे हों लेकिन वे खेतों में नहीं जाएंगे। इसलिए खेत मालिक अनेक मौकों पर प्रवासी मजदूरों पर ही निर्भर होते हैं।

"नरेगा को खेती में जोड़कर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए। हमारे राजनीतिक तंत्र की सबसे बड़ी समस्या है मुफ्त में चीजें देना।" मजदूरों की समस्या से परेशान बागपत के एक किसान का कहना था कि कृषि मजदूरी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह इस स्कीम से मजदूरी का एक हिस्सा भुगतान हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्र के भू-स्वामी किसानों की राय थी कि तथाकथित मुफ्त वितरण बंद होना चाहिए। यह लोगों के काम करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है।

भुवनेश्वर में आयोजित ग्रामीण भारत का एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

एक किसान के अनुसार, *"किसान से आजकल कोई शादी नहीं करता। बच्चे एसी में बैठना पसंद करते हैं।"*

भारत में कृषि का भविष्य दुविधापूर्ण लगता है तो इसका कारण सिर्फ आर्थिक या पर्यावरण संबंधी चुनौतियां नहीं, बल्कि इससे गंभीर सामाजिक चुनौती भी जुड़ी हुई है। युवा खेती करना नहीं चाहते। खेती करने वालों को दुल्हन नहीं मिलती। समाज खेती को चुका हुआ मानने लगा है। उसे लगता है कि खेती में भविष्य अनिश्चित है, इसमें कोई कमाई नहीं। फसल खराब होने पर किसान के कर्ज में डूबने की आशंका बहुत अधिक है।

इसका परिणाम यह है कि परिवार की मदद से युवा उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हालांकि गिने-चुने सरकारी पदों को छोड़ दें तो गांवों में अच्छी नौकरी कहीं नहीं है। खेती से इतर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर भी बहुत कम हैं। इसके कई कारण हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित क्वालिटी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव तथा ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। नतीजा- आकांक्षाओं और क्षमताओं से लबरेज युवक-युवतियां बेरोजगार हैं।

"गांव नशा मुक्त होना चाहिए, यह सब की प्राथमिकता है। नशा नहीं होना चाहिए और इसके

ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का इंतजार

जोनाथन डोनाल्ड सिम्लिह, सॉक्रेटस

पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों में हुई व्यापक चर्चा और उनसे मिली अंतर्दृष्टि ने सामूहिक रूप से ग्रामीण भारत के लिए एजेंडा तैयार करने की नींव रखी। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता प्रमुखता से उजागर हुई। यह अनिवार्यता स्वास्थ्य और शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा पहुंच सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी की चुनौतियों से संबंधित निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

ग्रामीण रोड नेटवर्क: सम्मेलन में इस मुददे पर कराए गए मतदान के दौरान एक चौथाई से अधिक प्रतिभागियों ने मेघालय के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी व्यवस्था में सुधार के महत्व पर जोर दिया। मेघालय और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर मतदान के परिणाम में सर्वसम्मति से खेतों और कृषि मंडियों को परिवहन सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का बुनियादी ढांचा बढ़ाने की साझा मांग पर प्रकाश डाला गया।

स्वास्थ्य अवसंरचना: ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का लाखों ग्रामीणों के जीवन और आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश और मेघालय दोनों जगहों पर प्रतिभागियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की अपर्याप्तता और उनके ठीक से काम नहीं करने पर भी चिंता जताई। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मेघालय में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने कहा कि वे अपना नेता चुनते समय देखेंगे कि अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित, सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने के वादे उन्होंने पूरे किए हैं या नहीं।

शिक्षा अवसंरचना: ग्रामीण भारत में बुनियादी शैक्षिक ढांचे की स्थिति सीधे तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और विस्तार देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। मुजफ्फरनगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त कौशल और तकनीकी शिक्षा नहीं मिलती है। ओडिशा, राजस्थान, मेघालय और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ रही है।

मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स के एक प्रतिभागी ने कहा कि प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय तक बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर अधिक है। इसके अलावा, कृषि से संबंधित व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है। ओडिशा में मौजूद लोगों के चुनावी वादे मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। मेघालय में ज्यादातर प्रतिभागियों ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनावी वादों और कॉलेज स्तर तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में एकरूपता प्रदान करने की अपनी प्राथमिकता जताई।

ऊर्जा अवसंरचना: मेघालय, तमिलनाडु और ओडिशा के ग्रामीण निवासियों ने बताया कि बिजली कटौती और लोड शेडिंग का उनके दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय लागू करने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक किसान ने बिजली की बढ़ती दरों को चिंता का कारण बताया।

ओडिशा में प्रतिभागियों ने कहा कि वे ऐसे नेताओं को वोट देंगे जो जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा बुनियादी ढांचे का संतुलित, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष: स्थानीय समुदायों, किसानों, शिक्षकों, कारीगरों और अन्य लोगों द्वारा साझा की गई अंतर्दृष्टि ने ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे के एजेंडे को आकार देने में अमूल्य योगदान दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा जैसे आवश्यक क्षेत्रों में निवेश करके हम न केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि परिवर्तनकारी कदमों की एक श्रृंखला भी शुरू करते हैं जो ग्रामीण समुदायों के कल्याण पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

प्रति युवाओं में जागरूकता बहुत जरूरी है।"- एक प्रतिभागी।

2016 में हिंदी फिल्म 'उड़ता पंजाब' ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर फोकस किया था। 2023 में ऐसा लगता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल शहरी अभिजात वर्ग और पंजाब तक ही सीमित नहीं है। भुवनेश्वर हो या जोधपुर, हर जगह हमें यह सुनने को मिला कि समाज के हर वर्ग में बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स ले रहे हैं।

शराब ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से प्रमुख समस्या रही है। मेघालय, तमिलनाडु और ओडिशा में यह समस्या हमें अब भी सुनने को मिली। हालांकि ड्रग्स का पूरे देश में बढ़ता इस्तेमाल देख लगता है मुख्यधारा की मीडिया की नजरों में यह नहीं आया। गहरी समझ के अभाव में कोई इसके अलग-अलग कारण सोच सकता है। जैसे, क्या यह बेरोजगारी के कारण है, क्या यह इस वजह से है कि लोकप्रिय गाने और मीडिया इसे 'कूल' और स्वीकार्य बताने लगा है, या फिर ड्रग्स आसानी से मिलने लगे हैं? बेरोजगारी, सामाजिक संस्थाओं की कमी, लोगों की बढ़ती चाहत और उस हिसाब से ड्रग्स की उपलब्धता के कारण यह पूरे देश में महामारी की तरह फैल गई है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ

लोग अब भी अच्छी क्वालिटी के बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं। मेघालय के गारो, खासी और जैंतिया समुदाय के लोगों को अभी तक आने-जाने अथवा सामान ले जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं मिली हैं। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी तो है, लेकिन वह अपर्याप्त है। जहां सड़क है वहां सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। यही स्थिति बिजली की है। ग्रामीण भारत में पूरे दिन बिजली की सप्लाई आज भी सपना है। आज के युग में इंटरनेट का लगातार कनेक्शन मिलना भी आवश्यक है।

राजस्थान के बालोतरा के एक किसान को

अभी तक पीने के लिए साफ पानी का इंतजार है। देश के दूसरे छोर पर स्थित मेघालय के लोगों की भी यही स्थिति है, जो नल का कनेक्शन चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों के पास पानी तो है, लेकिन उनकी चिंता भूजल में मिल चुके रसायनों और धातुओं के जहरीले प्रभाव को लेकर है।

गांव में शिक्षा की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि वे पीछे छूट गए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। लोग अच्छी सार्वजनिक शिक्षा चाहते हैं, लेकिन जहां स्कूल है वहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं। सरकारी स्कूलों के बारे में धारणा है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते।

अच्छी सेहत और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत भी हर जगह लोगों में बढ़ती दिखाई दी। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ने के साथ लोग बेहतर इलाज की मांग करने लगे हैं, लेकिन

कोयंबटूर में आयोजित ग्रामीण भारत का एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गांव से काफी दूर हैं। स्थानीय स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में अनेक खामियां हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त नहीं और वहां दवाई और उपकरण भी नहीं मिलते। एक प्रतिभागी के अनुसार, "हम अपने गांव में स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, वहां आराम करने की जगह हो, खेल का मैदान हो, व्यायाम करने की सुविधा हो।"

गांव में रहने वाली पुरानी पीढ़ी समाज में बदलाव को देख रही है। उन्हें लगता है कि लोगों में भाईचारा कम होता जा रहा है। युवा पीढ़ी हमेशा अपने फोन में लगी रहती है और वह गांव-परिवार से दूर हो गई है। खानपान और जीवन शैली बदलने के साथ युवाओं में मोटापे की बीमारी बढ़ रही है।

अक्सर अनियोजित तरीके से सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने से पेड़ काटे जा रहे हैं। वाहनों की संख्या और कचरा बढ़ता जा रहा है। लोगों के बैठने के लिए पहले जो खुली जगह हुआ करती थी, अब वह कहीं नहीं दिखती। अब लोग पेड़ के नीचे बैठकर जीवन और राजनीति की चर्चा नहीं करते। ऐसे स्थान की जरूरत है जहां लोग एकत्र हो सकें, आराम से बैठ सकें, बातें कर सकें तथा जहां युवा खेलकूद-व्यायाम कर सकें। एक स्थान सबके मनोरंजन का भी हो। गांव को पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह के स्थान का निर्माण करना सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।

चुनावी राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार

"सबसे पहले वादा यह हो कि वादा करने वाला वादा नहीं निभाए तो उसे कानूनन अपराध माना जाए और इसके लिए सजा का प्रावधान हो। क्योंकि वे वादा करते हैं, आप वोट देते हैं, वे चले जाते हैं फिर अगले 5 साल बाद आए ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई।"

कोयंबटूर सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण लोगों ने चुनावी राजनीति में धनबल और बाहुबल का मुद्दा उठाया। वहां एक व्यक्ति का कहना था कि कानून अभी सिर्फ किसानों को निशाना बनाता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार सामने आता है तो सरकारी अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में भी तगड़ा माहौल दिखा। सम्मेलन में आए लोगों ने पैसे देकर और 'मुफ्त' का वादा करके मतदाताओं को लुभाने पर रोक लगाने की मांग की। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी नेताओं और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। लोग जुमले सुनकर थक गए हैं। वे चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि जो वादे करके चुनाव जीता है, उन वादों को वह पूरा करे।

ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभी दूर का सपना है। प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि

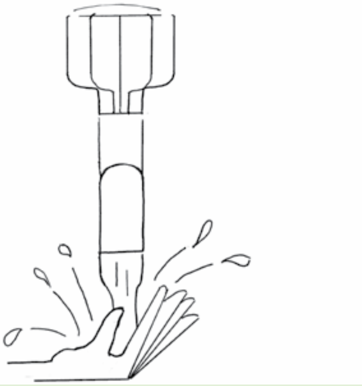

पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीण

अद्रिजा चौधुरी, सॉक्रेटस

पानी की सुविधा न केवल कृषि, बल्कि मानव समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों को पीने, घरेलू उपयोग और खेती में पानी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी जरूरत देश भर के ग्रामीण समुदायों की एक प्रमुख आकांक्षा थी। जोधपुर सम्मेलन में दो महिलाओं ने बताया कि पानी लेने के लिए वे प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर पैदल जाती हैं। वे राजस्थान के अर्ध-शुष्क जिले नागौर से आई थीं और ट्यूबवेल या नल तक उनकी पहुंच नहीं थी। बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, सीकर, जोधपुर, पाली और उदयपुर सहित राजस्थान के अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी का मुद्दा उठाया। इन क्षेत्रों के किसानों ने भूजल स्तर में गिरावट और खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के कारण इसके प्रदूषित होने पर भी अफसोस जताया। ओडिशा और मेघालय जैसे ज्यादा वर्षा वाले राज्यों में भी पानी तक पहुंच की समस्याएं थीं। मेघालय के तीन मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों- गारो, खासी और जैंतिया के प्रतिभागियों को सर्दियों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। उन्हें पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण वे खेती के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। इसलिए साल में केवल एक या दो फसलें ही उगा पाते हैं। ओडिशा के 30 में से 21 जिलों से प्रतिभागी आए थे। उन्होंने पीने के पानी और सिंचाई सुविधाओं की कमी को प्रमुखता से उठाया।

किसानों के अलावा अन्य ग्रामीण नागरिकों ने भी स्थानीय जल स्रोतों के क्षरण पर चिंता जताई। मेघालय के प्रतिभागियों ने कहा कि मैकेनिकल तरीके से मछली पकड़ने से नदियां उथली हो रही हैं और मछलियों की संख्या कम हो रही है। तमिलनाडु के प्रतिभागी पश्चिमी घाट की नदियों, झीलों और जलधाराओं के प्रदूषण और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों के पानी से संबंधित मुद्दों के बारे में अत्यधिक जागरूक थे।

बेरोजगारीः सामान्य या मजबूरी?

अनसिला एम. थॉमस, सॉक्रेटस

बेरोजगारी को लेकर बातचीत एक बड़ी भयावह समस्या के रूप में सामने आई जो देश के सभी हिस्सों में एक जैसी है। देश के पांचों क्षेत्रों में हमने देखा कि युवाओं में बेरोजगारी एक विशेष मुद्दा बनकर उभरी। कुछ स्थानों पर शिक्षितों के लिए पार्ट टाइम रोजगार था, तो अन्य स्थानों पर उद्योगों की कमी की वजह से लोगों में निराशा थी।

आजीविका और सरकारी नीति के मुद्दों पर विभिन्न समूहों के बीच बहस हुई। कई लोग, विशेष रूप से कृषि में लगे लोग नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनके पेशे को अपनाएं। मुजफ्फरनगर में यह बात सामने आई कि विकल्पों की कमी से कई युवा बेहतर अवसरों और अच्छी जीवन शैली की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। किसान माता-पिता को कर्ज में डूबते देखना और खेती को अपनाने से हतोत्साहित होने के बाद कई युवा खेती में नहीं जाना चाहते हैं।

गांव से होने वाले इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है, इसका एक संभावित समाधान युवाओं को खेती के लिए तकनीकी शिक्षा से लैस करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शैक्षिक पाठ्यक्रम काफी हद तक कृषि आवश्यकताओं से अलग हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी युवाओं की बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रही। यदि जनप्रतिनिधि छोटे व्यवसायों और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का समर्थन करने वाली नीतियों को प्राथमिकता देते हैं, तो उन्हें वोट मिलने की अधिक संभावना होगी। मेघालय में बेरोजगारी की वजह से युवाओं में नशीली दवाओं और शराब की लत बढ़ी रही है।

ओडिशा और तमिलनाडु, में राजनीतिक भ्रष्टाचार को उनके क्षेत्रों में बेरोजगारी से जोड़ा गया। ओडिशा में अप्रभावी शासन विशेष निराशा का कारण थी। इसके कारण सरकार द्वारा प्रस्तावित कई योजनाएं लागू नहीं हो पाईं। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी मामलों में पार्ट टाइम रोजगार और विकल्प की कमी को बेरोजगारी के समान महत्व वाली समस्याओं के रूप में पहचाना गया।

जोधपुर में आयोजित ग्रामीण भारत का एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार उनके गांव की प्रगति में बाधा है। पंचायत और कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार मुजफ्फरनगर और जोधपुर में कई गरमा-गरम बहस का मुद्दा रहा। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के एक समाधान के रूप में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने का सुझाव आया। भुवनेश्वर में प्रतिभागियों ने मनरेगा जैसी सरकारी स्कीम समेत हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई। शिलांग में भी लोगों की मांग थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने और वह वादों पर खरी उतरे।भ्रष्टाचार पर बातचीत हाल के वर्षों में भले ही कम हुई जान पड़ती हो, लेकिन लोगों को लगता है कि यह लगातार गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

वोट देने से पहले काफी सोच-विचार

जब लोगों से पूछा गया कि राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, तो कागज पर अपनी बात लिखने से पहले उन्होंने काफी देर तक सोच विचार किया। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। केंद्र और राज्य सरकार के लिए कौन से मुद्दे प्राथमिकता में है, यह अंतर स्पष्ट है। मेघालय में लोकसभा प्रत्याशी से ज्यादातर लोगों की मांग थी कि वह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और वहां की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाए, शांति कायम करने में भूमिका निभाए और राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य में अमल करवाए। राज्य चुनाव के प्रतिनिधियों से उनकी उम्मीद थी कि वह सामुदायिक विकास, जलापूर्ति और रोजगार के लिए कम करे। इसी तरह राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों से लोगों की उम्मीदें नौकरियां, कानून व्यवस्था, शिक्षा, बिजली आदि को लेकर थी, तो राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से नदियों को जोड़ने पर फोकस करने की अपेक्षा थी।

पानी भी हर क्षेत्र में लोगों की चर्चा का विषय रहा। भारत दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले क्षेत्रों में है। चाहे पीने के पानी की बात हो अथवा सिंचाई के पानी की, इसकी कमी हम सबको प्रभावित करती है। दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग औरों से ज्यादा इस समस्या को भुगत रहे हैं। यह जरूरी है कि हमारी राजनीतिक और नीतिगत बातचीत में इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाए।

ग्रामीण भारत अपना उचित स्थान मांग रहा है

"राजनीतिक दल ग्रामीण विकास की योजनाओं के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर घोषणा पत्र समिति में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।" एक प्रतिभागी का यह कहना गांव की आकांक्षा को बताता है। देश के 60 जिलों के 300 से ज्यादा लोगों की दबी हुई आकांक्षा यही है कि राष्ट्रीय परिकल्पना में ग्रामीण भारत को भी स्थान मिले। हमारा मीडिया, सिनेमा, हमारी आकांक्षाएं और राजनीति सब 65% भारतीयों के जीवन की हकीकत से दूर जाती दिख रही हैं। इन ज्वलंत मुद्दों का समाधान न करना गवर्नेंस की नाकामी है। सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव जैसी समस्याएं तो दशकों से हैं, जलवायु परिवर्तन और ड्रग्स की समस्याएं हालिया हैं।

लोगों में कृषि गतिविधियों के प्रति आकर्षण फिर से जगाने की जरूरत है। किसानों के बच्चे

शिलांग में आयोजित ग्रामीण भारत का एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी।

उत्तर-पूर्वी ग्रामीण भारत की हकीकत

जोनाथन डोनाल्ड सिम्लिह, सॉक्रेटस

एजेंडा फॉर रूरल इंडिया- मेघालय' सम्मेलन में राज्य के सात जिलों के प्रतिभागियों के विविध समूहों ने अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों के आधार पर ग्रामीण विकास और स्थायित्व पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में अपनी पहचान के बावजूद मेघालय सर्दियों में पानी की कमी की समस्या से जूझता है। पीने के लिए साफ पानी की कमी तो होती ही है, खेती में सिंचाई के लिए भी पानी कम मिलता है।

कुछ प्रमुख निष्कर्ष

आजीविका: पूर्वी जैंतिया हिल्स से आए एक प्रतिभागी ने कहा, 'हमें अपनी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।' उन्होंने राज्य में बेरोजगारी की व्यापक स्थिति पर अपने विचार साझा करते हुए युवाओं को श्रम बल में समाहित करने के लिए नौकरी के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिभागियों के मुताबिक, उद्यमिता और ग्रामीण उद्यम को प्रोत्साहित करने के नए तरीके खोजना आजीविका की संभावनाएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

ग्रामीण विकास: प्रतिभागियों ने रोड नेटवर्क के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी कमी न सिर्फ पहुंच को बाधित करती है, बल्कि व्यापार और परिवहन के अवसरों को भी सीमित करती है। उन्होंने बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की अपर्याप्तता के साथ-साथ अनियमित शिक्षकों और बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर ज्यादा होने के कारण शिक्षा सुविधाओं की कमी को भी सामने रखा।

जलवायु परिवर्तन: ज्यादातर प्रतिभागियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कीटों का संक्रमण बढ़ गया है जिससे पैदावार पर खतरा पैदा हो गया है। किसानों ने फसलों का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष और भुगतान में देरी का अनुभव साझा करते हुए चिंता जताई। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के एक किसान ने कहा कि मौसम में अचानक बदलाव और चरम घटनाओं में वृद्धि ने पैदावार और किसानों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

कृषि: किसानों ने सरकार से नियामकीय भूमिका की भी मांग की, ताकि कृषि बाजार में उनके हितों की रक्षा की जा सके, निष्पक्षता बढ़े और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि क्षेत्र स्थिर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहे।

नशीले पदार्थों का सेवन: युवाओं में बढ़ती नशाखोरी एक प्रमुख सामाजिक मुद्दे के रूप में उभरी, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियां पैदा करती है। एक ग्रामीण कार्यकारी सदस्य ने कहा कि कम उम्र में विवाह की प्रथा बच्चों के समग्र कल्याण और शिक्षा एवं अवसरों तक पहुंच पर सवाल उठाती है।

युवाओं से संवाद: मेघालय के युवाओं ने सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे बुनियादी ग्रामीण ढांचे पर ध्यान न देने जैसी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल क्षमता का इस्तेमाल करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, खेल के अवसरों और कला को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, सम्मेलन में उन तरीकों की खोज पर चर्चा हुई जिसके माध्यम से युवा उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने समुदायों के विकास और समृद्धि में योगदान दे सकते हैं।

मतदान की प्राथमिकता: प्रतिभागियों ने बताया कि समग्र ग्रामीण विकास का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को ही वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देंगे। उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में व्यापक सड़क संपर्क, किफायती स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रोजगार सृजन के साथ 2025 तक जीरो लोड शेडिंग के साथ नियमित और निर्बाध बिजली का आश्वासन शामिल है।

और युवा खेती नहीं करते हैं तो कोई भविष्य नहीं है। इसलिए एक किसान का कहना था, *"क्या स्वाभिमान नहीं है हमारे अंदर, हम मेहनत वाले लोग हैं, अन्नदाता कहलाए जाते हैं किसान, खुद नहीं कमा सकते क्या, आप हमें व्यवस्थाएं दीजिए, साधन दीजिए, बाकी का हम कर लेंगे।"*

लोगों को अब भी अपने गांव पर और खुद पर गर्व है। वे विकास चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि शहर जाने का मतलब जरूरी नहीं कि उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। वे ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जो शहरों में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। इसके बजाय वे गांव में ही अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अनकहा सवाल है- 'फ्री बी' देने के बदले क्या यह संभव नहीं कि गांव में निवेश किया जाए और स्थानीय स्तर पर उद्यमी तथा बिजनेस खड़े किए जाएं, जिससे वहां के लोगों का जीवन सुधर सके? क्या अच्छी एक्सटेंशन सेवा और मार्केटिंग से खेती की मदद नहीं की जा सकती है?

ग्रामीण भारत की आकांक्षा एक बेहतर जीवन की है, और यह आकांक्षा पूरे देश में है। गांव के लोग काम करने और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। कोयंबटूर में किसानों का एक समूह किसान परिवारों को डिस्काउंट पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता है। लोग एकजुट हों तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। सरकार सही कदम उठाए और बाजार की मदद मिले, तो इनकी आकांक्षाएं हकीकत बन सकती हैं। RW

(प्रचुर गोयल सॉक्रेटस के डायरेक्टर हैं)

नए ग्रामीण भारत की आकांक्षाएं

टी. नंदकुमार

लेखक खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव और एनडीडीबी के पूर्व चेयरमैन हैं

रूरल वॉयस (रूरल वर्ल्ड का सहयोगी प्रकाशन) और सॉक्रेटस (गैर सरकारी संगठन) ने यह असाधारण कार्य किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गया, वहां लोगों की बातें सुनीं। इसने भारत के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच केंद्रों में लोगों की आकांक्षाओं को समझने का प्रयास किया। संक्षेप में कहें, तो यह प्रयास बहुसंख्यक भारतीयों की चिंताओं, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के साथ भविष्य के दृष्टिकोण का खाका प्रस्तुत करता है। सरकार और नीति निर्माताओं के लिए यह ग्रामीण विकास को नया स्वरूप देने और आकांक्षी ग्रामीण भारत की समस्याओं के समाधान का एक टेम्पलेट भी मुहैया कराता है।

आयोजकों ने विकास, जलवायु और पर्यावरण तथा राजनीतिक-आर्थिक के अलग-अलग शीर्षकों के तहत मुद्दों को रेखांकित किया है। फिर भी, साझा तौर पर जो मुद्दे सामने आते हैं, वे हैं: अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग करना चाहते हैं, बाजार तक बेहतर पहुंच के साथ उपज की अच्छी कीमत चाहते हैं, मानव-पशु संघर्ष का समाधान चाहते हैं- विशेष रूप से आवारा पशुओं के संदर्भ में, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक प्रयास चाहते हैं।

हालांकि इन मुद्दों को विभिन्न मंचों पर अनेक बार उठाया गया है, यह संभवत: पहली बार है कि उन्हें एक ठोस, एक्शन योग्य प्रारूप में रखा गया है। ग्रामीण भारत की आम शिकायत है कि चुनावों में किए जाने वाले बड़े-बड़े वादों पर अमल नहीं होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ग्रामीण भारत नेताओं और उनके चुनावी वादों से निराश है। उन्हें एहसास होने लगा है कि चुनावी वादे तो बस जुमले हैं। यदि ग्रामीण भारत को समृद्ध, स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाना है तो इस धारणा को बदलना होगा। सरकार से लोगों के निराश होने का परिणाम समाज में अशांति हो सकती है और उग्रवाद का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जो देश के समग्र विकास के लिए हानिकारक है।

ग्रामीण भारत को अवरुद्ध करने वाली इनमें से अधिकांश समस्याओं से सरकार अवगत है। उसने मनरेगा, स्वच्छ भारत, ग्रामीण पेयजल मिशन (जल शक्ति), ग्रामीण विद्युतीकरण, पीएम किसान, आकांक्षी जिला (अब ब्लॉक) कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से समय-समय पर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण भारतीयों की आय और जीवन में सुधार है। अधिकांश योजनाओं के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। हालांकि, आकांक्षी ग्रामीण भारत गरीबों के जीवन में सुधार लाने वाले ऐसे कार्यक्रमों से अधिक और तेज नतीजों की उम्मीद करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ योजनाओं को एकीकृत करने और गांव तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयासों को साथ लाने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने गठन के बाद से ही ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित कर रहा है। इस मद में वह काफी व्यय भी करता है। इनमें आईआरडीपी और इसके बाद के अवतार मनरेगा, पीएमजीएसवाई जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, पंचायती राज, जल संसाधन जैसे अन्य मंत्रालयों के भी कई प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण भारत के लिए हैं, जिन्हें संबंधित मंत्रालय संचालित करते हैं। इन्हें जिला और ब्लॉक स्तरों पर लागू किया जाता है। इन कार्यक्रमों को लागू करने वाली संबंधित एजेंसियों द्वारा केंद्रीय और राज्य स्तर पर इनकी निगरानी की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण आबादी पर उनके प्रभाव की जानकारी नहीं है। व्यापक विकास के परिप्रेक्ष्य से नतीजों को मापना और प्रभावों का आकलन करना एक चुनौती बना हुआ है।

सरकार को चाहिए कि वह सभी ग्रामीण कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी निगरानी में ग्रामीण विकास विभाग को बड़ी भूमिका दे। उसकी भूमिका नीति आयोग के लगभग समानांतर हो। कार्यक्रमों को ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी भी उसी के पास हो। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में योजना बनाने के साथ उनकी निगरानी कार्य समाहित करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्रालयों में मंत्री और सचिव स्तर पर शासन के पद-क्रम की प्रकृति को देखते हुए, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक अलग तरह की समन्वय अथॉरिटी की आवश्यकता है। पारंपरिक समन्वय समिति या मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह से परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। संबंधित मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र रहें,

लेकिन कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी की जिम्मेदारी नई समन्वय अथॉरिटी को सौंपी जानी चाहिए। राज्य स्तर पर भी ऐसी ही अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए।

अधिकांश केंद्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन राज्य और जिला स्तर के प्रशासन पर निर्भर करता है। विकास के अधिकांश कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्रमुख प्रशासनिक इकाई बन गया है। लेकिन जिला कलेक्टर की व्यवस्था अब भी पुराने राजस्व और कानून-व्यवस्था सिस्टम की तर्ज पर चल रही है। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त और जिला परिषद प्रणाली गठित करने के प्रयोगों के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। राज्य सरकारें अपनी भूमिका और अधिकारों को किसी जिला स्तरीय संस्था को सौंपने में झिझकती रही हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या अन्य। एक-दो राज्यों को छोड़कर, जिला स्तरीय पंचायती राज (जिला परिषद) प्रयोग को कोई खास सफलता नहीं मिली है।

आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति विकास को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व भी बढ़ा है। इसे देखते हुए जिला स्तर पर शासन के मॉडल को इसके दायरे, इसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में एक नया स्वरूप देने की आवश्यकता है। योजना बनाना निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होनी चाहिए। विकास की निगरानी अलग ढंग से हो और योजनाओं में ही उनमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। जिला कलेक्टर कार्यालय कामकाज के मौजूदा मानदंडों के साथ आकांक्षी भारत की चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इस कार्यालय को व्यापक तौर पर रीडिजाइन करने और मजबूत बनाने की जरूरत है। जिला कलेक्टर की मदद के लिए युवा और कुशल तकनीक वाले प्रोफेशनल होने चाहिए। कलेक्टर को कई नियमित समितियों और बैठकों से भी मुक्त किया जाना चाहिए जो उसके कामकाज पर असर डालती हैं। यदि सार्थक ग्रामीण विकास हासिल करना है तो जिला कलेक्टर की भूमिका और कार्यों को तत्काल नए सिरे से डिजाइन करने की आवश्यकता है।

खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास का आधार है। तत्कालीन योजना आयोग के सामुदायिक विकास एजेंडे में इसकी कल्पना की गई थी। सभी प्रशासनिक कार्यालयों में यह संभवतः सबसे अधिक समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी किया जाने वाला कार्यालय है। कौशल और सपोर्ट सिस्टम को देखते हुए इस कार्यालय से अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि दिए गए टार्गेट को हासिल करना प्राथमिकता बन जाती है, चाहे वह टारगेट जो भी हो।

कार्यान्वयन के पद-क्रम में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यों और जिम्मेदारियों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कौशल और सपोर्ट सिस्टम के लिहाज से उसकी स्थिति शायद सबसे कमजोर होती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस कमी को दूर करने के लिए अक्सर अपर्याप्त और तदर्थ प्रयास ही किए हैं। उन्होंने खंड विकास कार्यालय के काम के ढांचे को रीडिजाइन करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। उन्होंने अधिकारियों को कामकाज की प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी के मामले में प्रशिक्षण देने में पर्याप्त निवेश भी नहीं किया है। आज का खंड विकास कार्यालय भविष्य का कार्यालय होने के बजाय अतीत का प्रतिनिधित्व करता है।

जिन राज्यों ने 73वें संविधान संशोधन की परिकल्पना के अनुसार पंचायतों को अधिक काम और जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनके परिणाम उन राज्यों की तुलना में बेहतर रहे हैं जो पंचायतों को सशक्त बनाने में धीमे थे। कई राज्यों ने तो पंचायतों को किसी तरह की स्किल या वित्तीय शक्ति दिए बिना सिर्फ कागजों पर अधिकार दे दिए। तेज ग्रामीण विकास हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है- उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकी सहायता के साथ स्थानीय रूप से उपयुक्त योजनाओं को डिजाइनिंग, प्लानिंग और कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना। वित्त आयोग के अनुदान के बावजूद राज्य पंचायतों को संसाधन आवंटित करने और उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मदद करने में असमर्थ रहे हैं। यह स्थिति ग्रामीण विकास के लिए अभिशाप है। कम समय में ग्रामीण परिदृश्य बदलने के लिए पांच साल का निवेश कार्यक्रम पहला कदम है। इसमें कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम, अधिक राशि का हस्तांतरण और इसके उपयोग के लिए निरंतर मार्गदर्शन शामिल होना चाहिए।

बेशक, राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इनमें कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन, रासायनिक उर्वरकों के लिए इन्सेंटिव, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण बाजारों को शहरी मांग केंद्रों से जोड़ना, कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश तथा जलवायु और पर्यावरण से संबंधित नीतियां शामिल हैं।

किसी भी जन-हितैषी और जन-केंद्रित योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न स्तर पर लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की सरकार की क्षमता है। रूरल वॉयस और सॉक्रेटस का यह प्रयास ग्रामीण भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं को समझने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को सलाह होगी कि वह समस्याओं और आकांक्षाओं को समझने तथा लोगों के अनुकूल नीतियों को डिजाइन करने में लोगों की आवाज सुनने के लिए ऐसे अनौपचारिक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करे। Rw

जिन राज्यों ने 73वें संविधान संशोधन की परिकल्पना के अनुसार पंचायतों को अधिक काम और जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनके परिणाम उन राज्यों की तुलना में बेहतर रहे हैं जो पंचायतों को सशक्त बनाने में धीमे थे।

कृषि सुधार पर अब राज्य आगे बढ़ें

*नीति आयोग के सदस्य **प्रोफेसर रमेश चंद** दुनिया के जाने-माने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं। देश की कृषि नीतियों के निर्धारण में हमेशा उनकी छाप दिखती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट होने के नाते उन्होंने कई पेपर और किताबें लिखी हैं। हाल ही में हरित क्रांति और अमृत काल को लेकर भारतीय कृषि पर उनका महत्वपूर्ण पेपर आया है, जिसमें उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र के भविष्य का रोडमैप रखने की कोशिश की है। **रूरल वर्ल्ड** के एडिटर इन चीफ **हरवीर सिंह** से उनकी बातचीत के प्रमुख अंश:*

प्र एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अब भी बड़ा जटिल मुद्दा है। इसके चलते फसलों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होते हैं जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। कृषि सुधारों का रोडमैप क्या होना चाहिए? किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, आप भावांतर को प्रभावी नीतिगत कदम मानते हैं। इस पर आपकी क्या राय है और कैसे काम होना चाहिए?

कृषि उत्पादन मौसम और जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इस कारण उनमें अस्थायित्व और उतार-चढ़ाव है, जो स्वाभाविक है। उसे रोक नहीं सकते, लेकिन जो उतार-चढ़ाव उत्पादन की प्रकृति की वजह से होते हैं और जिसका असर किसानों एवं उपभोक्ताओं पर पड़ता है, उसे हम मार्केट की सही नीतियों से कम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। किसानों को उपज की जो कीमत मिलती है उसके दो पक्ष हैं। एक तो सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलता है और दूसरा, बाजार से कीमत मिलती है। ये दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं। बाजार प्रतिस्पर्धी हो तो किसानों को वाजिब कीमत मिल जाएगी, लेकिन उत्पादन ज्यादा होने पर प्रतिस्पर्धा के बावजूद कीमत गिर जाती है। इसलिए बाजार में

भी कीमतों को लेकर सरकार की ओर से हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है। हमें दो-तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि बाजार में यदि किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है, तो एमएसपी उसको नुकसान न पहुंचाए। दूसरा यह कि एमएसपी देने का जरिया क्या है। हमारे देश में इसे ज्यादातर सरकारी खरीद के जरिये दिया जाता है। अनाजों की सरकारी खरीद इसलिए भी जरूरी है कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए अनाज चाहिए। अगर हमें पीडीएस से अलग अनाज चाहिए तो हमें दूसरे साधन अपनाने की जरूरत है, जैसे भावांतर भुगतान योजना, जिसका आइडिया मैंने बहुत साल पहले दिया था। मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस पर थोड़ा अमल हुआ है। इस तरह के दूसरे साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए जो एमएसपी के नकारात्मक असर को नियंत्रित कर सकते हैं।

प्र *कृषि सब्सिडी नीति निर्धारकों और अर्थविदों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। सब्सिडी देने की नीति पर अमल जारी रहना चाहिए या प्रोत्साहन आधारित आर्थिक नीति अपनानी चाहिए? कुछ राज्यों ने किसानों को सीधे कैश ट्रांसफर की नीति अपनाई हैं। केंद्र भी पांच साल से किसानों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहा है। क्या यह भविष्य में सब्सिडी की जगह ले सकता है?*

दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। इसके बारे में पहले मैं विस्तार से बता दूं कि इस पर क्या विचार करना चाहिए और हम किस स्थिति की ओर जा रहे हैं। सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि यह उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और ग्रोथ लाता है, क्योंकि अधिकांश सब्सिडी इनपुट पर होती है। इसका एक पक्ष यह भी है कि कोई किसान अपनी जमीन में इनपुट का उपयोग नहीं करता है, तो उसे सब्सिडी मिलने का कोई औचित्य भी नहीं है। दूसरा है नगद देना, जिसका इस्तेमाल किसान किसी भी रूप में कर सकता है, चाहे वह फर्टिलाइजर इनपुट हो या कोई और इनपुट या कुछ और। यह सभी को मिलेगा, भले वह इनपुट इस्तेमाल करता हो या नहीं। लेकिन सब्सिडी से उत्पादन पर जितना सकारात्मक असर पड़ता है उतना नगद हस्तांतरण से नहीं पड़ता। जो फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। यह सिस्टम में एक बैलेंस लाता है। सब्सिडी कई तरह की हैं। जैसे आप बीज पर सब्सिडी देते हैं, फिर जो टेक्नोलॉजी का कैरियर है उस पर सब्सिडी देना अच्छी बात है। एग्रीकल्चर कंजर्वेशन के लिए सब्सिडी अच्छा है। यदि आप फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी देते हैं, जिसकी वजह से किसान पराली जलाने की बजाय उसका प्रबंधन कर पाता है, तो यह बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण यह है कि सब्सिडी किस तरीके से देते हैं और किस चीज पर देते हैं। सब्सिडी देने से ज्यादा सब्सिडी देने के तरीकों से इसके नकारात्मक प्रभाव पैदा हुए हैं। हम सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं, इससे पानी का ज्यादा इस्तेमाल होगा और भूजल स्तर नीचे चला जाएगा। इस तरह दोनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं।

हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और इनकम सपोर्ट की ओर जा रहे हैं और सब्सिडी भी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे तर्कसंगत नहीं बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तर्क दिया जाता है कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या इनकम सपोर्ट सब्सिडी कम करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में हम उसको कम नहीं कर रहे हैं। यदि सभी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखा जाए तो इनकम सपोर्ट के रूप में दी जाने वाली राशि सब्सिडी की तुलना में बेहतर है।

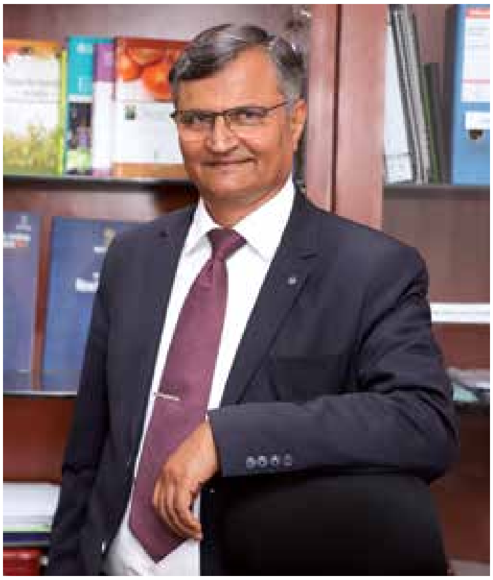

"तर्क दिया जाता है कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या इनकम सपोर्ट सब्सिडी कम करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में हम उसको कम नहीं कर रहे हैं।"

प्र *खाद्य सुरक्षा में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की है और देश एक बड़े कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है। कृषि निर्यात का स्तर 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। लेकिन दो साल से गेहूं, चावल और चीनी निर्यात पर प्रतिबंध या सख्ती की स्थिति क्यों पैदा हो गई है, जबकि सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के दावे किये हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर नीतियों में स्थायित्व क्यों नहीं है? अचानक लिए जाने वाले फैसलों को आप कैसे देखते हैं?*

यदि आपकी परिस्थिति में स्थायित्व नहीं है तो आप नीति को भी स्थायी नहीं रख सकते हैं। नीतियां परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 10-15 फीसदी के सामान्य उतार-चढ़ाव से ज्यादा बदलाव आ जाता है तो हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। देश में अचानक कहीं बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या किसी परिस्थिति में उत्पादन ज्यादा प्रभावित हो गया, तो उस स्थिति में आपको यह चुनना होता है कि आप देश को प्राथमिकता देते हैं या विदेश को। आपका अपना उपभोक्ता प्राथमिकता में है या विदेश का।

बहुत से फैसले देखने में लगता है कि अचानक लिए गए, लेकिन आप देखेंगे कि जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा। जैसा पिछले दिनों आपने प्याज के मामले में देखा। अगर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो जैसा कि पहले होता था, प्याज की कीमत 100 रुपये तक चली जाती। फूड मैनेजमेंट और फूड प्राइस को नियंत्रित रखना उपभोक्ता और किसानों दोनों के लिहाज से जरूरी हो जाता है। मैं आपकी इस बात से जरूर सहमत हूं कि यह हस्तक्षेप तभी होना चाहिए जब कीमत एक तय सीमा से ऊपर या नीचे चली जाए।

किसानों और व्यापारियों सभी के मन में यह रहना चाहिए अगर कीमतें तय सीमा में रहेंगी तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। उससे ऊपर या नीचे जाएंगी तो सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी। विदेशों में भी ज्यादातर सरकारें ऐसा करती हैं। हमने हमेशा पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक लिबरलाइजेशन को माना है। हमारा लक्ष्य रहा

हमारा लक्ष्य रहा है कि हम अपने प्राइस को इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से ऊपर-नीचे जाने देंगे, लेकिन उतार-चढ़ाव ज्यादा होने पर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, कभी उपभोक्ता के लिए, तो कभी किसानों के हित में।

है कि हम अपने प्राइस को इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से ऊपर-नीचे जाने देंगे, लेकिन उतार-चढ़ाव ज्यादा होने पर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, कभी उपभोक्ता के लिए, तो कभी किसानों के हित में।

प्र *क्या रद्द किये गये तीन कृषि कानून समय की जरूरत थी, क्या अब भी कृषि सुधारों पर काम होना चाहिए? सरकार दो साल से लगातार आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग कर रही है जो तीन कृषि कानूनों की उदार कृषि बाजार भावना के अनुरूप नहीं है। ये दोनों विषय एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, तो कृषि क्षेत्र में सुधारों की कितनी जरूरत है?*

जब तीन कृषि कानून वापस लिए गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि शायद हम किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाने में असफल रहे। नीतियों में कमियां हो सकती हैं। मेरा मानना है कि किसी भी इकोनॉमी में प्रगति के कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जैसे, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बढ़ाने का कारक होता है, दूसरा, हमारी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन उसके कारक होते हैं। परिस्थिति के हिसाब से यदि हम पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन में सुधार नहीं करते हैं तो इंक्रीमेंटल चेंज ही आएगी, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगी। पिछले महीने मैं मार्केटिंग के एक कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु गया था। वहां मैंने मार्केटिंग सोसायटी से कहा था आप हर राज्य में यह डिबेट करें, क्योंकि वर्ष 2002 से इस पर बहुत अच्छे-अच्छे विचार आ चुके हैं, इन पर बहुत डिबेट हो चुकी है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के थिंकर्स ने अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका। राज्य स्तरीय समितियों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इन कानूनों के उन मॉडल पर चर्चा करनी चाहिए जो फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था, मॉडल कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट था, उन मॉडल को लेकर राज्य अपने यहां चर्चा करें। मैं किसानों से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वे खुले मन से इन पर चर्चा करें। इनको ठंडे बस्ते में डालना कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए अच्छा नहीं होगा।

हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के कुछ पहलू केंद्र के स्तर पर हैं और कुछ राज्य के स्तर पर। राज्यों की भी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है, या कहें कि कृषि क्षेत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। उनको इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए और उससे जो निकल कर आए उसे लेकर सुधारों की ओर जाना चाहिए।

दूसरा, आपका सवाल है कि केंद्र सरकार एक ओर आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार लेकर आई थी, तो दूसरी ओर खुद उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव लाने का आधार यह था कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मार्केट में निजी निवेश बढ़ेगा। यदि कभी किसी चीज की उपलब्धता की जरूरत हो, तो सरकार का ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र का भी बफर स्टॉक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दो ही तरीके से कीमतें स्थिर रह सकती हैं, या तो आप ट्रेड करो या फिर स्टॉक में रखो। ज्यादातर देशों में सरकारी स्टॉक नहीं होता है, वहां प्राइवेट स्टॉक से ही उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है। यदि बाजार से संबंधित कानून लागू हो जाता तो आप देखते कि निजी निवेश कितना बढ़ता, कितने भंडारण गृह बनते। बजाय इसके कि सारा माल एकदम से बाजार में आ जाए, वह धीरे-धीरे कीमत के हिसाब से बाहर आता। आवश्यक वस्तु अधिनियम और बाजार को लेकर कानून एक दूसरे के पूरक थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम रहेगा तो निजी निवेश नहीं आएगा और अगर निजी निवेश नहीं आता है तो आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम की जरूरत पड़ेगी। यह एक वजह है कि पहले सरकार जो करना चाहती थी अब उसके विपरीत कर रही है।

प्र *आपने पिछले दिनों 'हरित क्रांति से अमृत काल: लेसंस एंड वे फारवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर' पेपर जारी किया, जिसमें हरित क्रांति से सबक लेकर कृषि की भावी रणनीति के लिए कदमों को सामने रखा है। इन पर अमल कैसे होगा?*

पिछले 75 वर्षों में हमारी कई उपलब्धियां रही हैं और पिछले 10 वर्षों में तो हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 4-5 फीसदी रही है। उनके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी

चुनौती के रूप में सामने आया है, केमिकल के बहुत ज्यादा प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर उस पर साइंटिफिक तरीके से रोड मैप नहीं बनाएंगे तो इधर-उधर भटकने की आशंका रहेगी। मैंने उसमें यह बात भी लिखी है कि हम जो प्राकृतिक खेती की ओर जाने की बात कह रहे हैं, उससे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में सुधार आएगा। इनको देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया है। उसमें एक-दो बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। अधिकांश सबूत ऐसे हैं कि एग्रो-केमिकल आधारित खेती को छोड़कर परंपरागत खेती, जिसमें एग्रो-केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था और देसी बीज का उपयोग होता था, में उत्पादकता 30 से 35 फीसदी प्रभावित होगी। परंपरागत खेती में उत्पादकता की कमी को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। हरित क्रांति की वजह से जो आधुनिक खेती शुरू हुई, उसमें 100 साल के विज्ञान की भूमिका है। मक्का का हाइब्रिड 1920 में ही आ गया था। फिर केमिकल आए, तरह-तरह के सीड्स आए और कई सारी चीजें आईं। एक ओर 100 साल का विज्ञान और दूसरी ओर परंपरागत खेती जिसमें हमने विज्ञान को शामिल ही नहीं किया।

इन सबको देखते हुए मैंने एक रोड मैप रखा है कि यह जो उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, उसका एक हिस्सा हम सहन कर सकते हैं क्योंकि अब हम खाद्यान्न में सरप्लस हैं। हम यह चांस ले सकते हैं कि धीरे-धीरे उस ओर बढ़ते जाएं लेकिन बहुत संभल कर। दस साल बाद इसका जायजा लें कि इस दौरान इसमें विज्ञान को शामिल कर उत्पादकता बढ़ाने में कामयाब हो गए ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

उदाहरण के लिए, जब हम अगले 25 साल के लिए विकास की बात करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि विकसित देशों में कृषि को लेकर क्या हुआ था। जब वे विकासशील से विकसित देश बने तो उनका एक मॉडल था। वे उसी के अनुसार विकसित हुए और वहां की सभी सरकारों ने उस मॉडल को लेकर अपनी नीतियां बनाई। वह मॉडल यह था कि जब कोई अर्थव्यवस्था प्रगति करती है तो वहां इंडस्ट्री बढ़ती है और मजदूर कृषि क्षेत्र छोड़ कर इंडस्ट्री में आते हैं। दोनों क्षेत्रों में नई-नई मांग आती है और देश की आय और देश के रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी घटती जाती है। पश्चिमी देशों में आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी इकोनॉमी में 2-4 फीसदी ही है और 2-4 फीसदी लोग ही वहां कृषि में लगे हुए हैं। मगर पिछले कुछ सालों में यह पाया गया कि गैर कृषि क्षेत्र, विशेष तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम रोजगार पैदा कर पा रहा है। सेक्टर की ग्रोथ तो 10 फीसदी हो रही हो लेकिन रोजगार की ग्रोथ 2-4 फीसदी ही है।

विकासशील से विकसित बने उन देशों ने जो मॉडल अपनाया, हमारे लिए आज की इंडस्ट्री उस विकल्प को बंद कर चुकी है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकसित भारत का लक्ष्य लेकर अगर हम चल रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति की आमदनी 2100 डॉलर से बढ़कर 11-12 हजार डॉलर हो जाएगी, तो फिर लोगों को रोजगार कहां मिलेगा, लोगों की आमदनी कहां से होगी। सरकार का इनक्लूसिव ग्रोथ का जो लक्ष्य है, उसमें हमें सिर्फ देश की आमदनी नहीं बढ़ानी, बल्कि सभी लोगों की आमदनी बढ़ानी है और आमदनी बढ़ती है रोजगार से। उस रोड मैप में मैंने इस चीज को भी उजागर करने की कोशिश की है कि हमें अब कृषि केंद्रित विकास के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारा रोजगार अब भी कृषि केंद्रित है। पिछले दिनों 2022-23 का पीएलएफएस का सर्वे आया, वह भी कहता है कि 45.8 फीसदी कार्यबल कृषि क्षेत्र में ही है। उसमें बहुत धीमी गति से कमी आ रही है। सस्टेनेबिलिटी, इम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज और इसी तरह ग्रोथ की गति को बरकरार रखना, इन सब को देखकर मैंने उसमें एक पोजीशन लिया है कि विकसित भारत बनाने में कृषि केंद्रीय भूमिका अदा करेगा।

> **बहुत सारी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, केमिकल के बहुत ज्यादा प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है।**

प्र कृषि में नई तकनीक पर जोर है लेकिन कृषि शोध और ढांचागत सुविधाओं पर सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ रहा है जिसकी जरूरत लगातार कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बताई जाती रही। जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर भी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट नहीं। क्या जीएम टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयोगी है और क्या शोध एवं तकनीक को अपनाने एवं निवेश बढ़ाने को लेकर हमें आक्रामक रुख अपनाना चाहिए?

कृषि क्षेत्र में तकनीक कई सारे क्षेत्र से आ रहे हैं। पहले हम पब्लिक सेक्टर पर ही पूरी तरह निर्भर थे। अब आप देख रहे होंगे कि एग्री-स्टार्टअप भी आ रहे हैं, निजी क्षेत्र भी है। लेकिन हमने एग्रीकल्चर का जो फ्रेगमेंटेशन कर दिया- एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, फिशरीज यूनिवर्सिटी- उससे फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो पैसा शोध में जाना चाहिए था वह वेतन में जाने लगा। उसका हम एफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते थे। कई सरकारें यह भी कहती हैं कि सब्सिडी पर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो शोध के लिए कहां से दें। हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पब्लिक सेक्टर के शोध से ही देश में मजबूती आती है। मैं तो यह भी कहूंगा कि किसान भाई के फायदे के लिए जो टेक्नोलॉजी है वह उसका प्रचार करें, राज्यों को भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और यह बहुत जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी महंगी भी होती जा रही है। हमें विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है।

आपने जीएम टेक्नोलॉजी का सवाल पूछा, यह संवेदनशील मुद्दा है लेकिन मैं इसका जवाब देने में हिचकिचाऊंगा नहीं क्योंकि यह देश और किसानों के भविष्य का मामला है। पहले तो मेरा यह मानना है कि जहां परंपरागत तकनीक से आपको सफलता मिलती है वहां हमें जीएम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जैसे गेहूं में, चावल में जो सफलता मिल रही है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मगर पूरा जोर लगाने के बाद भी अगर परंपरागत तकनीक से हमें कुछ नहीं मिलता है तब हमें मजबूरी में जीएम टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहिए। दूसरा, जो यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर सीड्स के जरिये टेक्नोलॉजी को बहुत महंगा कर देता है, तो जहां पर जीएम का डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन करती है, जैसे बैंगन को डेवलप किया, सरसों को डेवलप किया, हमें वैसा करना चाहिए। तीसरा हमारे देश में जीएम टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है। यहां तक कि जीईएसी में भी कोई कृषि वैज्ञानिक ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिक को नीति निर्धारण में रखना जरूरी है। हम केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, जीएम टेक्नोलॉजी तो कई तरह के केमिकल का सब्सटीट्यूट हैं जिसमें आपको केमिकल से मुक्ति मिलती है, तो इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए। और चौथा, हम टेक्नोलॉजी को कहीं बहुत ज्यादा इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी की अनदेखी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें खाद्य

तेलों के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इन सब बातों को देखते हुए देश को इसे पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए। कहीं और हमें सफलता नहीं मिलती है तो खाद्य तेल में इसको जरूर मौका देना चाहिए।

प्र *पर्यावरण में बदलाव की बढ़ती घटनाओं से कृषि पर बड़ा असर पड़ रहा है। हाल ही संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन (एफएओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन दशकों में कृषि और सहयोगी क्षेत्र के उत्पादन को क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदा और प्रतिकूल मौसम से 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इससे हम कैसे निपट पाएंगे? कृषि उत्पादन और किसानों की आय को इससे कैसे सुरक्षित रख पाएंगे?*

यह प्लानेट और लोगों के सर्वाइवल का मुद्दा है, किसानों की आमदनी का मुद्दा नहीं है। पर्यावरण संबंधी एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसमें अलग-अलग मिशन हैं। वाटर मिशन भी है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित भी होता है और क्लाइमेट को प्रभावित भी करता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे नकारात्मक असर एग्री फूड सेक्टर पर होने वाला है।

दूसरा एक मुद्दा है जिसे पूरी तरह इग्नोर किया गया है। मैंने भी एफएओ के जरिये दुनिया के 14 देशों के महत्वपूर्ण लोगों को इसी बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। मैंने एफएओ से भी इस मुद्दे को आगे लाने के लिए कहा कि किसान अब यह तो समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से कृषि पर क्या असर हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर जागृत नहीं हैं कि कृषि का भी क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव पड़ता है। हम इसे केवल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते कि वे अपना उत्सर्जन कम करें। भारत में क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर की भूमिका 17 फीसदी है। एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसी तरह कृषि में उत्सर्जन कम करने पर बात करनी पड़ेगी। अभी यह फैसला हुआ है कि डेढ़ डिग्री तापमान वृद्धि पर हमें रोक लगानी है। अभी तक हमें इसका नुकसान इसीलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि विज्ञान क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में कामयाब हुआ है। मगर उसकी एक सीमा है और हम ऊपरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम उस सीमा पर पहुंच जाएंगे तब कोई भी साइंस उसको काउंटर करने में सक्षम नहीं होगा। हमें क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर को बचाना है, और पर्यावरण को बचाने के लिए एग्रीकल्चर का योगदान भी बाकी सेक्टर की तरह कम करना है।

प्र *फसलों से अधिक उत्पादन वृद्धि डेयरी, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर में आ रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कृषि विविधीकरण के जरिये किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है?*

निश्चित तौर पर, अगर आप आमदनी को देखें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में रिस्क जरूर है लेकिन नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तुलना में इसमें 4 से 5 गुना ज्यादा आमदनी है। आज सबसे ज्यादा उत्पादकता और सबसे ज्यादा ग्रोथ उन राज्यों में आ रही है जो विविधीकरण की ओर जा रहे हैं। हरित क्रांति की वजह से उत्पादकता में आगे रहने वाले हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य अब टॉप पर नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आगे निकल रहे हैं। जहां विविधीकरण हुआ या हो रहा है वहीं तेजी से ग्रोथ हो रही है, वहीं पर ज्यादा उत्पादकता मिल रही है। हमें एमएसपी पर निर्भर किसानों को नए रास्ते देने होंगे। मेरे जिस पेपर का आपने जिक्र किया था, उसमें मैंने इससे संबंधित एक ग्राफ दिया है। एग्रीकल्चर के जिस सेगमेंट में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप है, चाहे एमएसपी से या सब्सिडी से, उसकी ग्रोथ उतनी कम है। उसकी वजह यही है कि विविधीकरण मांग पर निर्भर है और जो मांग पर निर्भर होता है उसकी कीमत देने की शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सब्जियों, फल, अंडे, पोल्ट्री, दूध और मछली में मांग के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। अनाजों की मांग बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। विविधीकरण ग्रोथ और किसानों की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा कारक है।

प्र *आपका आकलन है कि आने वाले दशकों में भारत को अपने अतिरिक्त उत्पादन के 25 फीसदी तक के लिए निर्यात बाजार तलाशने होंगे। क्या इस तरह की किसी रणनीति पर काम हो रहा है? विश्व व्यापार संगठन और क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे व्यापार समझौतों में इसकी कितनी गुंजाइश है?*

> **"हरित क्रांति की वजह से उत्पादकता में आगे रहने वाले हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य अब टॉप पर नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आगे निकल रहे हैं।"**

हमें अगले 10 साल में कितने फीसदी विदेशी मार्केट की तलाश करनी पड़ेगी, वह इस उम्मीद पर है कि हमारा कृषि क्षेत्र 3 से 3.5 फीसदी ग्रोथ करेगा। इंडस्ट्री डिमांड दो-सवा दो फीसदी हो रही है, तो हमारा सरप्लस बढ़ता जाएगा। आज स्थिति सामान्य नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं। आज तो आपका कुछ भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन दो-तीन साल बाद कीमतें नीचे आ जाएंगी क्योंकि कीमतों का एक चक्र होता है। गेहूं की कीमत नीचे आ जाएगी। हमें कृषि क्षेत्र को उस स्थिति में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए तैयार करना है। उसके लिए मैंने सुझाव भी दिए हैं कि दो तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है। एक है सप्लाई चेन और दूसरा प्रोडक्शन। हमें उनको लेकर चलना है, वरना प्राइस क्रैश के चांस बन जाते हैं। हमें कृषि में एफिशिएंसी लाकर कुछ हिस्सों को निर्यातोन्मुखी बनाना होगा। उसमें बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। आपने ओएनडीसी प्लेटफार्म यानी ओपन नेटवर्क व डिजिटल कॉमर्स के बारे में सुना होगा। उसके जरिये अगर उपज बेचेंगे तो लागत में बचत होती है। दूसरा जरिया है एफपीओ का जिसको हम ओएनडीसी के साथ लिंक कर रहे हैं। इस तरह के कुछ इन्नोवेटिव विचार हैं मार्केटिंग में। हमें सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, मार्केटिंग में भी लागत कम करनी है। हमें उत्पादन के साथ सप्लाई चेन में भी एफिशिएंसी लानी होगी। हमें ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग दोनों को प्रतिस्पर्धी बनाकर आगे बढ़ाना है। यही हमारी कृषि का भविष्य है।

प्र *अब भी भारत की कामकाजी आबादी का 45.8 फीसदी खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों से ही आजीविका कमा रहा है। गैर कृषि क्षेत्र वालों और इनकी आय का अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई बढ़ रही है, उसे कैसे कम किया जाए?*

हमारी जोतों का आकार छोटा है। छोटे किसान बड़े किसानों की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं। कहा जाता है कि जो छोटा है वह खूबसूरत है, लेकिन यहां जो छोटा है वह मजबूत नहीं है। उनके लिए आय के वैकल्पिक स्रोत जरूरी हैं। ऐसे पार्ट टाइम किसान हैं जिनकी आधी से ज्यादा आमदनी गैर-कृषि स्रोतों से आती है, जैसे छोटा-मोटा रोजगार। बहुत से ऐसे किसान हैं जो कृषि छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे भी हैं जो लीज पर जमीन लेकर अपनी जोत बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के सभी

बीते 10 साल में हमारी ग्रोथ रेट विश्व औसत के डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। चीन और अमेरिका से हमारी ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए पैदावार का अंतर कम होना शुरू हो गया है।

मैकेनिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें संगठित करें, उनका स्केल बढ़ाएं। खेती में हार्वेस्टिंग के बाद वैल्यू एडिशन की संभावना बढ़ाएं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमें पार्ट टाइम फार्मर का ही मॉडल अपनाना पड़ेगा और उन्हें गैर कृषि क्षेत्र से आधी से ज्यादा आमदनी दिलाने के अवसर पैदा करने होंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कृषि का जो मॉडल विकसित देशों ने अपनाया था उसे हम नहीं अपना सकते, हमें अपना अलग मॉडल बनाना पड़ेगा।

प्र *भारत में फसलों की उत्पादकता का औसत अमेरिका जैसे विकसित देश और चीन जैसे विकासशील देश के मुकाबले कई फसलों में आधा है। इसकी वजह कृषि शोध की कमी है या किसानों के पास संसाधनों व जरूरी कौशल न होना इसकी वजह है?*

इसमें बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन सकारात्मक फैक्टर यह है कि पैदावार का अंतर कम हो रहा है। पिछले 10 साल में भारत का कृषि विकास चीन से ज्यादा है। यह पहली बार हुआ है। बीते 10 साल में हमारी ग्रोथ रेट विश्व औसत के डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। चीन और अमेरिका से हमारी ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए पैदावार का अंतर कम होना शुरू हो गया है। चीन में ऊंची पैदावार के दो कारण हैं। एक तो वहां फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, हमारे देश से दो-गुना तीन-गुना ज्यादा। दूसरा, चीन के लोग फसलों की देखभाल ज्यादा करते हैं, तो उसका भी असर उत्पादकता पर है। हम मोनोक्रॉपिंग के खिलाफ बातें करते हैं, वहां काफी मजबूत मोनोक्रॉपिंग होती है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन अब हम इसे लेकर काफी सतर्क हैं। बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है और देश में भी विकसित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम सब में कमतर हैं, कुछ फसलों में विश्व औसत से बेहतर उत्पादकता है। यदि हमारी पैदावार का स्तर कम है तो हमारे पास चीन और अमेरिका की तुलना में ग्रोथ के अवसर बहुत ज्यादा हैं, जबकि उनके लिए ग्रोथ के मौके सीमित होते जा रहे हैं।

प्र *कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज पर सरकार सब्सिडी देती है लेकिन अलग-अलग राज्यों में करीब 15 से 30 फीसदी खेती करने वाले बटाईदारों को इसका फायदा नहीं मिलता है। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट या दूसरे सुधारों को लागू किया जाना क्या अब समय की जरूरत है?*

देश के अलग-अलग इलाकों में अलग स्थिति है। यदि आप बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों को देखेंगे तो वहां अब भी इंस्टीट्यूशनल कर्ज कम है। हमें उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। वह कर्ज इधर-उधर खर्च हो रहा है। वहां हमें अलग नीति की जरूरत है। जैसा कि किसान नेता कहते हैं, किसानों को गिरवी रखने में बैंकों का भी रोल है, वह उनको बहुत ज्यादा कर्ज देते हैं। इसमें बदलाव आ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं, अब तो पशु किसान कार्ड भी बना रहे हैं, मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। किसानों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसा लोन लें जिसको वापस करने में सहूलियत बनी रहे। कई इलाकों में एग्रीकल्चर क्रेडिट का एक मैकेनिज्म बन गया है। साल पूरा होने पर आपने पैसा वापस किया और अदल-बदल करके फिर ले लिया। मैं कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्रेडिट का रोल डायवर्सिफिकेशन लाने में होना चाहिए।

आपने लैंड लीज एग्रीमेंट का जो सवाल उठाया, तो उन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए लोन के लिए उनकी पात्रता नहीं है। बहुत पहले नीति आयोग ने एक लैंड लीज मॉडल दिया था जिसको कुछ राज्यों ने सीमित रूप में अपनाया लेकिन इसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत है। देश में परती भूमि बढ़ती जा रही है। किसानों के बेटे अब गैर कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। कुछ परिवारों में अगर एक ही बेटा है तो वहां कोई खेती करने वाला नहीं है। उनकी जमीन खाली पड़ी है। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट लागू करने पर राज्यों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से छोटे किसान जमीन बटाई पर लेकर गुजारा करने की बेहतर स्थिति में होंगे। अभी जिनको साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है उनको भी सब्सिडी वाला कर्ज मिल सकेगा। लैंड लीज मॉडल अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जमींदार और बटाईदार दोनों की सुरक्षा हो सकेगी।

प्र *किसान कर्ज माफी कितना जरूरी है और इसका मकसद सही है या नहीं?*

यदि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उस स्थिति में मैं कहूंगा कि इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर उस तरह की कोई बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो कर्ज माफी से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे ख्याल से सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। Rw

कृषि शिक्षा को 21वीं सदी के युवाओं के लिए तैयार करना

डॉ. आर एस परोदा

लेखक ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज- TAAS के चेयरमैन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग- DARE के पूर्व सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व महानिदेशक हैं।

भारत 1.41 अरब लोगों के साथ चीन (1.45 अरब) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या संभावनाओं के 2022 के संस्करण के अनुसार, 2050 तक इसके जल्द ही चीन से आगे निकलने और 1.668 अरब के अनुमानित आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 'भारत में युवा 2022' पर अपनी हाल ही में जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2021 में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की आबादी 27.2 प्रतिशत थी जिसके 2036 तक घटकर 22.7 हो जाने की उम्मीद है। बहरहाल, आज भारत में 10-24 वर्ष के आयु की 35.6 करोड़ की सबसे बड़ी वैश्विक युवा आबादी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 20 करोड़ युवाओं का बड़ा अनुपात है। इसके अलावा, भारत के युवाओं के बीच साक्षरता की समग्र दर में वृद्धि हुई है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत पढ़ने या लिखने में सक्षम हैं। सोशल मीडिया की व्यापकता और इंटरनेट की पहुंच के साथ बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से समझदार युवा आबादी है जो ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच रखते हैं जिससे सीखने और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार, देश को 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का लाभ मिलता है। जब युवाओं का यह विशाल संसाधन कार्यबल में प्रवेश करता है, तो इससे जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप अधिक आर्थिक विकास हो सकता है, मुख्य रूप से तब जब कामकाजी आयु की आबादी आश्रितों की संख्या से बड़ी होती है। ये युवा नवाचार, उद्यमशीलता और विविधता की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र में शामिल करने की अधिक आवश्यकता है, जो देश की जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देता है।

कोविड-19 संकट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आर्थिक गतिविधियों के सबसे गंभीर लॉकडाउन के तहत भी कृषि को बिना किसी रुकावट के उत्पादन जारी रखने की आवश्यकता है। महामारी के दौरान कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए और महामारी के कारण लगे झटकों से उबरने के लिए उन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। सामान्य रूप से शिक्षा और कृषि शिक्षा इस प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। केवल उच्च गुणवत्ता, समावेशी और न्यायसंगत प्रशिक्षण के साथ ही देश महामारी के झटके से उबरने में सफल होंगे, जिसने लाखों बच्चों, युवाओं और वयस्कों, विशेष रूप से निम्न आय समूहों को प्रभावित किया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि एक केंद्रीय गतिविधि है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र डिजिटलीकरण और अन्य तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए एक और गुणात्मक छलांग लगाएगा।

कृषि क्षेत्र से जुड़ने में युवा अनिच्छुक क्यों हैं?

पिछले कुछ वर्षों में घटती जोत (छोटी जोत) के कारण कृषक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें कुल कृषक परिवारों का 80 प्रतिशत से अधिक शामिल है। तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण, ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, अस्थिर बाजारों और बढ़ती जलवायु अस्थिरता से प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण कृषि से जुड़े कई जोखिम चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। अनुमान है कि वर्तमान में लगभग पांच प्रतिशत युवा ही कृषि से जुड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कृषि को रचनात्मक, लाभदायक और सम्मानजनक पेशा नहीं मानते हैं। युवा एक बड़े संसाधन हैं जिसका उपयोग कृषि विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए कृषि में युवाओं को बनाए रखने की चुनौतियों (बॉक्स-1) को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में एक बड़ी दुविधा कृषि की खराब सामाजिक छवि है जिसके कारण ग्रामीण युवा विकल्प और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अग्रणी संगठनों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों (उदाहरण के लिए आईटी क्षेत्र) के सफल व्यवसाय मॉडल के माध्यम से यह स्पष्ट है कि युवा अधिक नवीन और उत्पादक होने के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियों के प्रति ग्रहणशील भी हैं। इसके विपरीत, कृषि क्षेत्र में ऊर्जा (युवा) और अनुभव (बूढ़े लोगों) के बीच एक बड़ा अंतर है, जो खेती की पिछड़ी प्रकृति और नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों को धीमी गति से अपनाने का कारण है। खराब प्रौद्योगिकी प्रसार के कारण विज्ञान का समाज से नाता टूट गया है जिससे खेती गैर-लाभकारी होने के साथ-साथ गैर लचीली भी हो गई है। जब तक बौद्धिक रूप से संतोषजनक प्रौद्योगिकियां नहीं होंगी, युवाओं का कृषि की ओर आकर्षित होने की संभावना नहीं है।

वास्तव में, ग्रामीण युवाओं (पुरुष और महिला दोनों)

को सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), उच्च मूल्य वाली कृषि, प्रसंस्करण, मूल्य-संवर्धन, पैकेजिंग, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन, भंडारण आदि जैसे संभावित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह उन्हें विशिष्ट कृषि, उच्च तकनीक बागवानी, संरक्षित खेती, आईपीएम/जैव नियंत्रण, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सामुदायिक नर्सरी, बीज उत्पादन, किसानों को बाजारों से जोड़ना आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाएगा। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम युवा निश्चित रूप से उच्च स्तर के आत्मविश्वास के साथ कृषि को अपनाएंगे। उपरोक्त परिदृश्य में युवा कृषि को एक लाभकारी और सम्मानजनक पेशा नहीं मानते हैं। साथ ही इसे भोजन, पोषण और आजीविका सुरक्षा को पूरा करने के लिए एक स्थायी मार्ग नहीं माना जाता है। इससे यह अच्छी तरह से समझ में आता है कि आज के युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) की मानसिकता और दृष्टिकोण अलग हैं। वे बौद्धिक रूप से संतोषजनक, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से सशक्त गतिविधियों को अपनाना पसंद करते हैं।

दुर्भाग्य से भारत जैसे विकासशील देश में 'आकांक्षा-प्राप्ति का अंतर' मौजूद है। इसलिए उनकी आकांक्षाओं की प्राथमिकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए युवाओं को देश के समग्र कृषि और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के प्रति उन्नत कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से नवाचार, क्षमता विकास, साझेदारी और भागीदारी दृष्टिकोण में प्रगति के माध्यम से प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए मानसिकता में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता होगी, आजीविका के साधन के रूप में पारंपरिक कृषि से व्यवसाय-उन्मुख और ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल युवाओं को विशेष कृषि की ओर शामिल करने वाली मानसिकता अपनानी होगी। नए नवाचारों और उद्यमशीलता के माध्यम से वर्तमान कृषि व्यवसाय परिदृश्य को आकर्षक और लाभकारी बनाना होगा। गुणवत्तापूर्ण/कुशल युवाओं को खेती में तभी आकर्षित किया जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है जब यह बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे और बेहतर शैक्षिक और संबंधित सुविधाओं से जुड़ा हो। इससे भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए व्यापक रणनीतियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसरों और सुविधाओं के साथ सभी कृषि-आधारित और कृषि-संबंधित गतिविधियों में अधिक फायदेमंद नौकरियों की मांग होगी, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बेहतर विकल्प और कृषि-खाद्य और मूल्य-श्रृंखला प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए छोटी कृषि-फर्मों और उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विस्तार प्रणाली को एक नवाचार विस्तार मंच में बदलने की तत्काल आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी-उन्मुख ज्ञान, इनपुट और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है। विस्तार दृष्टिकोण को व्यक्तिगत कृषि घरेलू दृष्टिकोण की बजाय कृषक समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसा कि अतीत में हुआ था। ये सभी किसी भी राष्ट्र के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसलिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा नीति और संस्थागत समर्थन के माध्यम से एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता होगी।

कृषि में युवाओं को बनाए रखने की चुनौतियां

- **ज्ञान, सूचना और शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच**
- **भूमि तक सीमित पहुंच**
- **वित्तीय सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच**
- **नौकरी को लेकर औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण का अभाव**
- **बाजारों तक सीमित पहुंच**
- **निर्णय लेने और नीतिगत संवादों में सीमित भागीदारी**

बॉक्स - 1

भारत में कृषि शिक्षा की प्रमुख चिंताएँ

भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा और विस्तार प्रणाली (एनएआरईईएस) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वाधान में 4 डीम्ड-विश्वविद्यालयों, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), 93 आईसीएआर संस्थान और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के साथ सबसे बड़ी कृषि शिक्षा प्रणालियों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में आईसीएआर ने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बॉक्स 2 में दर्शाई गई कृषि शिक्षा की चिंताओं के अलावा, वर्तमान प्रणाली में दो अन्य प्रणालीगत कमजोरियां हैं: (1) शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों से अभिन्न रूप से जुड़े नहीं हैं और (2) कृषि-स्नातकों और कृषक समुदाय के बीच एक अलगाव है जो पूर्व और बाद वालों को आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में राज्य कृषि विश्विद्यालयों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और 'स्थान-विशिष्ट क्षेत्रीय अनुसंधान' पर अधिक जोर देने के कारण ज्ञान सृजन हमेशा पीछे रहा है। इसके अलावा, छात्र अपने करियर की शुरुआत से ही कार्यकारी पदों की आकांक्षा रखते हैं जिससे कृषि क्षेत्र के निचले स्तरों पर कुशल संचालन की कमी पैदा हो जाती है।

कृषि-शिक्षा प्रणाली को बदलना

आकांक्षाओं और जीवनशैली में बदलाव को ध्यान में रखते हुए युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रेरित और आकर्षित करने के लिए कृषि-शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाने की आवश्यकता है। युवाओं को कृषि में तभी बनाए रखा जा सकता है जब आवश्यक ज्ञान और शिक्षा, तकनीकी कौशल, निरंतर प्रोत्साहन और सक्षम नीति का वातावरण प्रदान किया जाए। इसके अलावा, युवा प्रतिभाओं

युवाओं को कृषि में तभी बनाए रखा जा सकता है जब आवश्यक ज्ञान और शिक्षा, तकनीकी कौशल, निरंतर प्रोत्साहन और सक्षम नीति का वातावरण प्रदान किया जाए।

भारत में कृषि शिक्षा की प्रमुख चिंताएँ

- **इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, अकाउंटेंसी आदि की तुलना में स्नातक पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा में प्रवेश अधिकांश छात्रों की पहली प्राथमिकता नहीं है।**
- **कृषि शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बहुत कम है, देश में कुल पात्र जनसंख्या में से कृषि शिक्षा के लिए जीईआर केवल 0.03% है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए यह 26% है।**
- **कृषि शिक्षा राज्य का विषय है जिसके कारण फंडिंग, संकाय भर्ती और वेतन, बुनियादी ढांचे और संकाय/छात्र विकास कार्यक्रमों के मामले में विविधताएं आई हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय भी अपर्याप्त है।**
- **कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अपर्याप्त निवेश और घटते वित्तीय संसाधन।**
- **कृषि में छात्रों का ठहराव कम है (केवल 30% स्नातक ही इस क्षेत्र में बने रहते हैं)।**
- **संसाधनों और मानदंडों के अनुरूप बिना नए संस्थान खोलना, विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा जो कृषि में डिग्री दे रहे हैं, जिनमें से कुछ में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी है और वे बहुत अधिक ट्यूशन फीस और अन्य फीस वसूलते हैं।**
- **कृषि शिक्षा, रोजगार और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संबंध विच्छेद।**
- **पर्याप्त कौशल, उद्यमिता और अनुभवात्मक शिक्षा का अभाव, कृषि स्नातकों की कुल मिलाकर खराब रोजगार क्षमता।**
- **अपर्याप्त शैक्षणिक कठोरता और उभरती चुनौतियों का संदर्भीकरण और अवसर।**

अवसर

- **कृषि पाठ्यक्रमों से बुनियादी विज्ञान का क्षरण।**
- **शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के बीच बढ़ते अलगाव के परिणामस्वरूप ज्ञान की कमी हो रही है।**
- **मूल्यांकन, निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन, जवाबदेही और प्रोत्साहन प्रणालियों की खराब प्रणाली।**
- **सीमित डिजिटलीकरण और अकुशल शासन।**

बॉक्स - 2

को आधुनिक खेती करने के लिए आकर्षित करने की आवश्यक नीतियां, प्रोत्साहन और पुरस्कार देने की आवश्यकता है जो न केवल लाभदायक और टिकाऊ हो बल्कि सम्मानजनक भी हो। यह युवाओं को अपने सुखी जीवन के लिए कृषि को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ आकर्षित भी करेगा। कृषि में युवाओं के नेतृत्व वाले समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा दृष्टिकोण स्थानीय, राज्य और देश स्तर पर एक रणनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार, नई रणनीति वर्तमान कृषि को फसल आधारित से 'हल-टू-प्लेट' दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कृषि प्रणाली पर आधारित करने की होनी चाहिए, जो अधिक प्रासंगिक, कुशल, मांग-संचालित, उत्पादक, प्रतिस्पर्धी और लाभदायक है। इसे सभी के लिए भोजन, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

कृषि में युवाओं के नेतृत्व वाले समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा दृष्टिकोण स्थानीय, राज्य और देश स्तर पर एक रणनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए।

आईसीएआर ने हाल के दिनों में सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से भारतीय कृषि शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उच्च कृषि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को मान्यता प्रणाली, उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों के निर्धारण, शैक्षणिक नियमों, कार्मिक नीतियों, पाठ्यक्रम और वितरण प्रणालियों की समीक्षा, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए समर्थन, संकाय क्षमता और अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से छात्रों के प्रवेश में सुधार किया गया है। आईसीएआर की पांचवीं डीन समिति की रिपोर्ट ने प्रासंगिक व्यावहारिक कौशल, उद्यमशीलता योग्यता, स्व-रोजगार, नेतृत्व गुणों और स्नातकों के बीच आत्मविश्वास और कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया। इसने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए मानदंड भी सुझाए। क्षेत्रीय विशिष्टताओं का उपयोग करने और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तटीय कृषि, पहाड़ी कृषि, जनजातीय कृषि आदि जैसे कुछ वैकल्पिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे। जीनोमिक्स (जैव प्रौद्योगिकी), नैनो टेक्नोलॉजी, जीआईएस, सटीक खेती, संरक्षित खेती, माध्यमिक खेती, हाई-टेक खेती, विशेष कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े डेटा एनालिटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, कृषि में प्लास्टिक जैसे उभरते क्षेत्रों में नए डिग्री कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सिफारिश की गई।

साथ ही, शुष्क भूमि में बागवानी, कृषि-मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट निपटान और प्रदूषण उपशमन, खाद्य संयंत्र नियम और लाइसेंसिंग, खाद्य गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और प्रमाणन, खाद्य भंडारण इंजीनियरिंग, खाद्य संयंत्र स्वच्छता और पर्यावरण नियंत्रण, उभरती खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां, रेशम उत्पादन, सामुदायिक विज्ञान और खाद्य पोषण और आहार विज्ञान जैसे क्षेत्रों के लिए भी पाठ्यक्रमों की सिफारिश की गई। 2015 में शुरू किए गए स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के अनुपालन में समिति ने सभी यूजी विषयों में एक साल का कार्यक्रम डिजाइन किया है जिसमें (1) जहां भी संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवात्मक शिक्षण सहित अनुभवात्मक शिक्षण, (2) ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव, (3) इन-प्लांट ट्रेनिंग/इंडस्ट्रियल अटैचमैंट (4) व्यावहारिक प्रशिक्षण (एचओटी)/कौशल विकास प्रशिक्षण, (5) छात्र परियोजनाएँ और (6) एग्रीकल्चरल साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च एक्सीलेंस (एस्पायर) कार्यक्रम शामिल हैं। विश्व बैंक समर्थित मौजूदा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी), जो पूर्ववर्ती विश्व बैंक परियोजनाओं, विशेष रूप से एनएटीपी और एनएआईपी पर बनाई गई है, फैकल्टी और छात्रों की क्षमताओं को मजबूत कर रही है, वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ

राष्ट्रीय प्रणाली के लिंकेज के संबंधों को बढ़ावा दे रही है, अंतरराष्ट्रीय अनुभवात्मक सीखने, शिक्षण-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने और निजी उद्योगों के साथ कृषि को मजबूत करने की सुविधा प्रदान कर रही है। उपरोक्त पहलों के बावजूद तकनीकी और नीतिगत पहलुओं पर अधिक ध्यान देकर कृषि में युवाओं को प्रेरित करने और आकर्षित करने के लिए कृषि शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी और सुधार की अच्छी गुंजाइश है।

तकनीकी पहलू

- जैसा कि एनईपी 2020 में कहा गया है, कृषि शिक्षा को ऐसे मानकों को बनाए रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के कृषि स्नातक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पेशेवर रूप से सुसज्जित हैं।
- एनएआरईईएस को पाठ्यक्रम और कौशल विकास में आवश्यक समायोजन करने के लिए तेजी से परिवर्तनशील, ज्ञान-गहन कृषि की जनशक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के संपर्क पर जोर देना चाहिए।
- आईसीटी, डिजिटलीकरण, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रो प्रोसेसिंग, सटीक कृषि और सिस्टम सिमुलेशन के विषयों में अधिक तकनीकी हस्तक्षेप की संभावना है, इसलिए संबंधित कार्यबल की मांग और शिक्षाशास्त्र में बदलाव को उसी के मुताबिक शामिल किया जाना चाहिए।
- स्थानीय विस्तार को सूक्ष्म स्तर पर चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाने, फीडबैक तंत्र को मजबूत करने और सही प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए व्यवसाय/विपणन/आय पर ध्यान केंद्रित करने वाले बहुलवादी दृष्टिकोण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता है।
- उद्यमिता और एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बाजार के नेतृत्व वाली विस्तार नीतियों को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग को शैक्षिक कार्यक्रमों में विधिवत शामिल किया जाना चाहिए।

नीतिगत पहलू

- मंत्रालय एक नियामकीय प्राधिकरण के रूप में 'भारतीय कृषि शिक्षा परिषद (एईसीआई)' की स्थापना पर विचार कर सकता है, जिसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) के समान काम करना चाहिए।
- चूंकि उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए प्रस्तावित सुधारों में एकरूपता लाने के लिए कृषि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए।
- निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्वायत्तता के साथ आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए।
- कृषि स्नातकों में रोजगार योग्य कौशल विकसित करने पर फोकस किया जाना चाहिए जिनकी आज के प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिदृश्य में नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षा की जाती है, कृषि प्रौद्योगिकियों में अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निवेश करें।

शैक्षिक सुधारों में अब युवाओं को 'नौकरी मांगने वाले' की बजाय 'नौकरी निर्माता' बनने के लिए सशक्त बनाने को कौशल उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स को गैर-औपचारिक डिग्री कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। इससे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रासंगिक और दूरदर्शी उन्मुख बनाने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

कृषि शिक्षा क्षेत्र में अन्य विषयों की तरह युवाओं के साथ एक प्रशिक्षित मानव पूंजी की आवश्यकता होती है जो (1) सामाजिक चेतना रखते हैं और ग्रामीण समुदायों से जुड़े और प्रतिबद्ध हों, (2) मजबूत उद्यमशीलता कौशल और भावना रखते हैं और नई नौकरी के अवसर शुरू करने में सक्षम हैं, (3) सकारात्मक मूल्यों और उच्च नैतिक मानकों द्वारा निर्देशित होते हैं, (4) टिकाऊ कृषि उत्पादन की दिशा में एक नई दृष्टि के लिए प्रतिबद्ध हैं, (5) वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों में एक ठोस आधार है जो विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुभव का आधार है, (6) सामान्य तैयारी करें जो उन्हें अपने करियर में आने वाली समस्याओं का समग्र समाधान विकसित करने में सक्षम बनाएगी, (7) रचनात्मक होने और वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के आत्मविश्वास वाले नवप्रवर्तक हैं, (8) मजबूत नेतृत्व, पारस्परिक और टीम निर्माण के अधिकारी हैं, कौशल और मजबूत संचार कौशल प्रदर्शित करें जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार भाषाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग शामिल है, (9) रोजगार और धन पैदा करने के लिए 'व्यावसायिक कौशल' रखें और विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के साथ काम करने में सक्षम हों। 'नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वालों' में बदलने के लिए युवाओं पर केंद्रित हमारे दृष्टिकोण और नीति में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। अनौपचारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं का क्षमता विकास और माध्यमिक और विशिष्ट कृषि सहित कृषि में नए अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने से युवाओं को कृषि में आकर्षित किया जा सकेगा, ग्रामीण और शहरी के बीच अंतर को पाटने में मदद मिलेगी और तेजी से राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अंत में, सक्षम वातावरण, संस्थागत समर्थन और आवश्यक सहयोग के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने से वे न केवल कृषि की ओर आकर्षित होंगे बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा लक्षित पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में से कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए कृषि क्षेत्र का त्वरित विकास सुनिश्चित होगा। Rw

'नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वालों' में बदलने के लिए युवाओं पर केंद्रित हमारे दृष्टिकोण और नीति में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है।

हरित क्रांति के जनक डॉ. स्वामीनाथन का निधन

देश में हरित क्रांति के जनक और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों में शुमार डॉ. एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की उम्र में 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया। 7 अगस्त, 1925 को कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन था। देश की खाद्य आत्मनिर्भरता में उनका सबसे बड़ा योगदान है। सी2 लागत पर 50% मुनाफा देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की उनकी सिफारिश ने उन्हें किसानों के घर-घर तक पहुंचा दिया।

सर्जन पिता एम.के. संबासिवन और मां पार्वती थंगम्मल के घर जन्मे स्वामीनाथन की स्कूली शिक्षा कुंभकोणम में ही हुई। कृषि विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके पिता की भागीदारी और महात्मा गांधी के प्रभाव ने उन्हें इस विषय में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा "आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक" के रूप में भी जाना जाता था। भारत में ज्यादा उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। उन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के 40 से भी ज्यादा पुरस्कार मिले।

गेहूं का एमएसपी 150 रुपये क्विंटल बढ़ा

केंद्र सरकार ने मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले नौ साल में गेहूं के एमएसपी में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का एमएसपी मार्केटिंग ईयर 2023-24 के 2125 रुपये से बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही 5 अन्य रबी फसलों का भी एमएसपी बढ़ाया गया है।

रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों एवं रैपसीड के एमएसपी में 200 रुपये की वृद्धि की गई है। इसे 5450 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं, मसूर के एमएसपी को 425 रुपये बढ़ाकर 6425 रुपये प्रति क्विंटल और चना का 105 रुपये बढ़ाकर 5440 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। जौ के एमएसपी में 115 रुपये और कुसुम में 150 रुपये की वृद्धि की गई है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए जौ का समर्थन मूल्य 1850 रुपये और कुसुम का 5800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

बौने पौधे वाले मक्का की खेती को मंजूरी

अमेरिका के बायोटेक रेगुलेटर (वहां के कृषि विभाग) ने एक नए तरह के मक्का के किस्म की कॉमर्शियल खेती को मंजूरी दी है जिसमें ऐसे ट्रांस जीन का इस्तेमाल किया है जिससे मक्का के पौधों की लंबाई कम हो जाती है। यह किस्म जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में रहे ज्यादा उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम है।

मक्का का पारंपरिक पौधा 9-12 फुट का होता है, लेकिन इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 7 फुट से कम है। यह सेमी-ड्वार्फ मक्का जेनेटिक बदलाव की टेक्नोलॉजी का सफल उदाहरण है। इससे उन फसलों में जीन ट्रांसफर और जीनोम एडिटिंग की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जो हरित क्रांति के दौरान अछूते रह गए थे।

जगपति राव "इंटरनेशनल एग पर्सन ऑफ द ईयर"

श्रीनिवास फार्म्स ग्रुप के अध्यक्ष और भारत में राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (एनईसीसी) के संस्थापकों में से एक, चित्तूरी जगपति राव को अंतरराष्ट्रीय अंडा आयोग (आईईसी) द्वारा प्रतिष्ठित "इंटरनेशनल एग पर्सन ऑफ द ईयर 2023" से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले एशियाई हैं। आईईसी ने हाल ही में आईईसी ग्लोबल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस लेक लुईस 2023 में वैश्विक अंडा उद्योग में उनकी उल्लेखनीय सफलता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जगपति राव को पुरस्कार प्रदान किया। जगपति राव ने भारतीय पॉल्ट्री क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न केवल अपना खुद का श्रीनिवास फार्म्स ग्रुप बनाया, बल्कि उन्होंने उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने और भारत में पॉल्ट्री उत्पादों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तूरी भारत में एनईसीसी के संस्थापकों में से एक रहे हैं जो अंडा उत्पादकों का एक संघ है। एनईसीसी ने अंडा उद्योग को तेजी से बढ़ने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.

Sahakar Se Samriddhi

In 1960, NFCSF sowed the seed of revolutionising the cooperative sugar sector in India. Today NFCSF works collaboratively with the Ministry of Cooperation, Government of India to strengthen the cooperative-based economic development model, thereby accelerating the welfare of villages and farmers of the country and making cooperative sugar sector self-reliant.

The National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited (NFCSF) is the largest Co-operative Apex sugar body in the world. The Federation has played a decisive role in establishing a nationwide network, building a strong and vibrant Cooperative sugar sector across India. 259 Cooperative Sugar Factories and 09 State Cooperative Sugar Federations across the country are its members. It represents over five crore farmers and their dependents who are involved in sugarcane cultivation.

Techno-Commercial Services Offered By NFCSF

- Sugar Cane Development
- Sugar Cane Engineering & Processing
- Distillery / Ethanol Plants
- Co-generation & Green Hydrogen
- Commercial Operations
- Financial Management & Legal Services
- Detailed Project Reports (DPR)
- Preparation of Tender Documents
- Project Management Consultancy (PMC) Services

Prakash Naiknavare
Managing Director

Ketanbhai Patel
Vice-President

Jaiprakash Dandegaonkar
President

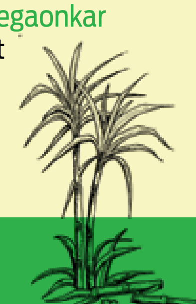

& Board of Directors

National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.
New Delhi; www.coopsugar.org

IPL
The Hallmark of Sustainability and Agro Prosperity

IPL

We Are Happy In Your Happiness

- National leader in fertilizer distribution with pan India dealer network.
- The single point-of-access for all agro nutrients in the country.
- IPL believes in empowering farmers by providing integrated solutions and educating them about sustainable farming practices.
- IPL has the philosophy of selfless service deeply entrenched in all its endeavours.
- Diversified into sugar production to support sugarcane farmers.
- Producers of vehicle grade Green Fuel (CBG) and nutrient rich Fermented Organic Manure.

Indian Potash Limited

IPL

Potash Bhawan,10-B, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi – 110 060
Phone: 011-25761540, 25763570, 25732438, 25725084
Fax: 011-25755313, E-mail: ipldel@potindia.com
Website: www.indianpotash.org

IPL Fertilizers - The First Choice of Wise Farmers